CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 20-06-2025 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAH10 User: dilip.lal Time: 06-19-2025 21:34 Color:

विचार
नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 20 जून 2025

अमेरिका दूर रहे

क्या ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका भी कूदेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप जब इस मुद्दे पर कहते हैं कि 'मैं ऐसा कर सकता हूं और नहीं भी कर सकता' - तो वह अनिश्चितता को और बढ़ा देते हैं। इस रवैये से तनाव घटाने में मदद नहीं मिलने वाली। अगर अमेरिका इस टकराव का हिस्सा बना, तो इसके नतीजे उसके साथ-साथ पूरे पश्चिम एशिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं।

आम लोग निशाना । इस्राइल और ईरान के बीच का संघर्ष केवल सैन्य या रणनीतिक लिहाज से अहम ठिकानों तक नहीं रहा है। अब इसकी जद में आम लोग आ रहे हैं। लेकिन, यूक्रेन युद्ध रुकवाने को आतुर ट्रंप का व्यवहार इस मामले में बिल्कुल अलग है। ईरान से बिना शर्त सरेंडर जैसी बात कहने से जाहिर है कि अमेरिका की दिलचस्पी शांति में नहीं है।

इराक युद्ध से सबक लें ट्रंप

जोखिम की वजह । ट्रंप सारे पत्ते अपने हाथ में रखना चाहते हैं। उनके कहने पर अमेरिकी सेना तैयार है। खबरें हैं कि ईरान ने भी पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए मिसाइलें तैनात कर दी हैं। यानी, अब एक ट्रिगर पॉइंट इस संघर्ष को भयावह युद्ध में बदल सकता है। ट्रंप इतना बड़ा रिस्क इसलिए लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है। हालांकि इस मामले में कोई निश्चित रिपोर्ट नहीं है।

पुरानी गलतियां । अमेरिका ने इस सदी की शुरुआत में भी ऐसी ही एक गलती की थी - इराक के खिलाफ युद्ध। जनसंहार के जिन हथियारों की खोज के नाम पर उसने इराक में तबाही फैलाई, वे कभी मिले ही नहीं और हजारों अमेरिकी सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। इराक आज भी अस्थिर है। वॉशिंगटन को ऐसा ही कड़वा घूंट अफगानिस्तान में भी पीना पड़ा। ईरान की स्थिति इन दोनों के मुकाबले मजबूत है।

कई मोर्चे खुल जाएंगे । अगर अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ, तो लड़ाई बस ईरान तक सीमित नहीं रहेगी। UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन समेत इस इलाके के कई देशों में अमेरिकी सेना तैनात है और ईरान उन्हें निशाना बनाने की कोशिश करेगा, जिससे ये मुल्क भी हिंसा की चपेट में आ जाएंगे। एक डर यह भी है कि ईरान के समर्थक हूती जैसे लड़ाके गुट भी अलग-अलग मोर्चा खोल सकते हैं।

आर्थिक तबाही । ईरान ने इस युद्ध में अभी तक ग्लोबल ऑयल सप्लाई को नहीं छुआ है। लेकिन, मौजूदा नेतृत्व के सामने अस्तित्व का संकट आया, तो वह पूरी ताकत से जवाब देगा, और नतीजा दुनिया के लिए आर्थिक तबाही भी लेकर आएगा। अमेरिका ने कई मौकों पर गलत अनुमान लगाए हैं - अपने अतीत से उसे इतना तो सबक लेना ही चाहिए।

रोज़-ब-रोज़

AC बिना चैन नहीं

शैलेंद्र पांडेय

लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्स के मुताबिक एशिया का पहला centrally air conditioned सिनेमा हॉल भारत में खुला था - मुंबई का रीगल थियेटर। साल 1933 में जो शुरुआत हुई, वह 2024 में रेकॉर्ड 1.4 करोड़ AC यूनिट की बिक्री तक जा पहुंची। इंटरनैशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) का अनुमान है कि 2050 तक हिंदुस्तान में AC की संख्या नौ गुना बढ़ जाएगी। लगातार बढ़ती गर्मी के कारण air conditioner देश की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक बन चुके हैं। 2024 में पूरे देश में कुल 536 हीटवेव डेज रेकॉर्ड किए गए थे। 2010 में यही औसत 177 दिनों का था। इसका मतलब कि भारत के विभिन्न इलाकों में डेढ़ दशक पहले लोगों को भीषण गर्मी के कुल जितने दिनों का सामना करना पड़ता था, आज वह संख्या तीन गुना है। इससे निपटने का फिलहाल एक ही रास्ता दिखता है - AC । हालांकि रेकॉर्ड बिक्री के बावजूद अब भी देश की केवल 10% आबादी के पास ही यह सुविधा है।

AC से जुड़ी दो चिंताएं हैं - पर्यावरण और बिजली। पिछले साल मई के आखिर में जब हीटवेव का कहर चरम पर था, तब बिजली की मांग 250 गीगावॉट को पार कर गई थी। अनुमान है कि इसमें से 20% ऊर्जा की खपत केवल AC में हुई। कमोबेश यही औसत पूरी दुनिया का है। ग्लोबली दो अरब से ज्यादा एयर कंडीशनर हैं और कुल बिजली जरूरतों का पांचवां हिस्सा इनमें ही जाता है। लेकिन, भारत की चिंता बड़ी है, क्योंकि कम AC यूनिट होने के बावजूद यहां बिजली उतनी ही खर्च हो रही है। इसी वजह से सरकार न्यूनतम और अधिकतम तापमान से जुड़ा नियम ला रही है। पर कुछ और भी कर सकते हैं - ज्यादा efficiency वाले AC लाए जाएं, कीमत घटाने के लिए टैक्स कम कर सकते हैं ताकि लोग 5 स्टार प्रॉडक्ट खरीदें। गर्मी का एक जवाब भारत के स्थापत्य में है। मोटी दीवारें, ऊंची छत और झरोखे - ऐसी इमारतों में भीतर की दीवार जल्दी गर्म नहीं होती और छत ऊंची होने की वजह से गर्म हवा ऊपर उठकर रोशनदान से बाहर निकल जाती है। इसी तरह, छत पर सफेद पेंट करके भीतर का तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जा सकता है।

एकदा

प्रवचन का अर्थ

गौतम बुद्ध जेतवन में प्रवचन दे रहे थे। सैकड़ों भिक्षुक, साधक और गृहस्थ श्रद्धालु उनके उपदेश सुन रहे थे। उपदेश खत्म करते हुए बुद्ध ने कहा, 'जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है।' सभा विसर्जित होने के बाद उनके प्रिय शिष्य आनंद ने पूछा, 'आपके इस उपदेश का क्या अर्थ है?' उत्तर दिए बिना बुद्ध ने कहा, 'चलो आनंद थोड़ा घूम-फिर आते हैं।' मुख्य द्वार पर उन्होंने सुना कि सभी प्रवचन की चर्चा कर रहे थे। एक स्त्री गौतम बुद्ध आई और कहा, 'तथागत, मैं नर्तकी हूं। आज नगर श्रेष्ठी के घर कार्यक्रम पहले से तय था, पर मैं भूल चुकी थी। आपने कहा, समय निकला जा रहा है, तो मुझे तुरंत इसकी याद आई।' एक व्यक्ति समीप आया और बोला, 'तथागत, मैं कोई बात नहीं छिपाऊंगा। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था, आपका उपदेश सुनकर मुझे अपनी योजना याद आ गई। धन्यवाद!' फिर एक वृद्ध ने कहा, 'तथागत, मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आज मेरी आंखें खुल गईं। अब मैं निर्वाण के लिए कोशिश करना चाहता हूं।' जब सभी चले गए, तो बुद्ध ने कहा, 'देखा आनंद! उपदेश एक ही था, पर उसका हर किसी ने अलग-अलग मतलब निकाला। जिसकी जितनी बड़ी झोली, वह उतना ही दान समेट पाता है। मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है।'

Subrata Dhar

संकलन : ललित गर्ग

इस्लामाबाद को ईरान से दूर करने की ट्रंप सरकार की रणनीति, मुनीर को इसीलिए मिल रहा भाव

पाकिस्तान पर क्यों मेहरबान अमेरिका

अवधेश कुमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कनाडा, साइप्रस और क्रोएशिया का दौरा कई स्तरों पर बेहद महत्वपूर्ण व सफल माना जाएगा। विदेश नीति, रक्षा और आंतरिक सुरक्षा से लेकर नैरेटिव के निर्माण तक, हर मोर्चे पर यात्रा सफल रही। किसने कल्पना की थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में 'ऑपरेशन सिंदूर' और भारत-पाकिस्तान टकराव रुकवाने को लेकर अमेरिकी दावे का ऐसा खंडन किया जाएगा।

दावे का सच । हालांकि मध्यस्थता का श्रेय लेने से ट्रंप पीछे नहीं हटेंगे और इस बातचीत के बाद भी उन्होंने वही पुराना दावा दोहराया। लेकिन, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मोदी और ट्रंप के बीच टेलीफोन पर हुई 35 मिनट लंबी बातचीत का जो ब्योरा दिया, उसका अमेरिकी सरकार ने खंडन नहीं किया। जरा सोचिए - दो नेताओं के बीच बातचीत में अगर सामने वाले को कहा जाए कि आपने जो दावा किया, वैसी हमारी कभी बात ही नहीं हुई, तो उस पर क्या गुजरेगी।

ट्रंप को अंदेशा । पीएम मोदी की बातों पर ट्रंप ने क्या कहा, यह पता नहीं है। लेकिन, अगर ट्रंप G7 Summit बीच में छोड़कर अचानक अमेरिका न लौटे होते और उनकी पीएम मोदी से आमने-सामने बातचीत होती, तो दृश्य कैसा होता? क्या यह मुमकिन है कि ट्रंप को पहले ही भारत के बदले हुए तेवरों का अंदेशा हो गया हो और उन्होंने सामने पड़ने से बचने में ही भलाई समझी?

कश्मीर पर नीति । भारत की नीति हमेशा से यही रही है कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जा सकती। ऐसे में सरकार इस नीति से नहीं हट सकती। वैसे भी मोदी सरकार ने तो सीमा पार जाकर आतंकवाद के ठिकाने ध्वस्त किए हैं और उसका नीतिगत बयान है कि अब पाक अधिकृत कश्मीर का मसला ही बचा है।

युद्धविराम पर बात नहीं । विदेश सचिव के वक्तव्य से यह धारणा भी टूटी कि इस बीच मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत हुई थी। वक्तव्य के अनुसार, 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी। इसके बाद दोनों नेताओं की यह पहली बातचीत थी। पूरे घटनाक्रम में यह तथ्य महत्वपूर्ण है। इसका मतलब कि 9 जून को केवल अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने बात की थी और उसमें भी युद्धविराम का कोई जिक्र नहीं था।

ट्रंप का 'पाक' पैंतरा
- खामेनेई की सत्ता समाप्त करने की है रणनीति
- ईरान तक मदद पहुंचने से रोकने की हो रही कोशिश
- चीन का पूरा नियंत्रण नहीं होने देना चाहते

भारत की नाराजगी । पीएम मोदी के साथ बातचीत में ट्रंप ने उनसे अमेरिका आने का आग्रह किया। यह व्यवहार हैरत भरा लगता है कि एक तरफ वह भारतीय प्रधानमंत्री को न्योता दे रहे हैं और दूसरी ओर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर को भोज पर बुला रहे हैं। सरकार ने ट्रंप प्रशासन के साथ बिल्कुल सही रणनीति अपनाई और पीएम मोदी ने दूसरी प्रतिबद्धताओं की बात कहकर अमेरिकी निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। ट्रंप और उनके प्रशासन के लिए यह बड़ा धक्का है। कनाडा से कुछ घंटों के लिए अमेरिका जाया जा सकता था, लेकिन अब ट्रंप को भारत की नाराजगी का अहसास हो गया होगा।

पाकिस्तान योजना का हिस्सा । सवाल उठता है कि ट्रंप पाक से इतना सम्मानजनक और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ऐसा लगता, अमेरिका ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई की सत्ता समाप्त करने की रणनीति काफी पहले बना ली थी। इसी के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पाक किसी भी स्तर पर ईरान की मदद न कर पाए। इसके लिए ट्रंप ने इस्लामाबाद की समय-समय पर पीठ ठोकी, IMF से कर्ज दिलाने में मदद की और भारत के साथ तुलना करते हुए उसे भी महान देश बताया। उसी कड़ी में पहलगाम आतंकी हमले के मुख्य खलनायक को इतना भाव दिया जा रहा है। इसके पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी पाकिस्तानी जनरल को इतना महत्व नहीं दिया।

करीबी की वजह । पाकिस्तान और ईरान लगभग 900 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। ईरान के रक्षा मंत्री का यह बयान भी अपने में महत्वपूर्ण है कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों से मदद करेगा। हालांकि पाकिस्तान ने इसका खंडन कर दिया है। फिर भी इस्लाम के नाम पर ऐसी नौबत न आए, इसी आशंका को दूर करने के लिए ट्रंप प्रशासन शायद पाकिस्तान से इतनी करीबी दिखा रहा है।

पश्चिम का डर । अमेरिका में मुनीर की मौजूदगी और ट्रंप के बयानों को भारतीय विदेश नीति की विफलता नहीं कहना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो हैसियत है, वह बनी हुई है। ऐसा नहीं होता तो जी-7 देश यह मांग न करते कि सम्मेलन में भारत को बुलाया जाए। असल में पाक के सच से अमेरिका और यूरोप भी वाकिफ हैं। लेकिन, उनको डर है कि कहीं अलग-थलग होकर पाक एक अराजक देश न बन जाए। वे इस्लामाबाद को पूरी तरह चीन के पाले में नहीं डालना चाहते। यह भी फैक्ट है कि पश्चिमी दुनिया के लिए पाकिस्तान आज वैसा खतरा नहीं है, जैसा भारत के लिए। हिंदुस्तान को अपनी रणनीति इन सारी बातों को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और विचारक हैं)

जलवायु परिवर्तन से मिट्टी भी हो रही ख़तरनाक

मुकुल व्यास

मिट्टी में एक बड़ा खतरा छिपा हुआ है। एक नए अंतरराष्ट्रीय अध्ययन से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन न केवल हमारे ग्रह को गर्म कर रहा है, बल्कि यह मिट्टी के सूक्ष्मजीव समुदायों में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन (ARG) और विषाणु कारकों में खतरनाक बढ़ोतरी कर रहा है। ये जीन बैक्टीरिया को सामान्य उपचारों से बचने में मदद करते हैं, जिससे इन्फेक्शन की आशंका बढ़ जाती है।

गर्मी में बढ़ोतरी । ब्रिटेन की डरहम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के विशेषज्ञों के साथ मिलकर यह रिसर्च की है। इसके मुताबिक गर्म परिस्थितियां न केवल प्रतिरोधी बैक्टीरिया को जीवित रहने में मदद करती हैं, बल्कि उनकी ऐसी किस्मों के विकास को भी प्रोत्साहित करती हैं जो मनुष्यों में अपना रास्ता खोजने से पहले प्राकृतिक वातावरण में रहती हैं। यूनिवर्सिटी के प्रो. डेविड ग्राहम ने बताया कि जलवायु में बदलाव दुनिया भर में मिट्टी में एंटीबायोटिक प्रतिरोध को बढ़ावा देने में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। इसलिए सभी के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए 'वन हेल्थ एप्रोच' अपनानी बहुत जरूरी है।

नए-नए संक्रमण । अधिकांश लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि मनुष्यों में संक्रामक रोग पैदा करने वाले अधिकांश रोगाणु वास्तव में पर्यावरण से उत्पन्न होते हैं। प्रो. ग्राहम ने कहा कि इसलिए मिट्टी में प्रतिरोध बढ़ने से निश्चित रूप से मनुष्यों और पशुओं में नए संक्रमण के स्तर में वृद्धि होगी। यही वजह है कि वन हेल्थ सॉल्यूशन महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों ने पाया कि ठंडे क्षेत्र, जहां बैक्टीरिया कम तापमान के कारण मर जाते थे, अब खतरनाक रोगाणुओं के लिए अधिक अनुकूल होते जा रहे हैं। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, ये बैक्टीरिया लंबे समय तक जीवित रहते हैं, तेजी से विकसित हो सकते हैं। इससे पूरी तरह से नए रोगाणु बन सकते हैं, जिन्हें हमारे एंटीबायोटिक्स छू भी नहीं सकते।

AI Image

ज्ञान-विज्ञान

बदलते गुणसूत्र । जलवायु और एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बीच संबंध की भविष्यवाणी 2023 की संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में की गई थी। तापमान में मामूली वृद्धि भी बड़े बदलावों को जन्म देती है। पर्यावरण में व्यापक रूप से मौजूद ई कोलाई बैक्टीरिया पर किए अध्ययन से पता चला कि गर्म परिस्थितियों के कारण इसमें प्रमुख एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन की अभिव्यक्ति में वृद्धि हुई है। अध्ययन में इस्तेमाल किए गए मशीन लर्निंग मॉडल विचलित करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। इसमें इस सदी के अंत तक दुनिया की मिट्टी में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीनों के स्तर में 23% तक की वृद्धि हो सकती है। सूक्ष्मजीव समुदायों में जलवायु-संचालित परिवर्तन एंटीबायोटिक प्रतिरोध को रोकने के प्रयासों को कमजोर कर सकते हैं। रिसर्चरों ने चेतावनी दी है कि यदि मिट्टी प्रतिरोधी बैक्टीरिया को पोषित करना जारी रखती है, तो प्रतिरोधी गुणों का मानव रोगाणुओं में पहुंचना और भी आसान हो सकता है।

मौन परिवर्तन । कोविड-19 जैसी पिछली महामारियों ने दिखाया है कि रोगाणु कितनी आसानी से पर्यावरण से इंसानों तक पहुंच सकते हैं। यही रास्ते एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी बैक्टीरिया को भी ऐसा करने में मदद कर सकते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक नया और गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। हमारी मिट्टी में हो रहा मौन परिवर्तन हमें याद दिलाता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हमारी नजर से कहीं ज्यादा दूर तक फैले हुए हैं। वे आसपास की अदृश्य दुनिया को भी नया आकार दे रहे हैं, जिससे हमारे जीवन के हर हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं।

राजनीति में कई बार अच्छा करने पर भी नहीं मिलता जनता का भरोसा

विशुद्ध राजनीति
इंटरव्यू

यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष **अजय कुमार लल्लू** इन दिनों ओडिशा का प्रभार देख रहे हैं। ओडिशा में पार्टी को खड़ा करने, BJP सरकार को कटघरे में लाने और राज्य के सियासी समीकरणों से लेकर यूपी के हालात तक पर उनसे NBT की **मंजरी चतुर्वेदी** की बात हुई। पेश हैं बातचीत के चुनिंदा अंश :

■ ओडिशा में BJP सरकार के एक साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं?

BJP का एक साल प्रताड़ना का रहा। सत्ता में आते समय BJP ने 2036 का सपना दिखाया था। लेकिन एक साल में न सुशासन दिखाई दिया, न सामाजिक न्याय के लिए काम हुआ। इन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात की थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जेल तैयार है। तमाम समितियों की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार की गाथा है, फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ।

■ पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस ने ओडिशा में जो विरोध प्रदर्शन किए, उनमें ज्यादातर मानवीय मुद्दे थे। आपने अभी जिन मुद्दों का जिक्र किया, क्या उन्हें लेकर भी कांग्रेस जवाबदेही की मांग करेगी?

राज्य में BJD और BJP की सरकार संयुक्त रूप से पिछले 11 साल से चल रही थी, आखिर के एक साल में ये अलग हुए। अब BJP सरकार में है। राज्य से 44 हजार महिलाएं गायब हैं। इन्हें खाड़ी के देशों में ले जाकर बेचा जा रहा है। हमें डर है कि इनके ऑर्गन भी बेचे जा रहे हैं। कई मामलों में हॉस्टलों में रहने वाली 12-14 साल की बच्चियां गर्भवती हो रही हैं। जब हमारी पार्टी ने इस पर आंदोलन किया, लाठियां चलीं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हमारे कुछ लोग आज भी जेल में हैं। हमारे 14 विधायकों ने सदन में इस मुद्दे को उठाया तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इस सरकार ने कहा था कि चिटफंड पर 24 घंटे के भीतर पैसा दिलवा देंगे। लेकिन एक साल बाद भी न चिटफंड वालों पर कार्रवाई हुई, ना निवेशक का पैसा मिला।

■ एक साल पूरे होने पर अक्सर सरकारें जश्न मनाती हैं और विपक्ष सवाल खड़ा करता है और इसे एक रस्म अदायगी मान लिया जाता है। लेकिन एक साल बाद भी आप इन सारे मुद्दों को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे, इसे लेकर आपकी क्या रणनीति है?

हम इन तमाम मुद्दों को लेकर बाकायदा लोगों के बीच जा रहे हैं। आदिवासियों के जमीन का पट्टा, राज्य से बड़ी तादाद में पलायन, उद्योग न लगना, कोल माइंस की वजह से 70 हजार लोगों का विस्थापन, या उस इलाके में स्थानीय BJP विधायक द्वारा 90 हजार पेड़ों को बिना इजाजत काटने का मामला हो, हम लगातार इनको उठा रहे हैं। कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। साथ ही, हम अपनी संगठनात्मक प्रक्रिया भी चला रहे हैं। भले ही हम वहां मुख्य विपक्षी दल न हों, लेकिन एक अच्छे विपक्ष की तरह हम सदन से लेकर सड़क तक लगातार सरकार को घेर रहे हैं।

■ आपने अभी संगठन की बात कही। लेकिन ओडिशा में कांग्रेस तो खुद की वजह से कमजोर हुई और विपक्ष की जगह BJP लेती गई। संगठन की मजबूती के लिए कांग्रेस क्या कर रही है?

यह कहना गलत होगा कि वहां पर हमारे नेताओं ने मेहनत नहीं की। लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि राजनीति संभावनाओं का दौर होता है। कई बार बहुत अच्छा करने के बाद भी हम जनता का भरोसा हासिल नहीं कर पाते। लेकिन हम लोग जिस तरह से जमीन पर उतर रहे हैं, हमें भरोसा है कि जनता हमारे साथ खड़ी हो रही है। पंचायत, ब्लॉक कमिटी, फ्रंटल विभाग, प्रकोष्ठ आदि का जिस तरह से गठन हो रहा है, उसके चलते हम मजबूती से लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। आने वाले पंचायत चुनावों में हमें इसका लाभ मिलेगा।

■ आप ओडिशा में अपना मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं- BJP या BJD?

आज BJP और BJD दोनों अलग हैं, हमारा मुकाबला दोनों से है। लेकिन दोनों कब मिल जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। दोनों की राजनीति पैसे पर ज्यादा आधारित है।

रीडर्स मेल
www.edit.nbt.in

■ चुनौती वाला समय

19 जून का लेख 'US कमजोर हुआ तो घाटे में रहेगी दुनिया' पढ़ा। यह लेख एक गंभीर वैश्विक सचाई की ओर इशारा करता है कि अमेरिकी नेतृत्व वाली व्यवस्था टूटती है तो उसके दूरगामी प्रभाव होंगे। लेखक ने इतिहास का हवाला देते हुए बिलकुल ठीक कहा है कि जब कोई साम्राज्य ढहता है, तो केवल शासन नहीं, बल्कि व्यवस्था और समृद्धि भी जाती रहती है। अमेरिका की अगुआई में बने वैश्विक संस्थानों और नियमों ने दुनिया को दशकों तक स्थायित्व, आर्थिक प्रगति और अपेक्षाकृत शांति दी है। अब जब यह व्यवस्था दुनिया के अलग-अलग खेमों में बंट गई है, तो संघर्ष, अस्थिरता और अनिश्चितता के बढ़ने की आशंका भी बढ़ गई है। भारत जैसे देश के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय है। हमें एक गहरे भू-राजनीतिक मोड़ की चेतावनी मिल रही है।

महेश प्रसाद वर्मा, ईमेल से

■ बदलनी होगी सोच

यह पत्र 18 जून के लेख 'बाल फिल्मों में पीछे क्यों है बॉलिवुड' से संबंधित है। 'चिड़िया' जैसी फिल्में यह सिद्ध करती हैं कि बच्चों की सरल कहानियां भी गहरा प्रभाव छोड़ सकती हैं। दुर्भाग्यवश, भारत में बाल फिल्मों को आज भी गंभीरता से नहीं लिया जाता। समस्या यह है कि निर्माता वैसी फिल्में बनाते हैं जिनसे कमाई हो। ऐसा करने के पीछे उनका मानना है कि बच्चों वाली फिल्म से उन्हें कमाई कम होगी। यही कारण है कि बच्चों को उनकी सोच जैसी फिल्में नहीं मिल पाती हैं। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया ने भी बच्चों की सोच को बदल डाला है।

गीता रावत, नोएडा

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

20 से 30 जून तक दिल्ली में आ सकता है मॉनसून - एक खबर
- माहौल तो दो दिन पहले से बन रहा है!

प्रदीप सिंह

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

सृष्टि के जादू से मिला है यह अनमोल जीवन

क्या आप जानते हैं, हमारा अस्तित्व क्यों है? ब्रह्मांड इतना विशाल है, फिर जीवन इस छोटे-से ग्रह पर ही क्यों पनपा और फला-फूला? इसका जवाब साइंस चैनल Cosmoknowledge के एक विडियो में मिलता है। असल में, हमारा जीवन कोई ऐसा चमत्कार नहीं, जो बस यूं ही हो गया। इसके पीछे ब्रह्मांड की कुछ अद्भुत ताकतें हैं। ये ताकतें मिलकर काम करती हैं। इन्हीं की वजह से हमारा अस्तित्व सुरक्षित रहा और आज हम इस मुकाम तक पहुंच सके।

इनमें सबसे पहली ताकत है चंद्रमा। समुद्र में उठने वाला ज्वारभाटा इसी चांद का जादू है। लहरों की इन हरकतों का असर पड़ता है पानी में मौजूद जीवन पर। हालांकि, चंद्रमा केवल पानी के उतार-चढ़ाव को ही नियंत्रित नहीं करता, यह कवच भी है हमारा। न जाने कितने asteroid की टक्कर इसने झेली। अगर बीच में चंद्रमा न होता, तो वे आकाशीय पिंड पृथ्वी से टकरा कर यहां के जीवन के लिए खतरा बन सकते थे।

सौरमंडल में थोड़ा और दूर जाकर हमें मिलता है बृहस्पति ग्रह यानी Jupiter - हमारी धरती का पहरेदार। धरती के लिए ढाल की तरह काम करती है इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अंतरिक्ष से आने वाली उल्काएं या तो इससे टकरा कर चूर हो जाती हैं या रास्ता बदल देती हैं। सोचिए, बृहस्पति न होता तो? अनुमान है कि तब पृथ्वी को space से 10 हजार गुना ज्यादा टकराव झेलने पड़ते। इनमें से कोई भी टक्कर एक पल में जीवन को मिटा देती। अब बढ़िए सूरज की तरफ, जिसकी वजह से धरती आबाद हुई, जिसने हमें अपनी रोशनी और गर्माहट का दुलार दिया। लेकिन, इस अद्भुत देन के आगे भी बहुत कुछ है, heliosphere - एक अदृश्य घेरा जो Pluto के भी आगे तक फैला हुआ है। यह घेरा सुरक्षा कवच है, घातक cosmic radiation से केवल धरती नहीं, पूरे Solar System को बचाता है।

लेकिन, ये सारी मदद शायद कारगर न होतीं, अगर धरती खुद भी हमारे लिए न खड़ी होती। पृथ्वी के चारों तरफ मौजूद magnetic field खतरनाक solar radiation से बचाता है। इस बचाव के बिना इस ग्रह का वातावरण खत्म हो सकता था।

सूरज, चांद, ग्रह, मैग्नेटिक फील्ड और atmosphere - ये सभी इस विशाल ब्रह्मांड के कल-पुर्जे जैसे हैं, जिनके बीच जबरदस्त समन्वय है और जिन्होंने जीवन की डोर को थामे रखा है। अगर इनमें से कोई एक भी न होता या अपने काम को ठीक से अंजाम न दे पाता, तो शायद हम भी न होते।

प्राचीन ऋषि-मुनियों ने सिखाया था कि हमें केवल बाहर ही नहीं, अपने भीतर भी झांकना चाहिए। ब्रह्मांड हमसे अलग नहीं है - यह हमारे ही अस्तित्व में बुना हुआ है। खुद को अकेला समझना छोड़ दीजिए। हम एक दिव्य संतुलन का हिस्सा हैं, जिसे ब्रह्मांड की शक्तियों ने बहुत सावधानी से सहेज रखा है।

- एनबीटी

कल्पमेधा

किसी के गुणों की सराहना करने में अपना समय बर्बाद मत करो, उसके गुणों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए।
- कार्ल मार्क्स

मनमाना रवैया

राजमार्गों के जाल और साथ ही बढ़ते टोल नाके। इन टोल नाकों पर फास्टैग प्रणाली का समूचा ढांचा संचालन की खामियों के कारण सवालों के घेरे में है। सरकार ने फास्टैग आधारित तीन हजार रुपए वाले वार्षिक पास की योजना का एलान किया है और दावा किया है कि इससे कई तरह के झंझटों से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। इस पास में पूरे साल टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन शर्तें भी लगाई गई हैं। इस योजना के तहत एक साल में दो सौ चक्कर लगा सकते हैं। यह योजना अभी सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों एवं पूर्वोत्तर के टोल प्लाजा पर ही मान्य होगी। राज्य मार्गों के अंतर्गत आने वाले टोल नाकों पर यह नया पास नहीं चलेगा। यह केंद्र सरकार की योजना है और इसमें राज्यों को जोड़ने की कवायद दुरुह है। इसके लिए ढांचा तैयार करना आसान नहीं होगा। यह तो नई योजना की बात हुई। दरअसल, फास्टैग की पूरी प्रणाली को लेकर ही उपभोक्ताओं की ढेरों शिकायतें हैं। उन शिकायतों की न तो कहीं सुनवाई हो रही है और न ही किसी स्तर पर चीजें ठीक करने की कोशिश दिख रही है। आम उपभोक्ता खामियाजा भुगत रहा है। फास्टैग के पूरे तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही का घोर अभाव दिखता है। इसके लिए कोई विनियमन नहीं है, न तो कोई नियामक।

देश में 39 बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को फास्टैग जारी करने का अधिकार दिया गया है। क्या ये लोग अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं। जब कोई उपभोक्ता अपनी समस्या लेकर बैंक के पास जाता है तो उसे यह कहकर टाल दिया जाता है कि काम 'तीसरी पार्टी' के पास है। अब उपभोक्ता तीसरी पार्टी को कहां ढूंढने जाए। खराब हुआ फास्टैग स्टीकर, खाते में से बार-बार राशि कट जाना, दोगुना टोल भुगतान, सर्वर की गड़बड़ी - इस तरह की खामियों की आखिर कौन लेगा जिम्मेदारी। कैसे उपभोक्ता को अपनी परेशानियों से निजात मिलेगी। सरकार के टोल संग्रह के आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है। यह अच्छी बात है, लेकिन बढ़िया सेवा की उम्मीद तो उपभोक्ता करेगा ही।

इसमें दो राय नहीं कि ढांचा अच्छा है। इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। लेकिन खामियां भी हैं, जिनसे आम उपभोक्ता परेशान हो रहा है। इस योजना का लाभ तभी मिल सकता है, जब सड़कें दुरुस्त हों और लोगों को अपनी यात्रा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। लेकिन हैरत की बात है कि फास्टैग प्रणाली से पांच हजार करोड़ का राजस्व जमा करने वाली कंपनी का कोई ऐसा दफ्तर नहीं, जहां कोई उपभोक्ता पहुंच सके और अपनी बात रख सके। टोल नाकों पर लोग दिखते हैं, लेकिन वे उपभोक्ताओं के प्रति कितने जिम्मेदार होते हैं इसको लेकर सवाल हैं। उन लोगों के लिए जटिलता और बढ़ जाती है, जो पहली बार फास्टैग ले रहे हैं या जिन्हें इसकी प्रक्रिया के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। अनधिकृत विक्रेता आसानी से अपने चंगुल में फांस लेते हैं। इस तरह के लोगों पर अंकुश कैसे लगे। राजमार्गों का चमचमाता तंत्र विकसित करना ही पर्याप्त नहीं है। राजमार्गों की व्यवस्था तभी मजबूत कही जाएगी, जब इस्तेमाल के लिए सुचारु व्यवस्था होगी, मजबूत तंत्र खड़ा किया जाएगा और उपभोक्ताओं को अपनी यात्रा में कोई दिक्कत नहीं होगी।

अमानवीयता की हद

युद्ध के उन्माद में संवेदना खत्म हो रही है। इजराइल व ईरान एक-दूसरे के ठिकानों पर हमला करने में अमानवीयता की सारी हदें लांघ रहे हैं। ईरान ने समूची नैतिकता को ताक पर रखते हुए इजराइल के मुख्य अस्पताल को निशाना बनाया है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब इजराइल ने युद्ध के सभी नियमों को ताक पर रख कर दक्षिणी गाजा के सबसे बड़े अस्पताल पर हमला कर कई लोगों को जख्मी कर दिया था। युद्ध की आग में गाजा को लगातार झुलसाने वाले इस देश को गुरुवार तड़के ठीक उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कोई दो राय नहीं कि युद्ध हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। दो देशों के बीच प्रतिशोध की आग बेकसूर नागरिकों को ही झुलसाती है। दुनिया ने यह दृश्य कई बार देखा है। सैन्य हमले के दौरान इजराइल ने कभी नहीं देखा कि वह शरणार्थी शिविरों पर बम गिरा रहा है या अस्पतालों पर। नागरिक ठिकानों पर कितनी मौतें होंगी और बच्चों-महिलाओं तथा बुजुर्गों पर क्या गुजरेगी। उसे कभी मानवीय संवेदना की परवाह नहीं रही। दूसरी ओर इजराइल के भीषण हमले के जवाब में ईरान की सैन्य कार्रवाई से साबित हो गया कि वह भी उतना ही असंवेदनशील है। दक्षिणी इजराइल के मुख्य अस्पताल को निशाना बना कर उसने स्पष्ट कर दिया कि वह भी युद्ध नियमों को नहीं मानता। कुछ मिसाइलें इमारतों पर गिरीं, जिससे कई नागरिक घायल हो गए।

ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को अपने अस्तित्व के लिए खतरा बता कर इजराइल ने जिस तरह से उसके साथ युद्ध छेड़ा है, इसके नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं। दुनिया के बड़े हिस्से में इसका असर दिख सकता है। ईरान की इस चेतावनी को गंभीरता से लेने की जरूरत है कि अगर अमेरिका युद्ध में कूदा तो भीषण तबाही होगी। तेहरान खाली करने की अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी और ईरानी नेतृत्व के बयान से लगता है कि इजराइल के साथ उसका सैन्य टकराव तीक्ष्ण रूप से बढ़ेगा। स्वाभाविक है कि इस युद्ध के जख्म गहरे होंगे। इसकी कीमत वे नागरिक ही चुकाएंगे, जिनका युद्ध से कोई संबंध नहीं। न जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे।

कर्ज के जाल में फंसा पाकिस्तान

पाकिस्तान के बजट का करीब आधा हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में जा रहा है। इस बार के बजट में भी शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार पर खर्च प्राथमिकता में नहीं है, बल्कि सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए रक्षा बजट में करीब 20 फीसद की वृद्धि की गई है।

जयंतीलाल भंडारी

इन दिनों अमेरिका बेशक भारत के साथ पाकिस्तान को बराबरी पर रखने की अनुचित कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया में प्रकाशित हो रही विभिन्न रपटों में जहां भारत को आर्थिक ऊंचाई हासिल करते देश के रूप में रेखांकित किया जा रहा है, वहीं, पाकिस्तान को कर्ज में डूबे व आर्थिक जोखिमों से ग्रस्त देश के रूप में चिह्नित किया जा रहा है। हाल ही में प्रस्तुत किए गए पाकिस्तान के वर्ष 2025-26 के बजट की तस्वीर में यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बजट का करीब आधा हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में जा रहा है। वहां गरीबी में कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार पर खर्च प्राथमिकता में नहीं है। मगर, सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए रक्षा बजट में करीब 20 फीसद की वृद्धि की गई है। इस बजट के बाद एक ओर जहां कर्ज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को खस्ताहाल बनाएगा, वहीं भारत की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों से उसकी आर्थिक मुश्किलें और बढ़ेंगी।

गौरतलब है कि पाकिस्तान के इस नए बजट के पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ है, वह उसकी दयनीय स्थिति रेखांकित करते हुए दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान पर कुल 76,000 अरब रुपए के कर्ज का बोझ है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार महज 16.64 अरब डालर का है। इतना ही नहीं इन दिनों पाकिस्तान अपनी खस्ताहाल आर्थिक स्थिति के बीच एक के बाद एक नए विदेशी कर्ज लेते हुए दिखाई दे रहा है। उसके कर्ज और जीडीपी के बीच अनुपात लगभग 65 फीसद है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक माना जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, इतना अधिक कर्ज और उसका सही ढंग से प्रबंधन न होना पाकिस्तान की आर्थिक और राजकोषीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन गया है।

यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि पाकिस्तान इस समय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्ज पर निर्भर है। हाल ही में प्रकाशित मुद्रा कोष की रपट के मुताबिक, आर्थिक अस्थिरता, महंगाई और खराब विदेशी कर्ज हालात जैसे कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लगातार पीछे कर रहे हैं। मई 2025 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उसे एक अरब डालर का कर्ज दिया है। मगर इसके साथ ही उसने पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें भी लगा दीं। अब कुल मिलाकर मुद्रा कोष की शर्तों की संख्या 50 हो गई है, जो सात अरब डालर के कर्ज के बदले में लगाई गई हैं। मुद्रा कोष के अनुसार, चालू वर्ष में पाकिस्तान की बेरोजगारी दर 8.5 फीसद है। वहीं, गरीबी भी बढ़ रही है। वर्ष 2017 में जहां 39.8 फीसद लोग गरीबी में थे, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़ कर 44.7 फीसद हो गई है। इसके अलावा, पाकिस्तान को खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में लगभग एक करोड़ लोग बेहाल हैं। पाकिस्तान के संबंध में विश्व बैंक की एक नई रपट के अनुसार, पाकिस्तान की विकास दर इतनी कम है कि गरीबी में कोई खास कमी नहीं हो पा रही है। एक सच्चाई यह भी है कि वहां की सेना-समर्थित सरकार भारत से सैन्य मुकाबले के मद्देनजर रक्षा बजट बढ़ाना ज्यादा जरूरी मान रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और पाकिस्तान खस्ताहाल है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि भारत के आर्थिक प्रतिबंध पाकिस्तान के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती है और अगर वह भारत में आतंक का निर्यात जारी रखता है, तो उसे आर्थिक रूप से बर्बाद होना पड़ेगा। अभी स्थिति यह है कि पहलगाम हमले के बाद स्थगित किए गए सिंधु जल समझौते ने कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ा दी है। इतना ही नहीं भारत ने चिनाब नदी पर बगलिहार बैराज से पानी के प्रवाह को रोक दिया है। साथ ही झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध के माध्यम से भी इसी तरह के कदम उठाने की रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में पानी के मुद्दे पर पाकिस्तानी संसद से लेकर सेना तक में बेचैनी देखी जा रही है। पाकिस्तानी सांसद सैयद अली जफर ने संसद में कहा कि अगर हम पानी का मुद्दा सुलझा नहीं पाए, तो भूखे मर जाएंगे। सिंधु बेसिन ही हमारी जीवनरेखा है। 90 फीसद खेती इस पानी पर निर्भर है। वस्तुतः 20वीं सदी की जंग तेल पर थी, जबकि 21वीं सदी की जंग पानी के लिए होगी। पाकिस्तान इस समय पानी की कमी वाले शीर्ष देशों में शामिल है।

इस परिप्रेक्ष्य में विश्व बैंक के प्रमुख अजय बंगा ने कहा है कि सिंधु जल संधि में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान की भूमिका सिर्फ मध्यस्थ की है और वह भारत की ओर से संधि के निलंबन पर कोई दखल नहीं देगा। जल संकट से परेशान पाकिस्तान लगातार भारत से गुहार लगा रहा है। छह जून तक पाकिस्तान ने भारत को चार पत्र लिख कर इस फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। दूसरी तरफ भारत ने जल संधि को निलंबित करने के फैसले के पीछे सीमा पार आतंकवाद को कारण बताया है। साथ ही, जल परियोजनाओं को लेकर भी कुछ तकनीकी आपत्तियां बताई हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी प्रकार के कारोबार पर पूरी तरह रोक लगा दी है। पाकिस्तान में तैयार हुए सभी सामान के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर रोक लगी हुई है। सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली सभी प्रकार की डाक और पार्सल सेवाओं के आदान-प्रदान को निलंबित कर दिया है। यह निर्णय हवाई और जमीनी दोनों मार्गों पर लागू हुआ है।

भारत ने 'अटारी लैंड-ट्रांजिट पोस्ट' को भी बंद कर दिया है। इस चौकी का इस्तेमाल दोनों देशों के बीच सामाप की आवाजाही के लिए किया जाता रहा है। हाल यह है कि कर्ज में डूबे पाकिस्तान में महंगाई नियंत्रण से बाहर हो गई है। यह बात भी अहम है कि भारत, पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की ग्रेलिस्ट सूची में वापस लाने की तैयारी कर रहा है। उसने हाल ही के दिनों में वैश्विक धनशोधन और आतंकवादी वित्तपोषण निगरानी संस्था एफएटीएफ को इस संबंध में जानकारी दी है। यह निर्धारित किया गया है कि भारत की तरफ से एफएटीएफ को एक विस्तृत डोजियर भेजा जाएगा, जिसमें धनशोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण में शामिल संस्थाओं और लोगों के सबूत होंगे। एफएटीएफ से अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। एफएटीएफ की संभावित बैठक में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान के बढ़ते कर्ज और वित्तीय चुनौतियां उसकी आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर सकती हैं।

> **पाकिस्तान के चालू वित्त वर्ष के बजट से पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ है, वह उसकी दयनीय स्थिति रेखांकित करता है। पाकिस्तान पर कुल 76,000 अरब रुपए के कर्ज का बोझ है। इतना ही नहीं, इन दिनों पाकिस्तान अपनी खस्ताहाल आर्थिक स्थिति के बीच एक के बाद एक नए विदेशी कर्ज ले रहा है। उसके कर्ज और जीडीपी के बीच अनुपात लगभग 65 फीसद है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक माना जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, इतना अधिक कर्ज और उसका सही ढंग से प्रबंधन न होना पाकिस्तान की आर्थिक और राजकोषीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन गया है।**

भाषा की शालीनता

दुनिया मेरे आगे

प्रभुनाथ शुक्ल

भाषा हमारी शालीनता और व्यक्तित्व की परिभाषा है। भाषा हमारी संस्कृति, संस्कार और उन्नति की मूल है। भाषा हमारा सौंदर्यबोध है। मानव सभ्यता के विकास में भाषा का अमूल्य योगदान है। जिस तरह एक बुरी संस्कृति एक सभ्य समाज का निर्माण नहीं कर सकती, उसी तरह एक असंयमित भाषा भी हमारी सभ्यता को गहरे गर्त में धकेलती है। एक अच्छी भाषा हमारा संस्कार होती है। जिस तरह हमें जीने के लिए वायु की जरूरत होती है, उसी तरह जीवन की गतिशीलता और सार्वभौमिक विकास के लिए अच्छी भाषा की आवश्यकता होती है। हमारे पास दुनिया की समस्त आधुनिक सुविधाएं भले हों, लेकिन भाषा के अभाव में जीवन दर्शन बेमतलब है। राष्ट्र के निर्माण के लिए एक संस्कारित भाषा का होना आवश्यक है। भाषा हमारे व्यक्तित्व का दर्पण है। जब हम ओजपूर्ण शैली में बोलते हैं, तो हमारी भाषा हमारे व्यक्तित्व को विशिष्ट बनाती है।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाषा को संस्कृति और समाज का दर्पण माना। भाषा में शालीनता और शिष्टता समाज के नैतिक मूल्यों को दर्शाती है। उनके अनुसार, भाषा का प्रयोग ऐसा होना चाहिए जो विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करे, लेकिन साथ ही वह दूसरों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता को बनाए रखे। प्राचीन भारतीय दार्शनिक पाणिनि भर्तृहरि ने संस्कृत व्याकरण और दर्शन में भाषा को विश्व की समझ और आध्यात्मिक चेतना का माध्यम माना। भर्तृहरि ने शब्दब्रह्म सिद्धांत में कहा कि भाषा और चेतना अभिन्न है। विदेशी विद्वान विल्हेम वान हम्बोल्ट ने भाषा को केवल संचार का साधन नहीं, बल्कि मानव विचार और संस्कृति की रचनात्मक अभिव्यक्ति माना। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भाषा एक अनूठा विश्व दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यानी वैश्विक विकास और सभ्यता के मूल में भाषा है।

भाषा सिर्फ संचार या संवाद का माध्यम नहीं है। यह हमारी संस्कृति और समाज का आधार है। भाषा यह साबित करती है कि हमारी सभ्यता, संस्कार और सामाजिक विकास एवं इतिहास की जड़ें कितनी गहरी हैं। हम शालीन भाषा से समाज में अपना संदेश मजबूती से पहुंचा सकते हैं। दुनिया में अनगिनत कबिलाई समूह हैं, लेकिन उनकी भाषा वैसी नहीं होती है। हम अपने को आधुनिक और सभ्य भले कह लें, लेकिन जब तक हमारे पास शालीन भाषा नहीं होगी, हमारे सभ्य कहलाने का सफर बाकी रहेगा। भूमंडलीकरण के दौर में जहां हमारी भाषा समृद्ध और सशक्त हुई है, वहीं उससे कई गुना उसका पतन हुआ है। हमने भाषा को लेकर अपना संयम और चरित्र खोया है। हम चांद पर भले पहुंच गए हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक गहराई में भाषा को लेकर हम इस हद तक कमजोर हुए हैं कि हमारे पास उसे मापने के लिए कोई पैमाना नहीं है।

चिंता इस बात की है कि किसका स्तर नीचे होता चला जा रहा है? भाषा का या हमारा? भाषा सकाम कर्म नहीं कर सकती। वह निर्जीव होते हुए भी सजीव है। वह हमारी मार्गदर्शक है। भाषा का कोई रूप, रंग, गंध और स्वाद-स्पर्श नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वह समस्त रूपों में विद्यमान है। जिस तरह हम ठोस स्वर्ण को आभूषणों के विभिन्न रंग में ढाल देते हैं और वह हमारा सौंदर्य बन जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारी भाषा है। इंटरनेट पर कई मंचों के उदय के बाद हमारी भाषा में भदेसपन बढ़ा है। हमने वैचारिकता और जय-पराजय के चौसर पर भाषा को महत्त्व देना बंद कर दिया है। दूसरी ओर, सोशल मीडिया ने आग में घी का काम किया है। हम भाषा को लगातार अपमानित कर रहे हैं। जबकि सच बात यह है कि भाषा कमजोर नहीं हो रही, हमारा खोखलापन सामने आ रहा है। विशिष्टता की होड़ में हमने अपनी शिष्टता को दांव पर लगा दिया है। भाषा हमारी रीढ़ है। यह हमारी शालीनता, सभ्यता, संस्कार, नैतिकता, एकता और अखंडता है। अगर किसी की भाषा मर्यादित है तो निश्चित रूप से उसका जीवन संयमित है। भाषा ही हमारे आदर्श की लक्ष्मण रेखा है। यह सोचने की बात है कि अगर हमारे पास एक सभ्य भाषा की मिठास नहीं होगी, तो क्या हम एक सौहार्दपूर्ण समाज की स्थापना कर पाएंगे। भाषा में वह ताकत है, जो हमें माधुर्य और वस्तु के तीखेपन का आभास कराती है। आम का नाम लेते ही हमें उसकी मिठास के स्वाद का अहसास होने लगता है। ठीक उसी तरह यह नियम मिर्च पर भी लागू होती है। मतलब साफ है कि हमारी भाषा में आम की मिठास और मिर्च का तीखापन दोनों हैं। अब हम किसका स्वाद लेना चाहते हैं, यह हम पर निर्भर है। हम सभ्यता के कई आयाम तय कर चुके हैं। भाषा के तकनीकी विकास को लेकर भी हमने नई दिशा तय की है। लेकिन अभी भाषा की अराजकता पर हमें बहुत कुछ करना है। हमें यह तय करना होगा कि वाकयुद्ध के इस संघर्ष में कहीं हम इतने पीछे न छूट जाएं कि फिर वहां से लौटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए।

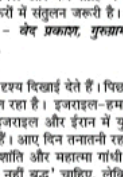

> **भाषा हमारी रीढ़ है। यह हमारी शालीनता, सभ्यता, संस्कार, नैतिकता, एकता और अखंडता है। अगर किसी की भाषा मर्यादित है तो निश्चित रूप से उसका जीवन संयमित एवं मर्यादित है। भाषा ही हमारे आदर्श की लक्ष्मण रेखा है। अशिष्ट भाषा हमारे समाज को बांटती है।**

चौपाल

हिंसक प्रवृत्ति

बच्चे हिंसक क्यों बनते हैं? इसके पीछे सबसे महत्त्वपूर्ण कारण साथियों या दोस्तों द्वारा बार-बार चिढ़ाया जाना, मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाना है। जब यह जब सीमा पार कर जाता है, तो वे एक क्षण में टूट जाते हैं और हिंसक कृत्य कर बैठते हैं। ऐसे मामलों में से 75 फीसद में यही वजह सामने आई है। हाल ही में आस्ट्रिया के एक शहर में ऐसी ही एक घटना घटी। सुबह जब स्कूल में पढ़ाई हो रही थी, तभी एक पूर्व छात्र बंदूक लेकर वहां आता है और अंधाधुंध गोलीबारी करता है। बाद में खुद को भी गोली मार लेता है। विकसित देशों में हथियार रखने की संस्कृति, माता-पिता से बच्चों को मिला संस्कार, परिवार में कलह, अभिभावकों का बच्चों पर ध्यान न देना जैसी कई वजहें इन घटनाओं का कारण होती हैं। बच्चों में मानसिक विकार और अवसाद का समय पर इलाज न होना भी एक बड़ा कारण है। अमेरिका इस तरह की घटनाओं में आगे है, लेकिन अब यह समस्या अन्य देशों में भी फैलने लगी है।

- दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुंबई

प्लास्टिक का जहर

प्लास्टिक के आविष्कार से मानव जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इसने हमारे जीवन को सुगम जरूर बनाया है, लेकिन प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग पर्यावरण के लिए नासूर बन गया है। आज कोई भी क्षेत्र प्लास्टिक से अछूता नहीं रहा। टूथब्रश, दूध का पैकेट, भोजन को ताजा रखने और दवाइयां को सुरक्षित रखने के लिए, संचार के साधन, यातायात के कलपुर्जे आदि सभी क्षेत्रों में प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। आज गांवों की गलियों से लेकर शहर का चौक-चौराहा, नदी-नाला, समुद्र की गहराई और पर्वतों के चोटियों पर प्लास्टिक कचरा बिखरा हुआ है। हवा में अब प्लास्टिक के कण मौजूद हैं, जो सांस के जरिए हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों को प्लास्टिक की जगह कोई और विकल्प तलाशने का प्रयास करना चाहिए।

- हिमांशु शेखर, गया

संतुलन और सुविधा

देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू हुए सात साल हो गए हैं। मगर इसके क्रियान्वयन में एकरूपता न होने के कारण अब भी कई समस्याएं सामने आ रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री सीमा शुल्क विभाग तथा अप्रत्यक्ष कर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रही हैं। इस बैठक को जीएसटी सुधार की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब तक समय-समय पर जीएसटी परिषद की बैठकों में अनेक संशोधन और दरों में बदलाव किए गए हैं। पांच, बारह, अठारह और अट्ठाइस फीसद की विभिन्न दरें लागू हैं। ये आम लोगों व व्यापारियों के लिए असुविधाजनक हैं। सरकार को चाहिए कि जीएसटी की दो श्रेणियां बनाई जाएं और इसे आवश्यक वस्तुओं और अन्य वस्तुओं तक सीमित किया जाए। विलासिता दर को भी कम करना उचित होगा, ताकि जनता को भी लाभ मिले और कर संग्रह में भी बढ़ोतरी हो। करों में संतुलन जरूरी है।

- वेद प्रकाश, गुरुग्राम

जियो और जीने दो

आज कहीं भी शांति नहीं है। हर जगह तबाही के दृश्य दिखाई देते हैं। पिछले तीन वर्षों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इजराइल-हमास भी काफी समय से आमने-सामने हैं। अब इजराइल और ईरान में युद्ध छिड़ गया है। पाकिस्तान की कारगुजारियां सबके सामने हैं। आए दिन तनातनी रहती है। महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो, गौतम बुद्ध ने शांति और महात्मा गांधी ने अहिंसा का संदेश दिया। यह भी कहा जाता है कि 'युद्ध नहीं बुद्ध' चाहिए, लेकिन यहां तो सभी युद्धरत दिख रहे हैं। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों से पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से खलबली मचाता रहता है। जियो और जीने दो की नीति अपनाकर सभी देश शांति के मार्ग पर क्यों नहीं चलते।

- हेमा हरि उपाध्याय, उज्जैन

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

राष्ट्रीय सहारा

नई दिल्ली • शुक्रवार • 20 जून • 2025

www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

मुझे ये लगता है कि समय सभी चीजों को परिपक्व कर देता है; समय के साथ सभी चीजें उजागर हो जाती हैं; समय सत्य का प्रणेता है

-फ्रन्किओस राबेलैस

खामेनेई की खरी-खरी

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो खरी-खरी सुनाई है, ट्रंप उसी के हकदार थे। एक तो ट्रंप इस्राइल और ईरान के संघर्ष में जबरदस्ती अपनी नाक घुसा रहे हैं दूसरे वह इस्राइल के पक्ष में ऊटपटांग बयान देकर ईरान को धमका और चिढ़ा रहे हैं। किसी भी संप्रभु राष्ट्र का नेता ऐसे हालात में वही करेगा जो खामेनेई ने किया है। उन्होंने आत्मसमर्पण करने की ट्रंप की नसीहत को खारिज कर दिया और उल्टे चेतावनी दे डाली कि संघर्ष में अमेरिका की किसी भी कूद-फांद से उसे ही अपूरणीय क्षति होगी। हालांकि इस्राइल अमेरिका की मदद के बल पर ही सीनाजोर बना हुआ है। ट्रंप ने एक ही दिन पहले ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण

करने को कहा था। इससे भी बढ़कर उन्होंने कहा था कि खामेनेई को मारने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। ये सब कौन बर्दाश्त करता। तकनीकी रूप से ईरान कितना ही कमजोर हो, लेकिन इस्राइल की बेजा हरकतों का मुकाबला तो वह कर ही रहा है। इसी कारण से नेतन्याहू बिलबिला रहे हैं और चाहते हैं कि अमेरिका इस युद्ध में कूद जाए। ट्रंप हैं कि रोज बयान बदलकर ही ईरान को झुका लेना चाहते हैं। ईरान को धमकाने के लिए अमेरिका ने इस क्षेत्र में कुछ और युद्धक विमान भेजे हैं। खामेनेई ने ट्रंप के धमकी भरे और बेतुके बयानों को खारिज करते हुए कहा इस तरह की धमकियां समझदारी नहीं है। सीधे अमेरिकियों को संदेश देते हुए खामेनेई ने चेताया कि अमेरिका की किसी भी सैन्य भागीदारी से क्षेत्र में पूर्ण युद्ध छिड़ जाएगा और उसे ही अपूरणीय क्षति होगी। लगता है इस मामले में अलग थलग पड़े ईरान के पक्ष में अरब देशों में एकजुटता की सुगबुगाहट होने लगी है। इसी कड़ी में इराक ने क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए इस्तांबुल में होने वाले इस्लामिक सहयोग संगठन सम्मेलन के दौरान अरब देशों के विदेश मंत्रियों की आपातकालीन बैठक बुलाने का आह्वान किया है। प्रस्तावित बैठक का उद्देश्य तेजी से बदल रहे घटनाक्रमों के मद्देनजर अरब देशों की स्थिति में समन्वय करना और साझा जिम्मेदारी की भावना के साथ मौजूदा चुनौतियों से निपटना है। हालांकि अमेरिका की चालबाजियों को देखते हुए अरब और इस्लामिक देशों की एकजुटता बहुत दूर की कौड़ी है। युद्ध के छठे दिन ईरान और इस्राइल के बीच महत्त्वपूर्ण संस्थानों पर हमले का सिलसिला जारी है।

दुखी न करे वसूली

केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स के हवाले से सालाना फास्टैग पास की घोषणा की। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा-परेशानीमुक्त राजमार्ग यात्रा की दिशा में परिवर्तनकारी कदम के रूप में तीन हजार की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास पेश कर रहे हैं, जिसकी वैलिडिटी साल भर या दो सौ यात्राओं के लिए होगी। यह सुविधा बहरहाल विशेषकर कार, जीप व वैन जैसे गैर-वाणिज्यक निजी वाहनों के लिए है। जिसे चालू करने या रिन्यूअल के लिए राजयात्रा-एप के आलावा नेशनल हाई-वे अथोरिटी ऑफ इंडिया व मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाई-वे की आधिकारिक वेबसाइटों पर जल्द ही लिंक की सुविधा दी जाएगी। राष्ट्रीय

राजमार्ग पर नियमित या रोजाना यात्रा करने वालों को टोल क्रास करने में दस हजार रुपये से अधिक खर्चने पड़ते थे। जो अब तीन हजार में सीमित हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस व्यवस्था को पंद्रह साल के लिए भी लागू किया जा सकता है, जिसमें एकमुश्त तीस हजार रुपये खर्चने होंगे। इससे समय बचेगा और लंबी कतारों से मुक्ति मिल सकती है। साठ किलोमीटर के दायरे के निवासियों को सहूलियत होगी तथा ड्राइवरों-टोलकर्मियों के दरम्यान होने वाली झड़पों को रोका जा सकेगा। फास्टैग सरकार द्वारा चालू किया गया इलेक्ट्रॉनिक स्टीकर है, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप लगी होती है। इसे गाड़ी के शीशे यानी विंडस्क्रीन पर चिपकाया जाता है। टोल प्लाजा से गुजरते हुए बगैर रुके टोल शुल्क का ऑटोमैटिक भुगतान हो जाता है। 15 फरवरी 2021 से देश के सभी चार पहिया वाहनों के लिए इसे अनिवार्य किया जा चुका है। अमेरिका, आस्ट्रेलिया व दुबई में इसी तर्ज पर टोल का भुगतान होता है। इससे न सिर्फ ईंधन व वक्त की बचत होती है बल्कि सरकारी खाते में सीधा धन जाता है। टोल की चोरी पर काफी हद तक काबू किया गया है। आने वाले समय में उम्मीद है कि वाहनों के निर्माण के साथ ही ऐसी तकनीक भी जोड़ी जा सके, जिससे टोल सिस्टम पूरी तरह ऑटोमैटिक हो जाए। बहरहाल उम्मीद करनी चाहिए कि इस नई व्यवस्था से सरकार एकमुश्त धन ही एकत्र न करे, बल्कि वाहन चालकों की सुविधाओं का ख्याल रखे व अड़चनों से छुटकारा दिलाए।

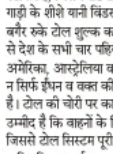

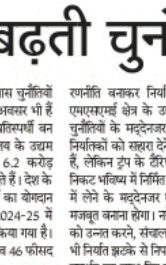

प्लास्टिक का चलन/अर्चना कुमारी

दुनिया भर के लिए मुसीबत

आधुनिक जीवन में प्लास्टिक एक अनिवार्य तत्व बन चुका है। यह सस्ता, टिकाऊ और बहुपयोगी होता है, लेकिन यही प्लास्टिक आज हमारे पर्यावरण के लिए एक गंभीर संकट बन चुका है। प्लास्टिक प्रदूषण विश्व स्तर पर चिंता का विषय है और यह न केवल भूमि को बल्कि जल और वायु को भी प्रदूषित कर रहा है। इतना ही नहीं यह प्रदूषण मनुष्यों, पशुओं, समुद्री जीवों और सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहा है। यही वजह है कि आज दुनियाभर के लिए प्लास्टिक कचरा बड़ी मुसीबत बन चुका है।

विश्व स्तर पर हर वर्ष लगभग 400 मिलियन टन यानी चार करोड़ लाख टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जो पिछले दो दशकों में तेजी बढ़ा है। इनमें से लगभग 80 लाख टन प्लास्टिक समुद्रों में पहुंचता है, जिससे लगभग 700 प्रजातियों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। वहीं हमारा देश भी अकेले लगभग 56 लाख टन टन प्लास्टिक कचरा प्रतिवर्ष पैदा कर रहा है,जिसका मिट्टी की ताकत पर बुरा असर पड़ने के साथ ही जलवायु पर प्रतिकूल असर साफ तौर से देखा जा रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण एक अनसुनी बात नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में जो कुछ अधिक स्पष्ट हुआ है, वह है जलवायु परिवर्तन के साथ इसका बढ़ता हुआ संबंध। यह ऐसे समय में चिंता का विषय बन गया है जब दुनिया जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते मौसम की घटनाओं का सामना कर रही है। बीते दो दशकों में ये स्पष्ट हुआ है कि वैश्वीकरण की नवउदारवादी और निजीकरण ने हमारे सामने बहुत-सी चुनौतियां खड़ी कर दी है, जिससे आर्थिक विकास के मॉडल लड़खड़ाने लगे हैं। सर्वविदित है कि इंसान व प्रकृति के बीच गहरा संबंध है। इंसान के लोभ, सुविधावाद एवं तथाकथित विकास की अवधारणा ने पर्यावरण का भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण न केवल नदियां, वन, रेगिस्तान, जलस्रोत सिकुड़ रहे हैं बल्कि ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। कभी वरदान समझा जाने वाला प्लास्टिक आज दुनिया के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। जलवायु परिवर्तन पर प्लास्टिक उत्पादन और निपटान का प्रभाव एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे में न केवल प्रभावी नीति निर्माण, बल्कि वैश्विक सहयोग, तकनीकी नवाचार और जन-भागीदारी की भी आवश्यकता है। वरना वह दिन दूर नहीं जब प्लास्टिक का जहर हमारी अगली पीढ़ियों की सांसों तक पहुंच जाएगा।

निशाने पर हिन्दू संस्कृति

नेपाल

प्रो. सतीश कुमार

नेपाल की राजनीति जिस तरीके से हिचकोले ले रही है उससे आम समुदाय अत्यंत हताश और विक्षुब्ध है। 2008 के बाद से 13 सरकार बदल चुकी है। प्रधानमंत्री पद म्यूजिकल चेयर की तरह बन गया है, लेकिन जबसे ओली पुनः प्रधानमंत्री 2024 में बने हैं उसके बाद से नेपाल निरंतर समस्याओ से घिरता जा रहा है।

अंदरूनी विखंडन और रस्साकसी और गंभीर बन गई है। नेपाल के भीतर हिन्दू संस्कृति बाहरी ताकतों के निशाने पर है। क्रिश्चियन पावर लॉबी हावी है, सत्ता संतुलन का खेल पैसो पर खेला जा रहा है। मुस्लिम आबादी अप्राकृतिक ढंग से बढ़ती जा रही है। 30 साल पहले मुस्लिम आबादी 1 प्रतिशत से भी कम थी, आज 5 प्रतिशत से ऊपर पहुंच चुकी है। रोहिंग्या समुदाय के लोग भी काठमांडू शहर के भीतर देखे जा सकते हैं। बहुत कुछ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हो रहा है तो बहुत कुछ राजनीतिक साजिश के रूप में देखा जा सकता है। इस डेमोग्राफिक बदलाव से सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक आधार कमजोर बन रहा है। साथ ही राजनीतिक और आर्थिक संकट भी पनप रहा है। नेपाल को देखने और समझने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि हिन्दू संस्कृति की मजबूती के बिना बुनियादी समस्याओं का हल ढूंढ पाना शायद संभव नहीं हो पाएगा। प्रचंड, जो जनक्रांति के नायक रहे हैं, राजशाही से माओवादी व्यवस्था को नेपाल में स्थापित करने के सबसे महत्त्वपूर्ण कड़ी थे, उनके शब्द और सुर भी सनातन संस्कृति की बात करते हैं। उनके शब्दों में 'सनातन संस्कृति नेपाल की आत्मा है, उसके बिना नेपाल की अवधारणा अधूरी है।

यही संस्कृति भारत और नेपाल को एक साथ जोड़ती है। दुनिया में दो देश के संबंध ऐसे नहीं मिलेंगे जो भारत और नेपाल के बीच है।' नेपाल की संस्कृति का विघटन मुस्लिम और ईसाई समुदाय के पसरते पैर की वजह से हो रहा है। नेपाल में ईसाई समुदाय के 'दबदबा' पिछले कुछ दशकों में प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो नेपाल में एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का विषय है। नेपाल की 2021 की जनगणना के अनुसार, देश में ईसाई आबादी कुल जनसंख्या का 1.76 फीसद है, जो लगभग 5,12,313 लोग हैं। यह संख्या पहली नजर में बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन इसकी वृद्धि दर बहुत तेज है। 2011 की जनगणना में ईसाई आबादी सिर्फ 1.4% थी। 1961 में नेपाल में केवल 458 ईसाई थे। नेपाल में मुस्लिम आबादी में वृद्धि देखी जा रही है। 2021 की जनगणना के अनुसार, नेपाल में लगभग 15 लाख मुस्लिम हैं, जो कुल जनसंख्या का 5.09% हैं। 2011 में यह आंकड़ा 4.39% था,

यानी एक दशक में 0.70% की वृद्धि हुई है। अधिकांश मुस्लिम आबादी तराई क्षेत्र में रहती है, जबकि कुछ समुदाय काठमांडू, गोरखा और पश्चिमी पहाड़ियों में भी बसे हुए हैं। नेपाल में इस्लाम तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, और कुछ अनुमान बताते हैं कि 2050 तक मुस्लिम आबादी 7% तक पहुंच सकती है। नेपाल में बढ़ती मुस्लिम आबादी भारत के लिए सुरक्षा और रणनीतिक चिंताओं का कारण बन रही है। भारत की खुफिया एजेंसियां इस जनसांख्यिकीय बदलाव पर नजर रख रही हैं, खासकर इंडो-नेपाल सीमा के पास।

आंकड़ों का खेल लोकतंत्र की सबसे महत्त्वपूर्ण कड़ी है। विशेषकर नेपाल जैसे देश में जो पिछले 15 वर्ष पहले ही लोकतंत्र की डगर पर चलना सीखा है। नेपाल की प्रतिनिधि सभा में कुल 275 सीटें होती हैं, जिनमें से 165 सीटें प्रत्यक्ष चुनाव से और 110 सीटें आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर तय होती हैं। नेपाली कांग्रेस 88 सीटें, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 79 सीटें, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) 32 सीटें, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 21 सीटें, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी 14 सीटें। मिली-जुली सरकार की चूले पहले से हिल रही थी, अब और डगमगा रही है। क्या इस बात कि विवेचना नहीं होनी चाहिए कि भारत के लिए कौन ज्यादा सार्थक प्रधानमंत्री हो सकता है-ओली या प्रचंड? ओली के कार्यकाल में भारत-नेपाल संबंधों में तनाव देखा गया था, खासकर सीमा विवाद के मुद्दे पर। उन्होंने नेपाल का नया नक्शा संसद में पारित कराया, जिसमें भारत के कुछ क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। ओली का झुकाव चीन की ओर अधिक रहा है, जिससे भारत-नेपाल संबंधों में कई बार असहजता आई है।

भारत के लिए प्रचंड अधिक व्यावहारिक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन नेपाल की आंतरिक राजनीति और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखना जरूरी है। पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' माओवादी नेता हैं, जिन्होंने नेपाल की राजशाही समाप्त करने और देश को गणतंत्र बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विचारधारा वामपंथी और धर्मनिरपेक्ष रही है। हालांकि नेपाल में हिन्दू धर्म का प्रभाव बहुत गहरा है और प्रचंडा ने राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए हिन्दू समुदाय के प्रति नरम रुख अपनाया है। उन्होंने भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की है और नेपाल में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने की बात कही है। देश का नेतृत्व वर्तमान में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली कर रहे हैं, जो जुलाई 2024 में नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर बनी गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री हैं। समझौते के तहत, ओली एक निश्चित अवधि के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे, जिसके बाद नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा शेष कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे।

इस तरह के सत्ता के चक्रीय हस्तांतरण ने दीर्घकालिक नीति निर्माण और शासन की प्रभावशीलता पर चिंताएं बढ़ा दी हैं। सरकारों का बार-बार बदलना आम बात हो गई है, जिससे देश के विकास और प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई है। ओली की मौजूदा सरकार भी आंतरिक विरोधाभासों और सत्ता-साझाकरण की मजबूरियों से जूझ रही है। संक्षेप में, नेपाल एक जटिल और चुनौतीपूर्ण राजनीतिक दौर से गुजर रहा है। एक तरफ नाजुक गठबंधन सरकार को स्थिरता बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ सड़कों पर बढ़ता जनाक्रोश और राजशाही की वापसी की मांग एक गंभीर दबाव बना रही है। आने वाले समय में यह देखना महत्त्वपूर्ण होगा कि ओली सरकार इन बहुआयामी चुनौतियों से कैसे निपटती है।

(लेख में विचार निजी हैं)

> सत्ता के चक्रीय हस्तांतरण ने दीर्घकालिक नीति निर्माण और शासन की प्रभावशीलता पर चिंताएं बढ़ा दी हैं। सरकारों का बार-बार बदलना आम बात हो गई है, जिससे देश के विकास और प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई है। ओली की मौजूदा सरकार भी आंतरिक विरोधाभासों और सत्ता-साझाकरण की मजबूरियों से जूझ रही है। संक्षेप में, नेपाल एक जटिल और चुनौतीपूर्ण राजनीतिक दौर से गुजर रहा है

आंवला स्क्वैश सभी के लिए गुणकारी

- आंवला से बने पेय पदार्थ यानी जूस (आंवला स्क्वैश) ताजे आंवले को धोकर, बीज हटा कर और रस निकाल कर तैयार किया जाता है। इसमें आम तौर पर खांड (कच्ची चीनी) या चीनी मिलाई जाती है, ताकि इसका खट्टा-कसैला स्वाद संतुलित हो सके
- आंवला स्क्वैश में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स रोग-प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करते हैं। कोलेजन उत्पादन बढ़ाते हैं, जो त्वचा को चमकदार बनाता है और झुर्रियां कम करता है
- हालांकि मधुमेह रोगियों को ध्यान रखना चाहिए कि आंवला स्क्वैश में शुगर मौजूद होती है। उसी के अनुसार उन्हें इसका सेवन करने में सावधानी बरतनी चाहिए

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

लोग छुट्टियां मनाने पहलगाम पहुंचे और गोलियों से भून डाले गए। लोग बेंगलुरू में जीत का जश्न मनाने में मशगूल थे कि भगदड़ में मारे गए। लोग कुंभ नहाने गए और भगदड़ में मारे गए। लोग मुंबई में ट्रेन में यात्रा करते में गिर कर मारे गए। अहमदाबाद में विमान क्रैश हुआ तो उसमें सवार यात्री मारे गए। इतनी मनहूसियत? आखिर, भारत में यह हो क्या रहा है?

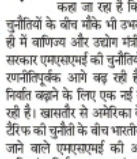

रोहिणी सिंह, पत्रकार@rohini_sgh

एमएसएमई की बढ़ती चुनौतियां

मुद्दा **डॉ. जयंतीलाल भंडारी**

इन दिनों भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि भारत में एमएसएमई की चुनौतियों के बीच मौके भी उभरकर दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार एमएसएमई की चुनौतियों को दूर करने की डगर पर रणनीतिपूर्वक आगे बढ़ रही है। सरकार एमएसएमई से निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई स्कीम लाने पर विचार कर रही है। खासतौर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप से टैरिफ की चुनौती के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले एमएसएमई की अमेरिकी बाजार पर निर्भर अधिकांश निर्यातक इकाइयां अमेरिकी खरीदारों द्वारा छूट की नई मांग और अनुबंधों पर नये सिरे से बातचीत के अलावा भुगतान में देरी जैसी चुनौतियों के मद्देनजर एमएसएमई के बचाव के लिए सरकार का रणनीतिक सहयोग जरूरी माना जा रहा है।

हाल ही में प्रकाशित सिडबी की रिपोर्ट के मुताबिक अभी एमएसएमई के लिए सरल कर्ज की प्राप्ति एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। एमएसएमई की क्रेडिट मांग व पूर्ति में 30 लाख करोड़ रुपये का अंतर है। मांग के मुताबिक लोन मिलने पर एमएसएमई के तहत 5 करोड नये रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटे उद्योगों को जरूरत के मुताबिक क्रेडिट, तकनीकी कौशल तथा विकास एवं अनुसंधान के क्षेत्र में मदद मिल जाए तो एमएसएमई रोजगार और आर्थिक विकास का बड़ा साधन बन सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि इस समय नये व्यापार युग के बदलाव के दौर में भारत के एमएसएमई के पास चुनौतियों के बीच दुनिया में आगे बढ़ने के ऐतिहासिक अवसर भी हैं और ये उद्योग वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। गौरतलब है कि एमएसएमई मंत्रालय के उद्यम पोर्टल पर इस साल मार्च तक पंजीकृत 6.2 करोड़ एमएसएमई 25.95 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई का योगदान करीब 30 फीसद है। एमएसएमई से वर्ष 2024-25 में करीब 12.39 लाख करोड़ रुपये का निर्यात किया गया है। देश से निर्यात किए गए कुल उत्पादों में से करीब 46 फीसद

उत्पाद एमएसएमई क्षेत्र से है। ऐसे में भारत ने हाल ही इंग्लैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) किया है और अमेरिका के अलावा अन्य कई प्रमुख देशों के साथ भी द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के पूर्ण होने पर एमएसएमई की भूमिका महत्त्वपूर्ण होगी। अतएव नये अवसरों का लाभ उठाने के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहन देकर मजबूत बनाना जरूरी है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि टैरिफ वार से एमएसएमई क्षेत्र को जो झटका लग रहा है, उस झटके से एमएसएमई के उबारने के लिए जहां एक ओर सरकार के द्वारा एमएसएमई के समक्ष दिखाई दे रही चुनौतियों के समाधान के लिए रणनीति बनाकर निर्यातकों को सहारा देना होगा, वहीं एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमियों और निर्यातकों को भी नई चुनौतियों के मद्देनजर तैयार होना होगा। निश्चित रूप से निर्यातकों को सहारा देने के सरकार के ये कदम सराहनीय हैं, लेकिन ट्रंप के टैरिफ तूफान का मुकाबला करने और निकट भविष्य में निर्मित होने वाले उभरते अवसरों को मुट्ठी में लेने के मद्देनजर एमएसएमई को हरसंभव उपाय से मजबूत बनाना होगा। नये सिरे से एमएसएमई की क्षमताओं को उन्नत करने, संचालन को सुव्यवस्थित करने तथा किसी भी निर्यात झटके से निपटने के लिए एमएसएमई को नीतिगत समर्थन का लाभ दिए जाने के प्रयासों में तेजी लाना होगी। इससे भारत की एमएसएमई उतार-चढ़ाव भरे सफर को आगे बढ़ा सकेगी।

इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी के लोग अब नौकरी की बजाय खुद का उद्योग-व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं। ऐसे में एमएसएमएई उनके लिए महत्त्वपूर्ण विकल्प है। जरूरी है कि देश के कोने-कोने में, प्रदेशों और जिला स्तर पर एमएसएमई कानक्लेव आयोजित किए जाएं और ऐसे मंच पर एमएसएमई से जुड़े कारोबारी, उद्योग विशेषज्ञ और नीति बनाने वाले लोग एकत्रित होकर एमएसएमई के नये दौर के लिए नई पीढ़ी का जन जागरण करें। नई पीढ़ी को एमएसएमई के उत्पादों और सेवाओं से परिचित कराएं। नये ग्राहकों से मिलाएं और एमएसएमई को आगे बढ़ाने के नये तरीके सिखाएं। उम्मीद करें कि एमएसएमई की बहुआयामी उपयोगिता के मद्देनजर सरकार एमएसएमई के समक्ष दिखाई देने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए तत्परता के साथ रणनीतिपूर्वक आगे बढ़ेगी। उम्मीद करें कि देश में एमएसएमई से संबद्ध उद्यमी और निर्यातक अधिकतम प्रयासों से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करते हुए देश के छोटे उद्योग-कारोबार को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। वर्ष 2028 तक देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित देश बनाने में एमएसएमई की भूमिका अहम होगी।

आत्मा **श्रीराम शर्मा आचार्य**

आत्मा को कितना ही कुचला जाय वह न मरने वाली है और न हार मानती है। अनसुनी, उपेक्षित पड़ी रहने पर भी अंतरात्मा की विरोधी आवाज

उठती ही रहती है। दुष्कर्म करते समय जी धड़कता और पैर कांपते हैं। यह स्थिति कितनी ही दुर्बल क्यों न कर दी जाए, उसका अस्तित्व बना ही रहेगा और झंझट तब तक चलता ही रहेगा, जब तक दुष्प्रवृत्तियां उस घुसपैठ से अपना पैर वापस न लौटा लें। अंतर्द्वन्द्व जीवन की शांति और सुव्यवस्था को नष्ट करते हैं। प्रगतिपथ अवरुद्ध करते हैं और भविष्य को अंधकारमय बनाते हैं। पापों की परिणति से किसी भी बहाने बचा नहीं जा सकता। यह शारीरिक संविधान की सामान्य क्रिया पद्धति हुई। इसके अतिरिक्त समाजगत, प्रकृतिगत एवं ईश्वरीय व्यवस्था के और भी ऐसे कितने ही आधार हैं, जिनके कारण कुमार्गगामी को अपने दुष्कृत्यों के दण्ड अनेक प्रकार से भुगतने के लिए विवश होना पड़ता है। राजदण्ड की व्यवस्था इसीलिए है कि दुष्कर्मों की आवश्यक रोकथाम की जा सके और अनीति बरतने वालों को उनकी करतूतों का मजा चखाया जा सके। पुलिस, कचहरी, जेल, फांसी आदि की शासकीय दण्ड व्यवस्था का अस्तित्व मौजूद है। चतुरता बरतने पर भी लोग अक्सर उसकी पकड़ में आ जाते हैं और आर्थिक, शारीरिक, मानसिक दण्ड भुगतते हैं, बदनामी सहते और नागरिक अधिकारों से वंचित होते हैं। इतने पर भी पीछा नहीं छूटता। शारीरिक व्याधि और मानसिक आधि उन्हें घेरती है और तिल-तिल करके रेतने, काटने जैसा कष्ट देती है। शरीर पर मन का अधिकार है। अचेतन मन के नियंत्रण में आकुंचन-प्रकुंचन, निमेष-उन्मेष, श्वास-प्रश्वास, रक्त-संचार, ग्रहण-विसर्जन आदि अनेकों स्वचालित समझी जाने वाली गतिविधियां चलती हैं। चेतन मन की शक्ति से ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियां काम करती हैं। शरीर तभी तक जीवित है जब तक उसमें चेतना का अस्तित्व है। प्राण निकलते ही शरीर सड़ने और नष्ट होने लगता है। चेतना का केंद्र स्थान मस्तिष्क है। मन के रूप में ही हम चेतना का अस्तित्व देखते एवं क्रिया-कलापों का अनुभव करते हैं। यह संस्थान मनोविकारों से पाप-ताप एवं कल्मषों से विकृत होता है तो उसका प्रभाव शारीरिक आरोग्य पर भी पड़ता है और मानसिक संतुलन पर भी।

रीडर्स मेल

सराहनीय फैसला

खबर है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा एक वर्ष या 200 यात्राओं के लिए केवल 3 हजार रुपये का भुगतान लिया जाएगा, निजी वाहन चालकों के लिये निश्चित ही यह एक सुखद समाचार है, जहां घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही टोल टैक्स का मीटर घूमने लगता था वहीं प्रतिमाह यह खर्च मात्र 250 रुपये होगा, अभी किसी भी यात्रा पर निकलने से पहले जहां जनता को अपना फास्टैग रिचार्ज करना पड़ता है, परंतु नई नीति के लागू होने से इस झंझट से मुक्ति मिलेगी, यात्रा सुगम होगी और अन्य समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। हालांकि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी अपने कार्य और निर्णयों से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं पर इस बार मंत्रालय ने वाकई बेहद महत्त्वपूर्ण, समझदार और सुखद निर्णय लिया है, परंतु एक बात देश को पसोपेश में डाल रही है कि इस निर्णय के बाद एनएचएआई को अभी मिलने वाले टैक्स की अपेक्षा काफी कम टैक्स मिलेगा और विभाग की आय पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है, कमाई बढ़ाने को लेकर सरकार कुछ दिनों में कोई और सुझाव लेकर जनता के बीच आए।

मनोज पुरुषार्थी, मेरठ

बंद करना होगा प्लास्टिक का प्रयोग

आज पर्यावरण में प्लास्टिक की वजह से जहर घुलता जा रहा है। हल्का और सस्ता होने की वजह से प्लास्टिक का प्रयोग हर तरफ बखूबी हो रहा है। इससे होने वाले प्रदूषण और इसके निस्तारण में होने वाली दिक्कतों के बारे में सबको पता है। फिर भी लोग प्लास्टिक का प्रयोग करने से पीछे नहीं हट रहे। ऊपर से सड़कों, रास्तों, नदी नालों, व सार्वजनिक स्थलों पर प्लास्टिक की बोतलें फेंक हम पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। पढ़-लिख और जागरूक होने के बावजूद और इससे होने वाले दुष्प्रभावों को जानते हुए भी लोग प्लास्टिक का प्रयोग बंद नहीं कर रहे हैं। सरकार को सख्ती से प्लास्टिक पर पाबंदी लगा पर्यावरण को बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझ सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुसरण करना चाहिए। आज अगर हम पर्यावरण को स्वच्छ और प्रदूषणरहित नहीं रखेंगे तो इसके दुष्परिणाम हमारे साथ-साथ भावी पीढ़ी को भुगतने पड़ेंगे।

अभिलाषा गुप्ता, मोहाली, चंडीगढ़

वर्दी की गरिमा गिराते पुलिस जवान

झारखंड के देवघर जिला अंतर्गत एसपी माइंस चितरा कोलियरी में आयोजित नौ दिवसीय महारुद्र यज्ञ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। मेला क्षेत्र में काफी पुलिस बलों की भी तैनाती की गई थी, जिसमें अधिकतर झारखंड ग्रामीण पुलिस (चौकीदार) के जवानों को लगाया गया था। पुलिस बलों की प्राथमिक भूमिका समाज में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने की है, परंतु मेला क्षेत्र में कुछ जवान वहां की व्यवस्था देखने के बजाय सोशल मीडिया पर रील बनाते हुए दिखे। सवाल यह है कि क्या सरकार ने उन्हें वर्दी लोगों की सुरक्षा के लिए दी है या फिर सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर लाइक्स, व्यूज बटोरने के लिए? वर्दी पहनकर ऑन ड्यूटी में रील बनाना न केवल अनुशासनहीनता का प्रतीक है, बल्कि यह वर्दी की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। वर्दी पहन कर रील्स बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

संदीप कुमार, मधुपुर, झारखंड

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 1209-1210, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। स्थानीय संपादक - रमेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 106

डॉलर बनाम रेनमिनबी

पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर पान गोंगशेंग ने एक बहु-ध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली तैयार करने की जोरदार वकालत की है। उन्होंने बुधवार को कहा कि किसी एक मुद्रा पर अत्यधिक निर्भरता दुनिया के लिए ठीक नहीं है। गोंगशेंग ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि दुनिया को डॉलर आधारित वैश्विक वित्तीय प्रणाली का विकल्प तैयार करना चाहिए। चीन अपनी मुद्रा रेनमिनबी (आरएमबी) को लगातार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। छह विदेशी बैंकों ने बुधवार को कहा कि वे स्विफ्ट भुगतान प्रणाली के विकल्प के रूप में चीन के क्रॉस-बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। यह तर्क दमदार है कि विश्व को सीमा पार भुगतान के लिए केवल एक मुद्रा या भुगतान प्रणाली पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। अमेरिकी की वर्तमान राजनीति एवं उसकी नीतिगत स्थिति को देखते हुए ऐसे विचार लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने हाल में कहा कि पूरे विश्वास के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि डॉलर का दबदबा आगे भी कायम रहेगा।

डॉनल्ड ट्रंप कई रूपों में अमेरिका को एक अनिश्चित दिशा में ले जा रहे हैं जिससे यह कहना मुश्किल है कि आगे हालात कैसे रहेंगे। उदाहरण के लिए ट्रंप ने दुनिया के अन्य देशों के साथ व्यापार का तौर-तरीका बदलने की ठान ली है। ट्रंप की नजर में किसी भी देश के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा स्वीकार्य नहीं है और इस स्थिति को बदलने का शुल्क सबसे सटीक हथियार है। उन्होंने दुनिया के देशों के लिए अमेरिका के साथ व्यापार समझौते करने के लिए 9 जुलाई की समय सीमा तय कर रखी है, जो अब नजदीक आ रही है। किंतु, अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि कितने व्यापार साझेदार देशों के साथ अमेरिका समझौता करेगा। हालांकि, यह तो साफ है कि शुल्क काफी अधिक होंगे और अमेरिका नियम-आधारित व्यापार व्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा चुका होगा। यह अनिश्चितता वास्तविक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। शुल्कों से जुड़ी अनिश्चितता के कारण फेडरल रिजर्व ने बुधवार को नीतिगत दरों में बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया। फेडरल रिजर्व के नए आर्थिक अनुमानों में कहा गया है कि वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति 3 फीसदी के आसपास रह सकती है। मार्च में व्यक्त अनुमान में इसके 2.7 फीसदी रहने की बात कही गई थी। फेडरल रिजर्व के अनुसार चालू वर्ष में अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 1.4 फीसदी की दर से बढ़ेगा। मार्च में जारी अनुमानों में यह दर 1.7 फीसदी रहने का जिक्र था। कमजोर होती आर्थिक वृद्धि दर और बढ़ती मुद्रास्फीति की आशंका ने अमेरिका के केंद्रीय बैंक को पशोपेश में डाल दिया है। ट्रंप प्रशासन का व्यापार पर रुख ही इसका एकमात्र कारण नहीं है। संस्थानों का अनादर भी काफी नुकसान पहुंचा रहा है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने नीतिगत दर पर निर्णय से पहले फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल को 'बेवकूफ व्यक्ति' करार दिया। केंद्रीय बैंक पर ट्रंप प्रशासन का दबाव बाजार को रास नहीं आया। इतना ही नहीं, अमेरिका की राजकोषीय सेहत भी बिगड़ गई है और आने वाले वर्षों पर उस पर भारी कर्ज चढ़ने की भी आशंका जताई गई है।

अमेरिका की वर्तमान स्थिति उत्साह एवं विश्वास को बढ़ावा नहीं दे रही है। भविष्य में व्यापार एवं पूंजी प्रवाह पर भी इसका असर दिखेगा। किंतु, इन बातों से चीन की मुद्रा रेनमिनबी के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर छाने की संभावना स्वतः मजबूत नहीं हो पाएगी। यह भी सच है कि चीन एक बड़ा व्यापारिक देश और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए कुछ द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यापार रेनमिनबी आधारित प्रणालियों में हो सकते हैं। हालांकि, रेनमिनबी के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बनने की राह में कम से कम दो बाधाएं हैं।

रेनमिनबी का मूल्य निर्धारण भी पिछले कई दशकों से अमेरिकी डॉलर से होता रहा है, जिसमें कड़े पूंजी नियंत्रण की अहम भूमिका रही है। ऐसा नहीं लगता कि चीन निकट भविष्य में पूंजी नियंत्रण से पीछे हट जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी मुद्रा के व्यापक इस्तेमाल होने के लिए जरूरी है कि उसका बेरोक-टोक कारोबार हो। दूसरा कारण यह है कि चीन अब भी मजबूत चालू खाता अधिशेष की स्थिति में है जिसका मतलब है दुनिया में कारोबार के लिए पर्याप्त रेनमिनबी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इसका इस्तेमाल ज्यादातर चीन की वस्तुएं खरीदने के लिए होता है। लिहाजा, अमेरिका और अमेरिकी डॉलर के भविष्य को लेकर चिंता जरूर जताई जा रही है मगर रेनमिनबी इस कमान को संभालने की स्थिति में नहीं है। आने वाले वर्षों में वैश्विक मौद्रिक प्रणाली अधिक बिखर सकती है जिसका नतीजा ऊंची लागत और बढ़ी अनिश्चितता के रूप में दिखेगा।

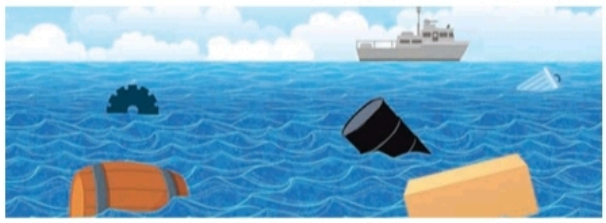

समुद्र की सेहत में सुधार के लक्ष्य

समुद्र की सेहत पर संयुक्त राष्ट्र के संकल्प स्वैच्छिक हैं। इसलिए भारत को अपने समुद्री हितों की रक्षा का रास्ता स्वयं तैयार करना होगा। बता रहे हैं श्याम सरन

इंसान भले ही जमीन पर रहते हैं लेकिन मानवता का मूल गहरे समुद्र में है। सन 1967 में जब दुनिया ऐतिहासिक समुद्री कानून पर बातचीत कर रही थी तब माल्टा के राजनयिक अरविड प्राडो ने कहा था, 'समुद्र ही वह कोख है, जहां से जीवन आया। महफूज रखने वाले इस समुद्र से ही जीवन निकला। हमारे खून और आंसुओं का खारापन अब भी हमारे शरीर में उस अतीत की निशानी हैं।'

हमें समुद्र से जोड़ने वाली गर्भनाल स्वयं जीवन का आधार तत्त्व है। पृथ्वी की आधी ऑक्सीजन समुद्र ही बनाते हैं। कुल कार्बन उत्सर्जन का 30 फीसदी समुद्र सोख लेते हैं। वातावरण के तापमान को ये कम करते हैं। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है। पृथ्वी की जलवायु को कायदे में रखने का काम अगर यह बंद कर दे तो इस ग्रह से जीवन खत्म होने में देर नहीं लगेगी।

समुद्र की सेहत ठीक करने की चिंता बहुत पुरानी है। द लॉ ऑफ द सी (समुद्र का कानून) पर दस्तखत तो 1982 में किए गए थे मगर यह लागू 1994 में किया गया। इसमें समुद्री वातावरण के संरक्षण से जुड़े प्रावधान थे। परंतु पहली विस्तृत और व्यापक योजना 2015 के सतत विकास के लक्ष्यों (एसडीजी-14) में पेश की गई, जिसमें दुनिया के महासागरों, सागरों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण तथा पर्यावरण अनुरूप इस्तेमाल की बात की गई। इसके तहत 2030 तक 10 लक्ष्य हासिल किए जाने हैं, जिनमें समुद्री प्रदूषण समाप्त करना, मछलियों का अत्यधिक शिकार बंद करना और समुद्र का अम्लीकरण रोकना आदि शामिल हैं। इनमें से कोई लक्ष्य दूर-दूर तक हासिल होता नहीं दिखता। इन लक्ष्यों पर हुई प्रगति की समीक्षा करने और इनका क्रियान्वयन बढ़ाने के इरादे से पहला संयुक्त राष्ट्र समुद्री सम्मेलन 2017 में न्यूयॉर्क में हुआ और दूसरा 2022 में लिस्बन में। मगर अभी तक निराशा ही हाथ लगी है।

स्वतंत्र गैर लाभकारी संस्था ओशनकेयर कहती है, 'लिस्बन 2022 के बाद से महासागरों की हालत कई संकेतकों पर बिगड़ती दिखी है और सरकारें कोई ठोस काम किए बगैर जबानी जमाखर्च में लगी रहती हैं। 5-10 साल बाद तो महासागरों के लिए कुछ कारगर करने का मौका ही नहीं रह जाएगा।' संयुक्त राष्ट्र के इन सम्मेलनों में बातचीत नहीं होती और इनकी घोषणाएं स्वैच्छिक संकल्प होती हैं। देशों के सामने इन्हें लागू करने का कोई प्रोत्साहन ही नहीं होता क्योंकि इनका अनुपालन कराने के लिए कोई कानूनी प्रावधान ही नहीं है।

तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन फ्रांस और कोस्टारिका ने साथ मिलकर 9 से 13 जून तक नीस में आयोजित किया। इस समय भूराजनीति खेमों में बंटी है और डॉनल्ड ट्रंप का अमेरिका बहुपक्षीयता को नकार चुका है, इसलिए इस माहौल में सम्मेलन को कामयाब माना जा सकता है। इसमें 170 से अधिक देशों के प्रतिनिधि थे और 60 देशों के प्रमुखों तथा सरकारों ने इसमें हिस्सा लिया। इससे राजनीतिक घोषणा और नीस ओशन एक्शन प्लान निकलकर आया। इसमें सरकारों के साथ वैज्ञानिकों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और नागरिक समाज के स्वैच्छिक संकल्प शामिल हैं। इससे भी अहम बात यह है कि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता या उच्च सागर संधि को जल्द स्वीकार करने तथा अगस्त में जिनेवा में होने वाले अंतिम दौर में वैश्विक प्लास्टिक्स संधि पर वार्ता संपन्न करने का संकल्प लिया गया है। समुद्र की सेहत को कानूनी सुरक्षा मुहैया कराने के लिहाज से ये दोनों अहम हैं। उच्च सागर संधि महासागरों के करीब दो-तिहाई हिस्से को बचाएगा, जो किसी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है और सभी समुद्री जीव खतरे में आ गए हैं। अब तो यह माइक्रोप्लास्टिक के रूप में हमारे भोजन में पहुंच रहा है, जिससे कैंसर हो सकता है और इंसानों तथा जीवों के लिए बराबर नुकसानदेह है। अनुमान है कि हर साल दुनिया का 18 से 20 फीसदी प्लास्टिक कचरा महासागरों में पहुंच जाता है। अंकुश नहीं लगाया गया तो 2040 तक 370 लाख टन प्लास्टिक कचरा महासागर में मिल जाएगा। लगातार फेंका जा रहा दूसरा कचरा और नुकसानदेह पदार्थ जोड़ दें तो कह सकते हैं कि समुद्र दुनिया के कूड़ाघर बन गए हैं। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन महासागर के संरक्षण के लिहाज से भी महत्त्वपूर्ण है। कनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क में 30 फीसदी समुद्री इलाके को संरक्षित करने का संकल्प है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन ने भी कहा है कि 2030 तक यह लक्ष्य हासिल करना बहुत जरूरी है। नीस में सहमति से स्वीकार की गई राजनीतिक घोषणा बताती है कि महासागरों की बिगड़ी सेहत पर कितनी अधिक चिंता है।

संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से पहले करीब 2,000 अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने अपनी वन ओशन साइंस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और चेतावनी दी। उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर साबित कर बताया कि समुद्र का बिगड़ता पारितंत्र कैसे पूरी पृथ्वी के अस्तित्व के लिए संकट खड़ा कर रहा है। यह सही समय पर की गई बहुत जरूरी पहल थी। हमेशा की तरह समस्या यह है कि ऐसी जल्दबाजी कार्य योजना के लिए जरूरी रकम जुटाने में नहीं दिखती। धीमी पड़ती विश्व अर्थव्यवस्था में रकम जुटाना और भी चुनौती भरा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि समुद्री संरक्षण के लिए जो रकम उपलब्ध हो रही है, उसमें 15.8 अरब डॉलर की और जरूरत है। मगर हमारे सामने मौजूद लक्ष्यों को देखते हुए लगता है कि कमी इससे कहीं ज्यादा है।

कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने छह बिंदुओं वाली समुद्र संरक्षण योजना पेश की, जिसमें समुद्री शोध बढ़ाना और समुद्र नीति के लिए विज्ञान आधारित हल शामिल थे। साथ ही समुद्र के संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार करना और समुद्री पारितंत्र की सुरक्षा करना, बेकार जल के कारगर प्रबंधन के जरिये समुद्र का प्रदूषण कम करना तथा देसी ज्ञान की मदद से समुदायों को सशक्त बनाना एवं समावेशी और समतापूर्ण समुद्री प्रशासन सुनिश्चित करना जैसी बातें इसमें शामिल थीं। इनमें से कई बिंदु अंतिम दस्तावेज में भी नजर आए।

भारत एक समुद्री देश है और हमारे यहां 22 लाख वर्ग किलोमीटर का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है। इसके अलावा महाद्वीप में करीब 12 लाख वर्ग किलोमीटर इलाका और है। हमारी तट रेखा 7,000 किलोमीटर से लंबी है। वैश्विक समुद्री प्रशासन व्यवस्था भारत के लिए बहुत मायने रखती है। उसके आर्थिक और सामुद्रिक हितों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। समुद्री सीमाएं जमीनी सीमाओं से अलग होती हैं और उनका उल्लंघन आसानी से हो जाता है। समुद्र के संरक्षण के लिए अपने समुद्री पड़ोसियों और साझेदारों के साथ करीबी सहयोग जरूरी होता है।

भारत संरक्षित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान पार्क के तहत आने वाले इलाके को बढ़ाने की भी सोच सकता है। फिलहाल केवल चार ऐसे क्षेत्र हैं- कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन और वांडूर।

हमें पूर्व में खराब होते गंगा डेल्टा को सुधारने पर भी विचार करना चाहिए। अब वह मृत क्षेत्र है, जहां जलीय जीवन खत्म हो चुका है। इसका कारण औद्योगिक गतिविधियां हैं, जिनसे उत्पन्न विषैले रसायन पानी में मिल गए हैं। जमीन और समुद्र की प्रणालियां आपस में जुड़ी हुई हैं और इन्हें एक साथ देखा जाना चाहिए। भारत को ऐसी पारिस्थितिकी रणनीति की आवश्यकता है जो इस जुड़ाव को समझे।

(लेखक विदेश सचिव और जलवायु परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री के विशेष दूत रह चुके हैं)

केंद्रीय बैंकिंग की कामयाबी के लिए जरूरी है संतुलन

बैंकिंग साख
तमाल बंद्योपाध्याय

करीब दशक भर पहले सितंबर 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रीपो दर में 50आधार अंकों की कटौती की थी। यह अनुमान से दोगुनी कटौती थी। यह तीन साल की सबसे बड़ी कटौती थी और इसके बाद रीपो दर घटकर 6.75 फीसदी रह गई। यह साढ़े चार सालों का न्यूनतम स्तर था।

मौद्रिक नीति के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान किसी ने तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन से पूछा कि क्या वह सांता क्लॉज की भूमिका निभा रहे हैं। जवाब में उन्होंने कहा, 'मैं नहीं जानता आप मुझे क्या बुलाना चाहते हैं...सांता क्लॉज... या आप मुझे हॉक कहना चाहते हैं...मैं नहीं जानता। मेरा नाम रघुराम राजन है और मैं जो करता हूं, वह करता हूं।'

50 आधार अंकों की कटौती के बारे में उन्होंने कहा, 'हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि टिकाऊ और वृद्धि शब्द साथ रहें। दोनों अहम हैं। यही वजह है कि हमने अपने पास मौजूद गुंजाइश का इस्तेमाल किया। पर मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा आक्रामक हैं। हम कोई दीवाली बोनस नहीं बांट रहे थे।'

ताजा मौद्रिक नीति में भी 50 आधार अंकों की कटौती की गई जो उम्मीद से दोगुनी थी। इतना ही नहीं नकद आरक्षित अनुपात में भी कटौती की गई और नीतिगत रुख को समायोजन से तटस्थ कर दिया गया। अप्रैल में पिछली नीति की घोषणा करते समय रिजर्व बैंक के मौजूदा गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा था, 'मैं संजय हूं, महाभारत का संजय नहीं जो भविष्य की दरों को लेकर कदमों का अनुमान जता सकूं।'

मल्होत्रा के पास दूर की चीजें देखने की दिव्य दृष्टि नहीं है। अतीत में हमें दोनों तरह के गवर्नर देखने को मिले हैं। एक तो वे जो वही करते थे जो जरूरी होता था और दूसरे वे जो भविष्य में कदम उठाए जाने के लिए आंकड़ों की प्रतीक्षा करते। जून की मौद्रिक नीति के बाद सवाल यह है कि क्या यह सही रुख है? या फिर क्या एक केंद्रीय बैंकर को सावधान रहना चाहिए और अपने सारे पत्ते नहीं खोलने चाहिए? खासतौर पर तब जबकि दुनिया भर में तमाम अनिश्चितताएं हैं। इस खेल के कोई नियम नहीं हैं। ऐसे भी कई ऐसे केंद्रीय बैंकर रहे हैं जो सावधानी से छोटे कदम उठाते हैं। वहीं ऐसे भी बैंकर रहे हैं जो वर्तमान को ध्यान में रखते हुए नीतिगत कदम उठाते हैं। मल्होत्रा दूसरी श्रेणी के हैं। नीतिगत घोषणा के कुछ दिन बाद हमें पता चला कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल के 3.2 फीसदी की तुलना में मई में घटकर 2.8 फीसदी रह गई। यह 75 महीने का न्यूनतम स्तर है। कई लोग कहते हैं कि जून में यह 2.5 फीसदी रह सकती है। क्या महज दो महीनों में रुख में बदलाव मुद्रास्फीति के आगामी आंकड़ों के साथ तालमेल वाला होगा।

इसी समय खाद्य कीमतों में गिरावट के दौरान ही वर्तमान अनिश्चित माहौल में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा खुदरा मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पर विपरीत असर डाल सकता है। यह सही है कि वृद्धि-मुद्रास्फीति का नया गणित वृद्धि को सहारा देने के लिए ब्याज दरों में कटौती की मांग करता है, लेकिन किसी रिजर्व बैंक गवर्नर को यह कहते हुए कम ही सुना जाता है, 'फरवरी 2025 के बाद कम अंतराल में नीतिगत रीपो दर को 100 आधार अंक तक कम करने के बाद मौजूदा हालात में मौद्रिक नीति के पास वृद्धि को सहारा देने की सीमित गुंजाइश है।' यहां वह अहम सवाल आता है कि केंद्रीय बैंकिंग में खामोशी और बातचीत बनाम कार्रवाई में से क्या होना चाहिए। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि केंद्रीय बैंकरों को अपनी बात पर अमल करना चाहिए क्योंकि विश्वसनीयता ही उनकी पूंजी है। उनकी कथनी और करनी में भेद नहीं रह सकता। अगर ऐसा हुआ तो बाजार उन पर भरोसा नहीं करेगा। ऐसे में मुद्रा की कीमत बढ़ाना और बॉन्ड यील्ड में कमी भी एक स्वीकार्य दस्तूर है। मल्होत्रा खुलकर कह चुके हैं कि मौद्रिक नीति के पास वृद्धि को सहारा देने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। ऐसे में क्या वृद्धि को गति देने का काम सरकार के जिम्मे है और दरों में आगे कटौती की गुंजाइश नहीं है। केंद्रीय बैंकिंग में संचार बहुत अहम है। समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मल्होत्रा ने साफ किया कि वह बातें करने में यकीन नहीं करते बल्कि कार्रवाई में करते हैं। यूरोपीय केंद्रीय बैंक की क्रिस्टीन लेगार्ड की अक्सर आलोचना की जाती रही है कि वे अत्यधिक सतर्क रहती हैं। कई बार उनके शब्दों में बाजार को गति देने की ताकत नहीं रहती। बैंक ऑफ जापान के गवर्नर काज़ुओ उएदा भी संचार में बहुत सावधानी बरतते हैं क्योंकि छोटा सा संकेत भी येन या बॉन्ड में भारी अस्थिरता ला सकता है।

1980 के दशक में अमेरिकी फेड के तत्कालीन चेयरमैन पॉल वोल्कर ने नीतिगत दरें बढ़ाकर मुद्रास्फीति की कमर तोड़ दी थी। उन्होंने कहा था, 'मुझे जो सबसे अहम काम करना है वह है फेडरल रिजर्व की विश्वसनीयता बरकरार रखना।'

तो क्या कारगर रहता है? शायद बातों और कार्रवाई के बीच का संतुलन बेहतर होता है। केवल बातें करने वाला केंद्रीय बैंकर और बिना बाजार के जोखिम के लिए तैयारी किए केवल कार्रवाई करने वाला बैंकर, दोनों विश्वसनीयता को क्षति पहुंचाते हैं।

यहां बातें करने और काम करने वाले के बीच की लड़ाई नहीं है। आदर्श स्थिति में केंद्रीय बैंकरों को बाजार को तैयार करना चाहिए, पारदर्शी ढंग से अपने इरादे का संकेत देना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने कोई काम क्यों किया। मल्होत्रा ने ऐसा ही किया।

रिजर्व बैंक ने फरवरी में दरों में कटौती शुरू की थी। फरवरी के पहले सप्ताह उसने 25 आधार अंक की कमी करके रीपो दर 6.25 फीसदी किया और जून की नीति की पूर्व संध्या पर (तब दर 6 फीसदी थी क्योंकि अप्रैल में एक और बार 25 आधार अंक की कटौती की गई थी।) एक वर्ष के ट्रेजरी बिल के यील्ड में 100 आधार अंक की कमी आई। 10 साल के बॉन्ड की यील्ड करीब 30 आधार अंक कम हुई। दरों में अप्रत्याशित कटौती के बाद 10 साल की यील्ड करीब 10 आधार अंक घटी है।

यकीनन ओवरनाइट दरों में कमी आ रही है यानी दूसरे शब्दों में कहें तो संपूर्ण स्तर पर न सही लेकिन ट्रांसमिशन नजर आ रहा है। परंतु जैसा कि वे कहते हैं नीतिगत कदमों और उनके असर में थोड़ा अंतराल तो रहता है। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। लचीलापन बहुत अहम है क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से विकसित होती है। एक केंद्रीय बैंकर आज कुछ कहता दिख सकता है जबकि अगले दिन वह कुछ और करता नजर आ सकता है। इसकी वजह उसके आत्मविश्वास की कमी नहीं बल्कि आंकड़ों में बदलाव हो सकता है।

(लेखक जन स्मॉल फाइनैंस बैंक के वरिष्ठ सलाहकार हैं)

आपका पक्ष

भारत अपनी कूटनीतिक शक्ति का उपयोग करे

ईरान और इजरायल के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं और कई लोगों की मौत भी हुई है। अब पश्चिम एशिया में चल रहा यह युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं है, बल्कि इसका व्यापक असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। वैश्विक स्तर पर भूरराजनीतिक तनावों का असर केवल राजनीतिक परिस्थितियों पर ही नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ता है। ईरान और इजरायल के बीच तनाव की स्थिति में ऊर्जा आपूर्ति, विशेष रूप से तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। वैश्विक हालात अगर और खराब होते हैं, तो भारत को आर्थिक मोर्चे पर कठिन निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। असल में भारत से करीब एक करोड़ लोग खाड़ी देशों में काम करने के लिए जाते हैं। बात अगर पिछले साल की करें तो इन्हीं कामगारों ने भारत में 45 अरब डॉलर भेजे थे, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी फायदेमंद रहे, लेकिन अगर युद्ध और भीषण होता है तो उस स्थिति में इन एक करोड़ कामगारों के काम पर संकट आएगा और उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दरअसल, रूस-यूक्रेन युद्ध हो या हमास-इजरायल जंग, भारत ने हमेशा से शांति और संवाद का समर्थन किया है। दुनिया के हर मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने शांति की वकालत की है। प्रधानमंत्री बार-बार अलग-अलग मंचों से कह चुके हैं कि भारत युद्ध में नहीं, बल्कि बुद्ध में यकीन रखता है। इजरायल और ईरान दोनों से भारत के बेहतर संबंध हैं। इजरायल और ईरान जंग के बीच भारत की कूटनीतिक ताकत एक बार फिर वैश्विक मंच पर उभरी है। ऐसे में दुनिया में एक मात्र भारत ही है, जो दोनों देशों को बातचीत की मेज पर ला सकता है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

ईरान और इजरायल युद्ध के दौरान तेल अवीव में ईरान के हवाई हमले से बचने के लिए लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण ली है

संभलकर कदम उठाना जरूरी

'वृद्धि के आगे आड़े आएंगी ऊंची तेल कीमतें' ने नई संभावित परिस्थितियों का जो उल्लेख किया है उससे सहमत हुआ जा सकता है। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक नए अनिश्चितता भरे दौर में ले जा रहा है जिसका सीधा असर भारत पर पड़े बिना नहीं रह सकता। पश्चिम एशिया में छिड़ी इस लड़ाई से तेल कीमतों में आग लगनी शुरू हो गई है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड के दामों में पिछले सप्ताह 9 फीसदी बढ़ोतरी हो चुकी है। यदि यह संघर्ष इसी तरह घमासान होता रहा तो तेल की कीमतें मौजूदा स्तर से दोगुनी हो सकती हैं। ईरान के तेल ठिकानों पर हमले से उत्पादन प्रभावित होना ही है और यदि होरमुज जलडमरूमध्य में अवरोध उत्पन्न हुआ तो वैश्विक आपूर्ति में भी बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। चूंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करता है ऐसे में ऐसे देशों के लिए यह स्थिति गंभीर है। ऊंची कीमतों से व्यापार और चालू खाता घाटा दोनों ही बढ़ सकते हैं। वैसे फिलहाल भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है मगर संघर्ष लंबा खिंचा तो चुनौतियां पैदा होना स्वाभाविक ही है। इससे रुपये पर दबाव के बढ़ने से महंगाई की दर बढ़ने का खतरा पैदा हो जाएगा।

अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर, मप्र

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

भारतीय युवा कांग्रेस ने गुरुवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 'रोजगार मेले' का आयोजन किया, जिसमें करीब 3,500 युवाओं को 'जॉब लेटर' प्रदान किए गए। युवा कांग्रेस ने बताया करीब 8,500 युवाओं ने अपना पंजीकरण कराया, लगभग 7,500 युवाओं के साक्षात्कार हुए तथा 3,500 युवाओं को जॉब लेटर सौंपे गए।

8.74 अरब डालर का कारोबार हुआ था भारत और कनाडा के बीच वर्ष 2022 में, जबकि वर्ष 2023 में यह 7.65 अरब डालर रहा था।

आजकल

नया अध्याय लिखते भारत और कनाडा

कनाडा में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वहां के प्रधानमंत्री से भी व्यापक चर्चा हुई। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई चर्चा से कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं। कुछ सिख संगठनों द्वारा भारत सरकार पर लगाए गए आरोप निराधार साबित हुए, जो विघटनकारी तत्वों के खिलाफ कूटनीतिक मजबूती को दर्शाता है। कहा जा सकता है कि भारत और कनाडा ने अपने द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत की है। लिहाजा इस बैठक को दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच जी-7 शिखर सम्मेलन में हुई मुलाकात। फाइल

डा. स्नेहा भगत
असिस्टेंट प्रोफेसर, अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ हुई वार्ता में यह बात स्पष्ट रूप से प्रतीत हुई कि यह बैठक भारत और कनाडा के संबंधों के पुनर्निर्माण की आधारशिला है। सम्मेलन के बाद कार्नी द्वारा सार्वजनिक रूप से भारत को जी-7 के मंच पर 'स्वाभाविक और सतत' स्थान के रूप में स्वीकार करना कनाडा का भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और बिगड़े हुए द्विपक्षीय संबंधों में सुधार को दर्शाता है। मार्क कार्नी ने भारत के साथ संबंधों पर जोर देते हुए इसकी अर्थव्यवस्था के 'आकार और गतिशीलता' के साथ-साथ भारतीय प्रौद्योगिकी और जी-20 समेत कई मंचों पर इसकी भूमिका की सराहना की है। भारत के दृष्टिकोण से यह स्वीकारना ही केंद्रबिंदु है।

कनाडा को 'ऊर्जा महाशक्ति' बनाने का समर्थक होने के नाते कार्नी ने भारत के ऊर्जा महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर होने की भी सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी उसी बात को दोहराते हुए सतत और हरित रास्तों के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने भारत के द्वारा उठाए गए कदमों जैसे अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस, आपदा-सहनशील अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआइ) और ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस के माध्यम से, मोदी ने ऐसे उच्च-स्तरीय मंचों पर ग्लोबल साउथ (वैश्विक दक्षिण) की चिंताओं को लगातार उठाया जिससे इस क्षेत्र की प्रमुख आवाज के रूप में भारत की भूमिका और अधिक मजबूत हुई।

कूटनीतिक साझेदारी : पीएम मोदी ने दृढ़ता से आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध जताते हुए जी-7 के सभी नेताओं से वैश्विक कार्रवाई करने और इसका समर्थन या प्रचार करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की अपील की। उन्होंने सभी को भारत के 'आपरेशन सिंदूर' के तहत गुलाम जम्मू-कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का भी जिक्र किया। वार्ता में प्रौद्योगिकी और नवाचार पर भी चर्चा हुई खासकर एआइ- ऊर्जा नेक्सस और क्वांटम से जुड़े मुद्दों पर व्यापक बातचीत हुई। मोदी ने भारत में तकनीक को जनसुलभ बनाने के अनुभव और मानव केंद्रित दृष्टिकोण को भी उजागर किया। शिखर सम्मेलन के अलावा उन्होंने विश्व के अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर भारत के कूटनीतिक साझेदारी को विस्तार दिया।

बेहतर संबंध बहाली की ओर : हालांकि भारतीय दृष्टिकोण से इस दौरे की महत्ता कनाडा के साथ द्विपक्षीय संबंधों के परिणाम पर निर्भर है। मोदी ने संदेश दिया कि भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई विचार-विमर्श से परे सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। यह सब बीते एक साल के अनायास तनाव के बाद शुरू हुआ, जिसमें राजनयिकों के निष्कासन और एक घोषित खालिस्तानी आतंकवादी की अनसुलझी हत्या से उपजे तनावपूर्ण संबंध शामिल हैं। भारत लगातार अपनी भागीदारी को नकारता रहा और इसका कारण कनाडा द्वारा अपनी भूमि पर चरमपंथियों तत्वों के प्रति लचीले रवैये को माना है।

सबसे ठोस परिणाम यह है कि दोनों देशों ने संबंधों को परस्पर सम्मान के साथ पुनर्निर्माण करने के लिए आवश्यक संरचनात्मक आधार प्रदान करने पर सहमति जताई है, जिसकी शुरुआत उच्चायुक्त की नियुक्ति से होगी। इनकी अनुपस्थिति ने एक बड़ी खाई पैदा कर दी थी, जिससे राजनयिक कार्य बाधित हुए और लोगों तथा व्यापारिक संबंधों को नुकसान पहुंचा। इन महत्वपूर्ण राजनयिक पदों को फिर से स्थापित करना, साथ ही वरिष्ठ और कार्यकारी स्तर की बैठकें फिर से शुरू करना, केवल एक प्रक्रिया से कहीं अधिक है। कार्नी ने कनाडा और भारत के लोगों तथा व्यापारिक संबंधों को स्वीकार करते हुए कूटनीतिक वार्ता को संबंधों के पुनर्निर्माण का आधार बताया है। दोनों नेताओं ने एक स्वतंत्र और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और ठप पड़े व्यापार वार्ता पर भी बातचीत की, जिसका लक्ष्य एक व्यापक आर्थिक साझेदारी स्थापित करना है।

भारत की चिंता : कनाडा की मीडिया में भारत को 'कानून प्रवर्तन अंतरराष्ट्रीय निगम' के लिए जिम्मेदार ठहराने को लेकर काफी उत्साह था। जहां कार्नी ने इस विषय से ही अपनी बातचीत शुरू की, वहीं भारत इसे दोतरफा राह मानता है और कनाडा से भी जवाबदेही की अपेक्षा करता है। अंतरराष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लिए वास्तविक साझेदारी और एक-दूसरे की सुरक्षा चिंताओं की स्पष्ट समझ आवश्यक है। भारत ने निरंतर साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और कनाडा की धरती से अलगाववाद और चरमपंथ को बढ़ावा देने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 'पारस्परिक सम्मान' पर आधारित संबंध में आवश्यक है कि कनाडा इन मूलभूत भारतीय चिंताओं को गंभीरता से ले और ठोस कार्रवाई करे।

पीएम मोदी की यह यात्रा एक लंबी और कठिन राह पर पहला महत्वपूर्ण कदम। यह हमारे खटास भरे आपसी संबंधों का कोई जादुई समाधान नहीं है। विश्वास एक बार ढह जाता है तो पुनर्निर्माण में समय लगना स्वाभाविक है। भारत के लिए इन संबंधों के वास्तविक संभावनाओं को साकार करने की प्रतिबद्धता को धरातल पर उतारने के लिए कनाडा द्वारा हमारी वास्तविक सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करने, चरमपंथी तत्वों के खिलाफ सक्रिय संलग्नता और राजनीतिक दिखावे से मुक्त द्विपक्षीय संवाद के लिए सतत प्रतिबद्धता के रूप में जमीनी स्तर पर ठोस कार्यों से मापा जाएगा। उच्चायुक्तों की नियुक्ति इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है, लेकिन विश्वास बहाली और सहयोग को बढ़ावा देने का वास्तविक कार्य अभी शेष है।

भविष्य की अपेक्षाओं का समन्वय एवं चुनौतियां

प्रो. एम. एल. मीणा
प्रोफेसर, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़

कनाडा में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हुआ है, जब वैश्विक राजनीति बहुस्तरीय और गहन संकटों से जूझ रही है। इनमें भू-राजनीतिक बदलाव, यूक्रेन-रूस युद्ध, इजरायल-फलस्तीन संकट, जलवायु परिवर्तन की तीव्रता, वैश्विक अर्थव्यवस्था का अनिश्चित भविष्य और हाल ही में इजरायल-ईरान के बीच जारी युद्ध प्रमुख हैं। यह सम्मेलन न केवल लोकतांत्रिक देशों की बैठक थी, बल्कि यह परखने का भी अवसर था कि क्या तथाकथित "विश्व नेतृत्वकर्ता" देश अब भी साझा दिशा तय करने में सक्षम हैं?

सम्मेलन की शुरुआत से ही इसका स्वर असमान था। इस साल की शुरुआत में सत्ता में वापस लौटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिखर सम्मेलन में 'लेन-देन की मानसिकता' के साथ भाग लिया, और पश्चिम एशिया में ईरान-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर परिदृश्य से बाहर आ गए। इससे यह संकेत मिला कि अमेरिका के हित अब तेजी से अंतर्मुखी हो रहे हैं। लेकिन इस कदम से जी-7 की मंचीय प्रक्रिया ठप हो गई।

इस शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी कमियों में से एक जलवायु संकट के प्रति इसकी सदस्यों की उदासीन प्रतिक्रिया थी। विज्ञानियों द्वारा दी जा रही बार-बार की चेतावनी और हाल ही में चरम मौसम की घटनाओं के बावजूद जलवायु वित्त के लिए कोई नई प्रतिबद्धता को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कोई ठोस रोडमैप नहीं बना है। यह विकासशील देशों और विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में उन देशों को हतोत्साहित करने वाला संकेत है, जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए लंबे समय से वित्तीय और तकनीकी सहायता की मांग कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह कि विकासशील देश अभी भी लंबे समय से वादा किए गए 100 अरब डालर की वार्षिक जलवायु वित्त प्रतिबद्धता की रकम का इंतजार ही कर रहे हैं। इसकी परिणति यह रही कि पर्याप्त प्रतिबद्धताओं की पेशकश किए बिना, केवल जलवायु आपातकाल को स्वीकार करके जी-7 ने वास्तविक नेतृत्व प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर खो दिया है।

भू-राजनीतिक दृष्टि से इस शिखर सम्मेलन ने एक महत्वपूर्ण बदलाव को उजागर किया। शीत युद्ध के बाद का युग जहां पश्चिम वैश्विक मानदंडों को निर्धारित करता था, अब उसका वर्चस्व स्पष्ट रूप से समाप्त हो चुका है। चीन और भारत जैसी उभरती हुई शक्तियां और ब्रिक्स एवं उसके साथ जुड़े हुए देशों के क्षेत्रीय गठबंधन अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। इन सभी देशों की आवाज को शामिल करने के लिए अपने दायरे को अनुकूलित करने या विस्तारित करने में जी-7 की अक्षमता एक 'रणनीतिक विफलता' को दर्शाती है। समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए इसे फिर से आकार देने के बजाय पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने पर इसका निरंतर आग्रह आने वाले दशकों में इसके धीरे-धीरे हाशिए पर जाने का एक कारण बन सकता है।

आर्थिक दृष्टिकोण से भी इस शिखर सम्मेलन में साहसिक पहलों का अभाव ही देखने को मिला है। वैश्विक मुद्रास्फीति, अफ्रीका में ऋण संकट और आपूर्ति शृंखला की कमजोरियों के कारण विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसलिए समन्वित राजकोषीय कार्रवाई या कम से कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों को स्थिर करने के लिए एक रूपरेखा की अपेक्षा इस सम्मेलन से थी। जी-7 कनाडा शिखर सम्मेलन ने आखिरकार यह उजागर किया कि वैश्विक नेतृत्व एक चौराहे पर खड़ा है। पारंपरिक संरचनाएं अपने वादों को पूरा करने में विफल हो रही हैं, न केवल आंतरिक विभाजनों के कारण, बल्कि इसलिए भी कि जिस दुनिया पर शासन करने के लिए उन्हें बनाया गया था, वह मौलिक रूप से अब बदल गई है।

खरी-खरी

असली साहित्यकार

पूरन सरमा

यह विषय इतना सामयिक हो गया है कि निरंतर विवाद के बावजूद हल होने का नाम ही नहीं लेता। साहित्यकार और असली साहित्यकार का फर्क समझ में तो आता है, परंतु उसकी मान्यता गले नहीं उतर पाती। आदमी जब साहित्यकार हो जाता है, तब वह आम आदमी से पर्याप्त रूप से भिन्नताएं ग्रहण करता है और यदि असली साहित्यकार बन जाए तो हद से ज्यादा विशिष्ट बन जाता है। साहित्यकार और असली साहित्यकार के भेद को समझना आज की स्थितियों में जरूरी है। वरना कई जगह हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वह इसलिए कि जैसे पत्रकार को साहित्यकार मान लिया जाए या साहित्यकार को असली साहित्यकार मान लिया जाए और असली साहित्यकार को घसियारा।

आजकल पत्रकार और साहित्यकार में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि पत्रकार साहित्यकार बन रहे हैं और साहित्यकारों का रुझान पत्रकारिता की ओर हो रहा है। इसलिए इन दोनों के बीच इतनी घपलेबाजी हो गई है कि पत्रकार और लेखक दोनों को साहित्यकार मानना ही हित में है। पत्रकारों के हाथ में अखबार है। अतः वे खूब लिखते हैं- लिखने वाला लेखक होता है और लेखक साहित्यकार होता ही होता है। लेखक, पत्रकार-संपादक की कृपा पर आजकल बहुत निर्भर हो गया है। अतः उसका साहित्यकार बनना उस पर ही है। चूंकि लेखक भी छपता है। अतः वह भी साहित्य को रचने वाला है, इसी आधार पर उसके भी साहित्यकार होने में शक नहीं है।

लेकिन हमें जानना है उस जीव के बारे में जो असली साहित्यकार है। असली साहित्यकार की स्थिति वैसी ही है- जैसी असली घी की। वनस्पति घी के चलन व मिलावटियों की साजिशों के पीछे देसी घी अपनी मूल पहचान खो बैठा है, उसी तरह यह असली साहित्यकार भी बहुत ही उपेक्षित रह गया है। असली साहित्यकार की अव्वल पहचान यह है कि वह साल में एकाध बार लिखता है और फिर लंबी चुप्पी साध जाता है। असली साहित्यकार लिखता कम और भाषण ज्यादा देता है। यदि उसके मौखिक वचनों को टेप किया जाए तो प्रतिदिन एक पाकेट बुक तैयार की जा सकती है।

X पोस्ट

जिन जज पर उनके घर में नोटों से भरे बोरे पाए जाने का आरोप है, उनके अयोग्य डिफेंस लायर के तौर पर भी कपिल सिब्बल ही सामने आ रहे हैं।
रंगनाथ सिंह@rangnathsingh_

इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से दो-टूक कहा हो कि आप झूठ बोल रहे हैं।
एस. गुरुमूर्ति@sgurumurthy

मैंने किसी भी बड़े देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के सम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति को लंच या डिनर देते सुना था। यह पहली बार है कि एक सेनाध्यक्ष के सम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति लंच दे रहे हैं, वह भी पाकिस्तान जैसे देश के आर्मी चीफ को। ट्रंप असल में भारत को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं।
राजीव शुक्ला@ShuklaRajiv

जब चीन को काउंटर करने के लिए जरूरत थी, तब अमेरिका भारत से मोहब्बत का इजहार कर रहा था। अब ईरान के खिलाफ जरूरत है तो ट्रंप कह रहे हैं कि वे पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कूटनीति में अपना हित ही सर्वोपरि होता है।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

जागरण जनमत

कल का परिणाम

पीएम मोदी की ट्रंप से बात के बाद अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति रवैया बदलेगा?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या ट्रंप-मुनीर मुलाकात भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

अमेरिका को चाहिए वफादार 'यसमैन',
नजदीकी की पाक से यही बात है मैन।
यही बात है मैन बनाकर सैनिक अड्डा,
चला सके ईरान सरीखों पर वह डंडा।
'ट्रम्प भोज' का स्वाद लगेगा उनको तीखा,
जब आपाकिस्तान उगेगा खुद अमरीका!
- ओमप्रकाश तिवारी

प्रदीप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, झारखंड

झारखंड डायरी

पेसा कानून पर फिर गरमाई राजनीति

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में स्वशासन और सामुदायिक अधिकारों को सशक्त करने का एक महत्वपूर्ण कानून है। यह कानून ग्रामसभाओं को भूमि, प्राकृतिक संसाधनों और सामाजिक-आर्थिक निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान करता है। झारखंड में 26 प्रतिशत आबादी आदिवासी है और राज्य के 24 में से 13 जिले पांचवीं अनुसूची के तहत आते हैं। पेसा कानून लागू करने की मांग लंबे समय से रही है। हालांकि इसे लागू करने की प्रक्रिया और इसके नियमों को अंतिम रूप देने को लेकर हेमंत सरकार और भाजपा के बीच राजनीतिक होड़ है।

पेसा अधिनियम 1996 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को स्वायत्तता प्रदान करना है। यह कानून आदिवासी समुदायों को उनकी भूमि, जंगल, जल और खनिज संसाधनों पर नियंत्रण देने के साथ-साथ पारंपरिक संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था को संरक्षित करने पर केंद्रित है। झारखंड में आदिवासी समुदायों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि, वन संसाधनों और खनन पर निर्भर है। पेसा कानून लागू करना ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने और बाहरी हस्तक्षेप को रोकने का एक प्रभावी उपाय हो सकता है। इसके प्रमुख प्रविधानों में ग्रामीण सभाओं का सशक्तीकरण, पारंपरिक प्रथाओं का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण और सामाजिक व आर्थिक विकास है।

हेमंत सरकार ने 2023 में पेसा नियमों का मसौदा तैयार किया। यह मसौदा ग्राम सभाओं को पारंपरिक प्रमुखों की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित करने, भूमि सौदों में सहमति को अनिवार्य करने और गांव में गिरफ्तारी की स्थिति में

आदिवासी समुदाय के सामाजिक-आर्थिक हितों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। फाइल

पुलिस को 48 घंटे के भीतर ग्रामसभा को सूचित करने जैसे प्रविधान शामिल करता है। सरकार ने इसे आदिवासी हितों की रक्षा और स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। मुख्यमंत्री ने बार-बार आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण पर जोर दिया है। उन्होंने 2024 में हुए झारखंड आदिवासी महोत्सव में कहा था कि उनकी सरकार ने 73,583 एकड़ क्षेत्र को कवर करने वाले 280 सामुदायिक वन अधिकार पट्टों को भी सौंपा, जो पेसा के तहत आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है।

सोरेन सरकार का दावा है कि पेसा कानून लागू होने से आदिवासी समुदायों को उनकी जमीन और संसाधनों पर बाहरी अतिक्रमण से बचाने में मदद मिलेगी। यह विशेष रूप से वैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां खनन और औद्योगिक गतिविधियों ने आदिवासी समुदायों को प्रभावित किया है।

दूसरी ओर विपक्षी दल भाजपा ने पेसा कानून के कार्यान्वयन में देरी को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पेसा नियमों को तत्काल लागू करने की आदिवासी स्वशासन और सरना समाज की परंपराओं के संरक्षण के लिए आवश्यक बताया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ गठबंधन कुछ विदेशी धर्मों के अनुयायियों के दबाव में कानून को लागू करने में देरी कर रहा है, जिससे आदिवासी हितों को नुकसान हो रहा है।

पेसा कानून का कार्यान्वयन झारखंड के लिए कई सकारात्मक प्रभाव ला सकता है। ग्राम सभाओं को भूमि और संसाधनों पर निर्णय लेने का अधिकार मिलने से आदिवासी समुदाय अपनी आजीविका और संस्कृति को बेहतर ढंग से संरक्षित कर सकेंगे। यह विशेष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों में विस्थापन को रोकने में मददगार होगा। पेसा के तहत ग्रामसभाओं को जंगल और जल संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार मिलेगा, जिससे अवैध खनन और वन कटाई पर अंकुश लगेगा।

पेसा कानून को लेकर हो रही राजनीति में दोनों पक्षों की मंशा स्पष्ट है। हेमंत सोरेन सरकार इसे आदिवासी पहचान और स्वशासन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जो उनकी 2024 की चुनावी जीत में एक प्रमुख कारक रहा। दूसरी ओर, भाजपा इस मुद्दे को उठाकर आदिवासी मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। इन सब से इतर पेसा कानून का कार्यान्वयन समय की मांग है। झारखंड में आदिवासी समुदायों ने संसाधनों के लिए संघर्ष किया है और पेसा इस संघर्ष को एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

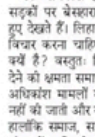

मंथन

बेसहारा गायों को मिले सहारा

ईश्वर दास
अध्यक्ष, श्रीकृष्णायन देसी गौ रक्षाशाला

बेसहारा गायों को सहारा मिले इसके लिए गोचर भूमि से अवैध कब्जा हटाया जाना चाहिए। इसमें दिल्ली की पहल का व्यापक असर हो सकता है। इससे गायों के संरक्षण को नई दिशा मिल सकेगी

देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के अधिकांश क्षेत्रों में आप अक्सर सड़कों पर बेसहारा गायों को भटकते हुए देखते हैं। लिहाजा हमें इस बारे में विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है? वस्तुतः जिन गायों की दूध देने की क्षमता समाप्त हो जाती है, ऐसे अधिकांश मामलों में उनकी देख-रेख नहीं की जाती और वे भटकती रहती हैं। हालांकि समाज, सरकार और संबंधित संस्थानों आदि की ओर से इन गायों के लिए गौशालाओं की व्यवस्था की गई है, परंतु उनकी संख्या पर्याप्त न होने के कारण अक्सर वे भटकती रहती हैं।

ऐसे में दिल्ली सरकार बेसहारा गोवंश की रक्षा के लिए नया कानून बनाने जा रही है। दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा में सड़कों पर भटक रही बेसहारा गायों की समस्या पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो चुकी है। इसमें बेसहारा गायों की रक्षा के लिए अतिरिक्त आश्रय स्थल निर्माण की मांग की गई है। वैसे इस विमर्श की प्रक्रिया में गोचर भूमि उद्धार की बात नदारद है। गायों के लिए स्थायी आश्रय स्थल को गोचर भूमि के रूप में जाना जाता है। नीति निर्माण में लगे विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों को इसकी महत्ता भी समझने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी अपने सरकारी आवास में गायों की सेवा का प्रबंध कर रखा है। इसके बावजूद दिल्ली में बड़ी संख्या में बेसहारा गोवंश भटक रहे हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक फ्लाईओवर पर भटकते हुए गायों की वजह से लगभग 15 मिनट इंतजार करना पड़ा था। उसी समय उन्होंने अधिकारियों से गायों के लिए उचित आश्रय की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। यह कहा जा सकता है कि दिल्ली की नई सरकार गोवंश की रक्षा हेतु समर्पित प्रतीत होती है।

गोवंश के लिए आश्रय की व्यवस्था करना आवश्यक है। लेकिन इस कार्य में लगे नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्मृतिलोप की समस्या है, ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि यह ऐसी समस्या नहीं, जिसका समाधान बहुत मुश्किल हो। उन्हें याद दिलाना होगा कि इतिहास में पहले से ही गायों का आश्रय स्थल गोचर रहा है। देश के हर गांव की सीमा में गोचर भूमि हुआ करती थी। गोकशी करने वाले आक्रांताओं की तमाम कोशिशों और साजिशों के बावजूद इसे नष्ट नहीं किया जा सका था। परंतु आजादी के बाद स्वदेशी सरकारों की राजनीति इसे नष्ट करने की रही। इस मामले में दिल्ली अवैध कब्जे का मार्ग प्रशस्त करती है। उल्लेखनीय है कि 14वीं सदी में सनातन के प्रवक्ता श्याम गिरि सवाई को चार हजार एकड़ भूमि यमुना किनारे आवंटित की गई थी। शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के समीप स्थित श्याम गिरि सवाई मठ इसके सिकुड़ने की कहानी बयां करती है।

गोधूलि बेला में यमुना तट से गायों के साथ लौटते गोपाल कृष्ण के भक्त श्याम गिरि और उनके शिष्यों द्वारा मुगलों और फिरंगियों के राज में भी गौसेवा और यमुना सेवा की मर्यादा बराबर कायम रही। हजारों गुर्जर परिवार उनके साथ साये की तरह खड़ा रहा। उन्हें इस बात का ज्ञान रहा कि पशुओं के प्रवक्ता गायों को बांधते नहीं हैं। उस दौर में बैल कृषि और यातायात में उपयोगी बने रहे। आज इन सभी तथ्यों को फिर से याद करने और समझने की आवश्यकता है। दिल्ली को यह समझना होगा कि देसी गांव समाज की कल्पना भी गोचर भूमि के बिना संभव नहीं रही। यमुना तट पर पसरा घास का मैदान गायों के लिए सुरक्षित था। क्या यह आज भी सुरक्षित है? देसी कृषि की यह संस्कृति दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं थी। मिथिला के राजा जनक के काल का विवरण बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। इसमें भी गोचर और गाय संरक्षण की चर्चा की गई है।

गोचर की पर्याप्त व्यवस्था होने से ही संभव है गायों का संरक्षण। फाइल

गोसेवक समाज का पतन : पश्चिम से आयातित सभ्यता देश के लिए घातक साबित हुई। गुलामी का दौर बीतने के बाद भी औपनिवेशिक मानसिकता हावी होती रही। आजाद भारत में गोसेवक समाज का पतन और विखंडन तीव्रता से होने लगा। श्याम गिरि सवाई मठ के संन्यासियों ने एक इंच जमीन नहीं बेची, लेकिन यह चार हजार एकड़ से सिकुड़ कर आठ एकड़ में सिमट कर रह गया है। सोचने वाली बात है कि इतने छोटे इलाके में कितनी गायें रह और चर सकती हैं। जबकि यह सब जानते हैं कि गोचर में चरने पर ही गायों का दूध अमृत होता है। इसलिए इस कड़ी में गोचर भूमि का संरक्षण और उद्धार आवश्यक है।

गोचर भूमि से हटे कब्जा : दिल्ली में यमुना तट पर रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट अंगड़ाई लेने को मचल रहा है। आमजन को यह प्रोजेक्ट बहुत ही लुभा रहा है। कंक्रीट का नया जंगल खड़ा करने की पहल प्रकृति को लाठी भांजने को मजबूर कर सकती है। इसलिए बेहतर यह होगा कि इसमें गोचर भूमि उद्धार कार्यक्रम को भी शामिल किया जाए। श्याम गिरि सवाई मठ की अधिगृहित जमीन इसी उद्देश्य के लिए वापस कर सरकार को जनभागीदारी की नई मिसाल पेश करने की आवश्यकता है। गोचर भूमि से अवैध कब्जा हटाए जाने से गायों का संरक्षण कार्य आसान होगा। इस मामले में दिल्ली की पहल प्रभावी हो सकती है। आधुनिक भारत प्राचीन मूल्यों को त्याग कर अपनी जड़ों से कटता हुआ दिख रहा है। जड़ों से जुड़ने की नीति अपनाने से गायों के संरक्षण को सही दिशा मिल सकती है।

****

दैनिक जागरण
दुविधा की स्थिति में अंतरात्मा की आवाज ही राह दिखाती है

अब तो पद छोड़ें

अपने सरकारी आवास में बड़ी संख्या में अधजले नोट मिलने से कठघरे में खड़े उच्च न्यायालय के जज यशवंत वर्मा की जांच करने वाली सुप्रीम कोर्ट समिति की रपट के ऐसे निष्कर्ष बहुत ही गंभीर हैं कि उनका कदाचार साबित हो रहा है और वे पद पर रहने के योग्य नहीं। इस रपट में उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की संस्तुति भी की गई है। ऐसी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कर दी थी और उसके आधार पर सरकार यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी भी कर रही है, पर उच्चतर न्यायपालिका के जजों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लंबी चलती है। महाभियोग प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों से पारित कराना पड़ता है। आज तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, क्योंकि कभी क्षेत्रवाद, जातिवाद की संकीर्ण राजनीति आड़े आ गई और कभी पक्ष-विपक्ष में सहमति ही नहीं बन पाई। पता नहीं इस बार क्या होगा। कहीं जांच समिति की रपट का लीक होना मुद्दा न बन जाए। जो भी हो, न्यायपालिका की छवि के लिए बेहतर यही होगा कि यशवंत वर्मा स्वतः त्यागपत्र दे दें।

अधजले नोट कांड के बाद जज यशवंत वर्मा को दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजकर उन्हें न्यायिक कामकाज से विरत कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर इसलिए सवाल उठे थे, क्योंकि उनके खिलाफ जांच के लिए तीन जजों की एक समिति तो बना दी गई थी, लेकिन मामले की छानबीन करने के लिए दिल्ली पुलिस को नहीं कहा गया था। आखिर क्यों? क्या इसलिए कि यशवंत वर्मा उच्च न्यायालय के जज हैं? क्या उच्चतर न्यायालयों के जज कानून से परे होते हैं? यह प्रश्न आज भी है कि आखिर ऐसे जजों पर लगे कदाचार के गंभीर आरोपों की जांच पुलिस को क्यों नहीं करनी चाहिए? यह सही है कि विशेषाधिकार के चलते उच्चतर न्यायपालिका के जजों पर लगे गंभीर आरोपों की जांच पुलिस सीधे नहीं कर सकती और उसे सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेनी होती है, लेकिन यशवंत वर्मा के मामले में तो जांच रिपोर्ट मिल जाने के बाद भी शीर्ष अदालत ने पुलिस को जांच के कोई निर्देश नहीं दिए थे। बात केवल यशवंत वर्मा की ही नहीं है। इसकी पूरी आशंका है कि उनके जैसे कुछ और जज भी हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि रह-रहकर उच्चतर न्यायालय के जजों के आचरण को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं। ऐसे कुछ जजों को त्यागपत्र देने के लिए कहा गया। कुछ ने विपरीत हालात देखकर त्यागपत्र दे दिया, लेकिन कुछ ने नहीं दिया या पद छोड़ने में देर की। यह देर एक तरह की अंधेर ही होती है। यह सच स्वीकार करने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए कि उच्चतर न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है।

सर्वजन सुलभ हो योग

संपूर्ण भारतवर्ष में सनातनी योग के प्रति दीवानगी बढ़ी है। हरियाणा योगेश्वर श्रीकृष्ण की कर्मभूमि रही है। स्वाभाविक ही, योग अपनाने में यहां के लोग किसी प्रांत से पीछे नहीं हैं। इस सच को यूं भी समझा जा सकता है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर योग की ग्राह्यता तेजी से बढ़ी है। इस बार राज्य में सामूहिक योगाभ्यास के लिए 11 लाख लोगों का पंजीकरण इस सच्चाई को बल देता है। जिला एवं खंड स्तर पर योग के व्यापक कार्यक्रम तय कर प्रदेश सरकार ने योग-चेतना जागृत करने का प्रयास किया है। इस बार महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी व्यायामशालाओं में विशेष योग कार्यक्रम के आयोजन से योग युक्त, नशा मुक्त हरियाणा का संदेश देने की रणनीति तैयार की गई है। ऐसा अपेक्षित भी था। युवा शक्ति को नशे के दलदल से बाहर निकालने में योग प्रमुख भूमिका निभा सकता है। जो योग को अपनाएगा, उसमें सकारात्मक सोच प्रवाहित होने की संभावना बलवती होगी। इसलिए यह कहना उचित होगा कि सरकार ने योग युक्त, नशा मुक्त हरियाणा का स्लोगन देकर सराहनीय निर्णय लिया है। इस बार थीम भी सार्वभौमिकता लिए हुए है। 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग' की थीम की सर्वव्यापकता है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी एक साथ योग करें और स्वस्थ रहें। हरियाणा में योग के प्रति रुचि और बढ़ाने के लिए कुछ अतिरिक्त जतन करने होंगे। सरकारी स्कूलों में व्यायामशालाएं हों ताकि दूर न जाने के चाहवान ग्रामीणों की भी रुचि बनी रहे।

भारतीय संस्कृति में सनातन से रचा-बसा योग जन-जन तक पहुंचे, इसके लिए अभी कुछ और कदम उठाने होंगे

अमेरिका–पाकिस्तान फिर एक साथ

श्रीराम चौलिया

महाशक्तियों की दोहरी मानसिकता और पाकिस्तान के बिकाऊ रवैये से भारत को लंबे कूटनीतिक एवं सैन्य संग्राम के लिए कमर कसनी होगी

कार्ल मार्क्स ने कहा था, 'इतिहास खुद को दोहराता है-पहले त्रासदी के रूप में और फिर मजाक के रूप में।' कट्टर जिहादी सोच वाले पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में भोज के लिए बुलाकर और पाकिस्तान से गहरे सामरिक तालमेल की पेशकश करके मार्क्स के कथन को प्रासंगिक कर दिया। 1980-88 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने तत्कालीन पाकिस्तानी तानाशाह जनरल जियाउल हक को गले लगाया था। फिर राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश ने भी जनरल परवेज मुशर्रफ को। क्या इस खतरनाक खेल का तीसरा अध्याय अब आरंभ हुआ है? जनरल जिया और मुशर्रफ की तुलना में मुनीर पाकिस्तान के औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष नहीं हैं, पर उन्हें उसी तरह का रुतबा हासिल है।

अमेरिका अतीत में भी पेश किए जा चुके भूराजनीतिक तर्कों के आधार पर ही नए सिरे से पाकिस्तान को अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा है। रीगन को जिया की जरूरत इसलिए पड़ी थी, क्योंकि वे पाकिस्तान के पड़ोसी देश अफगानिस्तान से सोवियत संघ को वापस धकेलना चाहते थे। अमेरिका को अपने सहायक के रूप में लड़ने के लिए मुजाहिदीन चाहिए थे। वे पाकिस्तान ने उपलब्ध कराए। जिया खुद जिहादी प्रवृत्ति के थे। एक समय उन्होंने कश्मीर हड़पने के इरादे से भारत के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया था। तब अमेरिका ने इसकी अनदेखी की थी, क्योंकि उसका मकसद साम्यवाद को टक्कर देना था। रीगन की भांति ही बुश ने भी मुशर्रफ को अरबों डालर की आर्थिक और सैन्य मदद देकर अफगानिस्तान में बदलाव के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। तब अमेरिका को उस कट्टर जिहादी तालिबान की सरकार गिरानी थी, जिसने अमेरिका में 9/11 हमलों के जिम्मेदार ओसामा बिन लादेन को शरण दी थी। अमेरिका के पैसे और हथियारों से लैस पाकिस्तान ने दोनों बार अपनी उपयोगिता सिद्ध की, पर दोहरा खेल भी खेला। उसने अमेरिका को कुछ हद तक खुश रखते हुए दक्षिण एशिया में जिहादी जहर घोला। उसके इसी पाखंड से उकताकर ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान को सैन्य सहायता पूर्णतः रोक दी थी। 2018 में पाकिस्तान को 'झूठा और धोखेबाज' कहने वाले ट्रंप आज उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। दरअसल विश्व राजनीति में फिर ऐसा मोड़ आया है, जब अमेरिका को अपने भूराजनीतिक लक्ष्यों को साधने के लिए पाकिस्तान की जरूरत आन पड़ी है। इसीलिए वह उसे रिझा रहा है। पाकिस्तान के पड़ोसी ईरान पर अमेरिका के निकटतम साथी इजरायल ने हमला बोल दिया है। इस हमले का अंतिम उद्देश्य तेहरान में तख्तापलट है। ट्रंप ने मुनीर के साथ बैठक में ईरान पर चर्चा की और यह भी कहा कि इस मामले पर पाकिस्तान 'मुझसे सहमत है।' अमेरिका को लगता है कि शिया ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई जैसे सर्वोच्च नेता की तानाशाही के खात्मे के लिए सुन्नी पाकिस्तान को अग्रिम मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को इसके लिए भी शाबाशी दी कि वह अफगान-पाकिस्तान सीमा पर इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को पकड़ने और उन्हें मार गिराने में वाशिंगटन का 'अभूतपूर्व साझेदार' बन गया है।

अशोक रामगढ़

भारत को अंदेशा है कि इस सबके चलते अमेरिका पहलगाम जैसे पाकिस्तानी बर्बर आतंकी कृत्यों की अनदेखी कर सकता है। वैसे तो ट्रंप भारत के आतंक विरोधी अभियान को समर्थन का वादा करते हैं और चीन की चुनौती का सामना करने के लिए भारत को करीब लाना चाहते हैं, पर यह स्पष्ट ही है कि महाशक्तियों की रणनीति एक देश के हितों तक सीमित नहीं रहती।

फिलहाल वाशिंगटन का प्रमुख लक्ष्य ईरान में बदलाव और अमेरिका पर हमला करने की ताक में रहने वाले इस्लामिक स्टेट से निपटना है। अगर मुनीर ट्रंप के साथ सौदा करते हैं और पाकिस्तान अमेरिका से पुनः सैन्य सामग्री और आर्थिक लाभ लेने लगता है तो इससे अमेरिका पाकिस्तान को चीन के साये से भी बाहर निकाल सकता है। अमेरिका का रणनीतिक लक्ष्य व्यापक और बहुआयामी है, जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों से मेल खाता नहीं दिख रहा है। यदि अमेरिका पाकिस्तान को चीन के चंगुल से निकालने में सफल हो जाता है तो इससे भारत का भला होगा, पर यदि पाकिस्तान अमेरिका की शरण में जाकर भारत में पहलगाम जैसे जघन्य जिहादी हमले कराने का दुस्साहस करेगा तो इससे भारत को खतरा बढ़ जाएगा।

ट्रंप की मानें तो उन्होंने मुनीर को इस कारण धन्यवाद जताने के लिए अमेरिका आमंत्रित किया, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत से युद्ध करने से परहेज किया। ट्रंप ने मुनीर की कथित सूझबूझ को सराहा और उनकी बराबरी भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से करते हुए कहा कि दोनों की परिपक्वता के चलते अमेरिका ने दक्षिण एशिया में परमाणु युद्ध रोक दिया। ऐसे बेबुनियाद दावे खारिज करने के ही लिए ट्रंप से फोन पर वार्ता में मोदी ने दो टूक कहा कि कश्मीर पर किसी भी देश की मध्यस्थता भारत को कतई मंजूर नहीं है। कनाडा में जी-7 शिखर सम्मेलन में भी मोदी ने आतंक की जड़ पर सबका ध्यान केंद्रित करते हुए आतंकवाद पर विकसित देशों के दोहरे मापदंड की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विकसित देश 'किसी भी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देते हैं, पर आतंकवाद का खुलेआम समर्थन करने वाले देशों को पुरस्कृत करते हैं।'

आतंक-आतंक में अंतर स्वार्थी सोच है। इसके कारण ही विश्व समुदाय आतंक की समस्या पर काबू नहीं कर पाया है। भारत को पाकिस्तान का आतंकी चेहरा सामने लाने और उसे काबू में रखने का प्रयास करते रहना होगा। भारत को लंबे कूटनीतिक-सैन्य संग्राम के लिए कमर कसनी होगी, क्योंकि महाशक्तियों की चिरपरिचित दोहरी मानसिकता और पाकिस्तान के बिकाऊ रवैये से साफ होता है कि आतंकवाद पर अंकुश लगाने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की सीमाएं हैं।

(लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं)

response@jagran.com

बुजुर्ग होते विश्व में भारत की महत्ता

डा. विशेष गुप्ता

भारत को अभी युवा आबादी का लाभ मिल रहा है, पर यह भी ध्यान रहे कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है

देश में 16वीं जनगणना की अधिसूचना जारी हो चुकी है। देश में यह पहली ऐसी जनगणना होगी, जहां आंकड़ों का संकलन कागज-कलम से न होकर डिजिटल आधार पर किया जाएगा। 2011 के बाद होने वाली इस जनगणना में जाति गणना भी शामिल होगी। इस जनगणना से भारत में गरीबी, शिक्षा, लोगों की आय, लिंगानुपात, जाति, पंथ, अमीरी-गरीबी, युवा-बुजुर्ग इत्यादि की तस्वीर साफ होगी। अभी हम युवा देश हैं, परंतु हाल में देश में लिंगानुपात से संबंधित जो रपटें आई हैं, उनमें देश में वृद्धजनों की बढ़ती आबादी का आकलन किया गया है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहली रिपोर्ट प्लोसेस नामक जर्नल में प्रकाशित हुई है। इसके आंकड़े बताते हैं कि आज भारत का हर चौथा-पांचवां बुजुर्ग स्मृति लोप, भाषा का ठीक से प्रयोग न करने, सोचने-समझने एवं निर्णय लेने की क्षमता के कमजोर हो जाने जैसी समस्याओं से जूझ रहा है।

दूसरी रिपोर्ट भारतीय स्टेट बैंक ने जारी की है। इसके अनुसार भारत की कामकाजी आबादी की औसत आयु 2021 में 24 वर्ष के मुकाबले साल 2026 में बढ़कर 28-29 वर्ष हो जाएगी। आज चीन की कामकाजी औसत आयु 39.5 साल है। वहीं यूरोप में यह 42 साल, उत्तरी अमेरिका में 38 एवं एशिया में 32 साल है। वैश्विक स्तर पर यह औसत आयु 30.4 वर्ष दर्ज की गई है। एसबीआइ की रिपोर्ट संकेत देती है कि भारत में शून्य से चौदह साल के बच्चों की आबादी में गिरावट आ रही है। 1991 में इनकी जो आबादी 36.4 करोड़ थी, वह 2026 में घटकर 34 करोड़ रहने वाली है। आबादी में 1991 में इनकी जो हिस्सेदारी 37 प्रतिशत थी, वह वर्ष 2026 में घटकर 24.3 प्रतिशत रह जाएगी। इस प्रकार 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की आबादी विगत ढाई दशक में बढ़कर दोगुनी हो गई है। इसका अर्थ है कि 2001 में बुजुर्गों की जो आबादी 7.9 करोड़ थी, वह साल 2026 में बढ़कर 15 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। इनमें 7.7 करोड़ पुरुष तथा 7.3 करोड़ महिलाएं होंगी। इसी तरह वर्ष 2001 में देश में जो कामकाजी आबादी 58.6 करोड़ थी, 2026 में इसके बढ़कर 91 करोड़ होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि अगली जनगणना में देश की कुल आबादी में 67 प्रतिशत हिस्सेदारी कामकाजी लोगों की होगी। इसी संदर्भ में तीसरी रिपोर्ट केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय ने प्रकाशित की है। यह बताती है कि देश में 2036 तक बच्चों एवं किशोरों की आबादी में गिरावट दर्ज होगी और बुजुर्गों एवं मध्यम उम्र के लोगों की संख्या बढ़ेगी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में आबादी में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की हिस्सेदारी 26.2 प्रतिशत थी, लेकिन 2026 में यह घटकर 20.6 प्रतिशत रह जाएगी। 2021 में 35-49 आयुवर्ग के लोगों की आबादी में हिस्सेदारी 19.1 प्रतिशत थी, परंतु 2026 में इस आयुवर्ग का प्रतिशत बढ़कर 23 प्रतिशत हो जाएगा।

दिल्ली में एक कोचिंग केंद्र के बाहर एकत्रित छात्र। फाइल

वर्तमान में देश की आबादी में 60 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लोगों का प्रतिशत 9.5 है। 2036 में ऐसे लोगों की आबादी बढ़कर 13.9 प्रतिशत हो जाएगी। चौथी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की है। इसमें कहा गया है कि अगले 25 वर्षों में भारत की आबादी में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की हिस्सेदारी 20.8 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। अर्थात देश में हर पांचवां व्यक्ति बुजुर्ग की श्रेणी में होगा। 2024-2050 के बीच देश की कुल आबादी 18 प्रतिशत ही बढ़ेगी, मगर वृद्ध जनसंख्या में 134 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होगी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022-2023 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी 14.9 करोड़ थी। यानी कुल आबादी में इनका हिस्सा 10.5 प्रतिशत था। इस तरह देश में 100 कामकाजी लोगों पर 16 वृद्धजन निर्भर हैं। इससे देश में कामकाजी युवाओं और वृद्धजनों के बीच संतुलन के बिगड़ने की आशंका है। अभी संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम जनसांख्यिकी रिपोर्ट से पता चला है कि 2025 के अंत तक भारत की आबादी दुनिया में सर्वाधिक 1.46 अरब तक पहुंच जाएगी। इस रिपोर्ट से देश की जनसंख्या संरचना, प्रजनन क्षमता एवं जीवन प्रत्याशा में भविष्य में बड़े परिवर्तन के संकेत मिलते हैं।

उपरोक्त रपटों का सार यही है कि यदि भारत में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है तो फिलहाल उससे कहीं बढ़े हुए अनुपात में कामकाजी युवक-युवतियों की संख्या भी बढ़ रही है। आज विकसित देशों में जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि दर साल दर साल घट रही है। जापान, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन जैसे देशों में जनसंख्या के बढ़ने का स्तर अमूमन शून्य हो चुका है। निःसंदेह भविष्य में वहां वृद्धजनों की संख्या बढ़ेगी और कार्यशील जनसंख्या कम होती जाएगी। इससे उनका उत्पादन स्वतः ही घटेगा। भविष्य में भारत उन देशों में प्रमुख होगा, जहां कार्यशील युवा जनसंख्या सबसे अधिक होगी। प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक जिस विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, उसके लिए यदि युवाओं की ऊर्जा, शक्ति, उत्साह और सामर्थ्य देश के काम आएगा तो उसी अनुपात में वरिष्ठजनों का अनुभव भी भारत के निर्माण में पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा। फिर भी आज की आवश्यकता यही है कि युवाओं के बेहतर भविष्य के साथ वरिष्ठजनों के लिए सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के भी प्रबंध हों।

(लेखक समाजशास्त्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आत्ममूल्य

आत्ममूल्य से आशय है-स्वयं का महत्व समझना, अपने अंदर निहित क्षमताओं, योग्यताओं एवं विशिष्टताओं की पहचान करते हुए उन्हें स्वीकारना। मानवरूपी काया पाने के उपरांत यदि हम आत्ममूल्य से अवगत न हो पाए, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। निःसंदेह जीवन जीने के लिए हमें बाह्य जगत एवं बाहरी परिस्थितियों से संबंध रखना ही होगा, किंतु इसी यात्रा में हमें एक शाश्वत सत्य को भी अपने अंतरात्मा से जोड़े रखना चाहिए और वह सत्य है कि मेरे लिए मुझसे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। जिस क्षण हम उपर्युक्त कथन का भाव समझने में सफल हो जाएंगे, उसी क्षण हम आत्ममूल्य की अवधारणा को भी समझ जाएंगे।

मनुष्य केवल एक शारीरिक अस्तित्व का नाम नहीं है, अपितु मनुष्य शब्द अपने आप में बहुत ही गहन एवं गूढ़ अर्थों को समाहित करता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आत्ममूल्य सतत रूप से परिष्कृत होता रहता है। यदि हम व्यस्ततम दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकालकर स्वयं के लिए समर्पित करें एवं इन प्रश्नों पर मंथन करें कि मैं कौन हूं, मेरा इस जगत में आने का उद्देश्य क्या है एवं मैं किन क्षमताओं से युक्त हूं, तो निश्चित रूप से हम आत्ममूल्य का आकलन करने में समर्थ हो सकेंगे।

'अहं ब्रह्मास्मि' अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, के पीछे यह भाव निहित है कि मनुष्य असीम क्षमताओं से युक्त है। आत्ममूल्य की पहचानना एवं जीवन के व्यावहारिक पहलुओं में इसका उपयोग हमारे लिए एक ऐसी उत्कृष्ट एवं दृढ़ आधारशिला का निर्माण करता है जिस पर हमारे जीवन की इमारत खड़ी होती है। स्वामी विवेकानंद का कथन है, 'अपने आप को कम मत समझो, तुम अनंत संभावनाओं का भंडार हो।' हमें सदैव सकारात्मकता के भाव से ओतप्रोत रहते हुए आत्ममूल्य का विश्लेषण करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सफल एवं सार्थक सिद्ध हो सके।

प्रेरणा अवस्थी

श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि

डा. मोनिका शर्मा

इस वर्ष उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद पांच हेलीकाप्टर हादसे का शिकार हो चुके हैं

देश के किसी भी हिस्से में यात्रा के लिए उपलब्ध सेवाओं और सुविधाओं का सही ढंग से संचालन न होने पर वे समस्या बन जाती हैं। जब सुविधाएं ही जीवन को जोखिम में डालने लगें, तो स्थिति और विकट हो जाती है। यही कारण है कि दुर्गम इलाकों में सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन और भी आवश्यक हो जाता है। इन दिनों उत्तराखंड में एक के बाद एक हेलीकाप्टर दुर्घटनाओं के कारण श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कई प्रश्न उठ रहे हैं। हाल में उत्तराखंड में केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा एक हेलीकाप्टर गौरीकुंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट समेत सात लोगों का जीवन छिन गया, जिनमें दो बच्चे भी शामिल थे। आर्यन एविएशन कंपनी के हेलीकाप्टर में सभी श्रद्धालु केदारनाथ दर्शन के बाद लौट रहे थे। मौसम खराब होने के कारण हेलीकाप्टर पहाड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हेलीकाप्टर हादसे में हेली कंपनी की लापरवाही भी सामने आई है। कंपनी को सुबह छह बजे से हेलीकाप्टर उड़ाने की अनुमति थी, जबकि यह दुर्घटना साढ़े पांच बजे हुई। ऐसे में खराब मौसम के साथ ही नियमों के संभावित उल्लंघन को भी हादसे की वजह माना जा रहा है।

ऐसे हादसे प्रबंधन और व्यवस्थागत कमियों के साथ-साथ मानक संचालन प्रक्रियाओं से जुड़ी कमियों या उनका अनुसरण न करने की गलतियों को भी उजागर करते हैं, जिसका परिणाम बिना गलती की सजा के समान आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। ध्यातव्य है कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की सहजता और सुविधा के साथ दर्शन सेवा उपलब्ध करवाने के लिए ही हेली सेवा शुरू की गई थी। ऐसे में सुविधा को संकट में डालने वाली इन दुर्घटनाओं के कारणों को जानना आवश्यक है। साथ ही सधे संचालन के लिए नियमों की सख्ती भी आवश्यक है।

चिंतनीय है कि केदारनाथ में इस तरह की दुर्घटना पहली बार नहीं हुई है। इस वर्ष उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद पांच हेलीकाप्टर हादसे का शिकार हो चुके हैं। ऐसे में दुर्घटनाओं का यह सिलसिला संचालन से जुड़ी खामियों के साथ ही अन्य मोर्चों पर सोचने को विवश करता है। ज्ञात हो कि तीन साल पहले नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा किए गए आडिट में भी उड़ानों से जुड़े सुरक्षा मानकों की अनदेखी की बात सामने आई थी। असल में हेली सेवाएं श्रद्धालुओं के लिए वरदान से कम नहीं हैं। खासकर बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए इन सेवाओं ने चारधाम यात्रा को काफी सहज बनाया है। ऐसे में कठिन भौगोलिक और मौसमी स्थितियों को देखते हुए न केवल प्रशासन को सुरक्षा मानदंडों के पालन को सुनिश्चित करना चाहिए, बल्कि हेली सेवाएं देने वाली कंपनियों द्वारा सुरक्षा नियमों का गंभीरता से पालन किया जाना चाहिए।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

नए भारत की स्पष्ट नीति

'मोदी की ट्रंप से खरी बात' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा गया है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आएगा। कश्मीर, आतंकवाद और युद्ध नीति को लेकर नए भारत का सोच और नीति एकदम स्पष्ट है। शांति का पक्षधर भारत युद्ध का समर्थन नहीं करता, लेकिन यदि कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेगा भी नहीं। यह दिख भी रहा है कि नया भारत गोली का जवाब गोले से दे रहा है। पाकिस्तान में आतंकवाद की नर्सरी चलाने वाले आतंकी आकाओं को उन्हीं की भाषा में जवाब देकर भारत ने पाकिस्तान को यह संदेश भी दे दिया है कि उसके द्वारा प्रायोजित हर आतंकी घटना को भारत अपने विरुद्ध युद्ध मानकर उसका करारा जवाब देगा। भारत की इस नीति को लेकर अमेरिका जैसी वैश्विक शक्ति यदि निहित स्वार्थवश कोई हस्तक्षेप भी करना चाहेगी तो भारत उसके दबाव में नहीं आएगा। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ होने वाले किसी भी अंतर्विरोध के समाधान हेतु किसी तीसरे की मध्यस्थता को भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भारत हमेशा प्रयत्नशील रहता है। वर्तमान में चल रहे इजरायल-ईरान और रूस-यूक्रेन युद्ध की विनाशकारी भयावहता को भारत दुर्भाग्यपूर्ण मान रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि आज इजरायल के लिए हमास और हाउती जैसे आतंकी संगठन केवल इसलिए चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि ईरान जैसा ताकतवर इस्लामिक देश इन आतंकी संगठनों की हर तरह की मदद कर रहा है। इजरायल के विरुद्ध ईरान का यह प्राक्सी वार का खेल वैसा ही है जैसा कि पाकिस्तान भारत के साथ खेलता रहा है। ऐसे में अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ईंट का जवाब पत्थर देना हर स्वाभिमानी देश के लिए लाजिमी है।

pandeyvp1960@gmail.com

मेलबाक्स

अमेरिका का सच

आतंकवाद को लेकर अमेरिका अब बेनकाब हो चुका है। दो देशों को लड़ाकर अपने को मसीहा साबित करने वाले अमेरिका का सच दुनिया को पता चल चुका है। पीएम मोदी के साथ दोस्ती का ढोंग रचने वाला अमेरिका क्या वास्तव में पाकिस्तान का हमदर्द है? क्या अमेरिका ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिफ मुनीर को पहलगाम कांड कराने के लिए टास्क दिया था? उपरोक्त आरोप अमेरिका पर इसलिए हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच सीजफायर के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिफ मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाकर ऐसी खातिरदारी की है कि पाकिस्तान की सरकार गदगद है। अमेरिका पर आंख मूंदकर भरोसा करना बेमानी होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोले से उनकी लोकप्रियता घट रही है।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

जवाबदेही का संकट

हर बड़ी दुर्घटना के बाद देश में संवेदना की लहर तो उठती है, पर लहर थमते ही शासन, प्रशासन और व्यवस्था की जवाबदेही भी बह जाती है। यह विडंबना नहीं, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विफलता है, जहां दुर्घटनाओं को 'नियति' और 'दुर्भाग्य' बता कर जिम्मेदार लोग खुद को निर्दोष घोषित कर लेते हैं। रेलवे हो या अस्पताल, विमान हादसा हो या स्कूल की छत गिरना-अधिकतर मामलों में पाया गया है कि सुरक्षा मानकों की खुली अनदेखी, प्रशासनिक उदासीनता और भ्रष्ट अनुज्ञापन प्रक्रिया दुर्घटनाओं की मूल वजह होती हैं। किंतु किसी मंत्री, अफसर या जिम्मेदार संस्था पर ठोस कार्रवाई दुर्लभ है। क्यों? हमारे देश में नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन के बीच एक गहरी खाई है। सुरक्षा मापदंड कागज पर होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में उनकी अनुपालना पर किसी की रुचि नहीं। जांच समितियां बनती हैं, रिपोर्ट आती हैं, पर निष्कर्ष केवल कागजों तक सीमित रह जाते हैं। समस्या प्रणालीगत है। समाधान भी प्रणालीगत सुधार से ही संभव है। जब तक संस्थागत जवाबदेही को कानूनी और नैतिक रूप से अनिवार्य नहीं किया जाएगा, तब तक 'घटनाएं' जारी रहेंगी, और सत्ता में बैठे लोग केवल मुआवजे और शोक संदेशों से अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे।

अवनीश कुमार गुप्ता, हिसार

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

डिजिटल धोखाधड़ी

बड़ी समस्या

डिजिटल धोखाधड़ी भारत में एक बड़ी समस्या बन गई है जिसके कारण हजारों लोगों का मेहनत से कमाया पैसा अदृश्य डिजिटल धोखेबाज हड़प लेते हैं और वे विरले ही पकड़ में आते हैं। हर बार फोन पर जब आप अमिताभ बच्चन की आवाज में डिजिटल धोखाधड़ी के बारे में चेतावनी सुनते हैं तो याद रखें कि यह केवल सार्वजनिक जागरूकता संदेश नहीं है। यह उस बड़ते संकट का प्रतीक है जो अधिकांश लोगों की कल्पना से भी अधिक व्यापक है। हजारों लोग अनजाने ही ऐसे धोखेबाजों का शिकार बन जाते हैं जो फोन काल, फर्जी वेबसाइटों और सोशल मीडिया में फैलाए जाल में फंस जाते हैं और इस प्रक्रिया में अपनी मेहनत से कमाई धनराशि गंवा देते हैं। यह और अधिक चिन्ता की बात है कि अधिकांश मामलों में धोखेबाज की पहचान अज्ञात रहती है और उसे पकड़ने की संभावना कष्टदायक रूप से बहुत कम होती है। 'कैशलेस अर्थव्यवस्था' की ओर तेज दौड़ के कारण भारत के डिजिटल परिदृश्य ने समृद्धि के साथ संकट के दरवाजे भी खोल दिए हैं। स्मार्टफोन के पर्स में बदलने तथा स्वाइप की गति से पैसा दौड़ने के साथ धोखेबाज भी डिजिटल हो गए हैं। वे भी इसी लहर पर सवार हो कर खामोश धोखाधड़ी से भारतीयों की लाखों रुपयों की मेहनत से एकत्र बचत हड़प रहे हैं। यह संकट खतरनाक रूप से बहुत व्यापक है। केवल 2024-25 के पहले दस महीनों में डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी ने नागरिकों के 4,245 करोड़ रुपये हड़प लिए हैं और देश भर में ऐसे 2.4 मिलियन मामले सामने आए हैं। पिछले साल की तुलना में इसमें 67 प्रतिशत का तेज उछाल आया है और हर धोखाधड़ी के पीछे नुकसान, भ्रम और विश्वास टूटने की एक कथा छिपी है। भारत में डिजिटल धोखाधड़ी अब केवल नौसिखियों द्वारा हैकिंग या फिशिंग प्रयासों तक सीमित नहीं है। अब इसमें अनेक प्रकार की आपराधिक रणनीतियां शामिल हो गई हैं जिनका विस्तार फर्जी निवेश योजनाओं से लेकर धोखाधड़ी वाले 'लोन एप' और 'मैलवेयर से भरी' वेबसाइटों, फर्जी प्रस्तुतीकरण ओर पुलिस या बैंक अधिकारियों के नाम से की जाने वाली फर्जी फोन कालों तक है। इनमें से अनेक घोटालों की जड़ में 'मनी म्यूल' खाते हैं जिनको अनजान लोगों या फर्जी पहचानों के नाम पर खोला जाता है और वे चोरी किया पैसा जमा करने के काम आते हैं। ऐसी धोखाधड़ी में तेज वृद्धि के तीन कारण हो सकते हैं। पहला, भारत में डिजिटल वित्तीय सेवाओं का तेज विस्तार है जिसमें खासकर यूपीआई, मोबाइल वैलेट और इंटरनेट बैंकिंग शामिल हैं, जबकि जनता में डिजिटल सुरक्षा की समझदारी में इतनी तेजी से वृद्धि नहीं हुई है। दूसरा, कानून लागू करने वाली एजेंसियों के पास समुचित संसाधनों की कमी है जिसके कारण वे अक्सर साइबर अपराध की जटिल और विकसित होती प्रकृति से निपटने में पूर्णतः सक्षम नहीं होती हैं।

इसके साथ ही सामाजिक-आर्थिक दबाव की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जिसका कारण टेक-सेवी नौजवानों में उच्च बेरोजगारी है जो कभी-कभी उनको 'डार्क वेब' और अवैध आनलाइन गतिविधियों में धकेल देती है। भारत अब 'वर्ड साइबर क्राइम इंडेक्स' में वैश्विक रूप से दसवें स्थान पर है। इससे न केवल बड़ी संख्या में पीड़ितों, बल्कि बड़ी संख्या में धोखेबाजों का भी पता चलता है। इससे समस्या की गंभीरता तथा इससे तत्काल निपटने की आवश्यकता भी सामने आती है। इस व्यापक स्तर पर फैली चुनौती का सामना करने के लिए नियामकों और अधिकारियों ने व्यवस्था को मजबूत करना शुरू किया है। लेकिन जब तक नीति-निर्माता, बैंक, नियामक और नागरिक एकजुट होकर जागरूकता फैलाने तथा अपराधियों को पकड़ने में सहयोग नहीं करते हैं तब तक देश को इस व्यापक समस्या से मुक्ति नहीं दिलाई जा सकती है। देश के तेजी से इस सर्वाधिक खतरनाक जाल में फंसने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ संघर्ष केवल तकनीकी या वित्तीय संघर्ष नहीं है, बल्कि यह हर ईमानदार भारतीय को सुरक्षा देने का संघर्ष है जो बेहतर तथा ज्यादा परस्पर जुड़ाव वाले भविष्य में विश्वास करता है। हमें याद रखना चाहिए कि तत्काल भुगतानों के इस युग में धोखेबाज भी बस हमसे केवल एक क्लिक दूर हैं।

विकसित भारत का मोदी मिशन

आने वाले 20 वर्षों में यदि हम आर्थिक विकास दर 8-11 प्रतिशत रखने में कामयाब रहते हैं तो निश्चित तौर पर आजादी की 100 वीं वर्षगांठ 2047 तक देश 35 ट्रिलियन डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था होगा।

प्रो विवेक सिंह
(लेखक, अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

विश्व पटल पर भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत की विकास दर दुनिया में सर्वाधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था 4.2 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2014 से 2025 के बीच, 11 वर्षों में देश ने उल्लेखनीय आर्थिक और सामाजिक प्रगति दर्ज की है। इस अवधि में कई अन्य देशों की प्रगति हुई है लेकिन भारत के प्रगति खासकर आर्थिक प्रगति भिन्न है। राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण होता रहा है और आगे भी होता रहेगा परन्तु भारत के परिपेक्ष में 2014 का सत्ता परिवर्तन को अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। 2014 का ऐतिहासिक जनादेश स्पष्ट था कि भारत अब स्वयं को विकसित भारत के रूप में देखना चाहता है। आर्थिक तरक्की का केंद्र बनना चाहता है जिसमें आशातीत सफलता मिली है।

नरेंद्र मोदी सरकार के विकासोन्मुख निर्णयों के कारण भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आगामी वर्षों में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 से 9 प्रतिशत तक बनी रहेगी। इसका श्रेय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र है जो भारत के 145 करोड़ लोगों को एक सूत्र में बांध देता है। मोदी सरकार का समावेशी विकास पर जोर है। मोदी सरकार का लक्ष्य विकसित भारत 2047 साकार होता दिख रहा है।

विकसित भारत 2047 का लक्ष्य स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है। यह महत्वाकांक्षी मिशन भारत को आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित है। लक्ष्य प्राप्ति मुश्किल है परन्तु असंभव बिल्कुल नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 के अंत तक 4.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 35 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है।

भारत को 2047 तक 35 ट्रिलियन डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए 20 साल तक जीडीपी ग्रोथ 8 से 11 प्रतिशत होनी अनिवार्य है जिसके लिए समग्र और समन्वित विजन की आवश्यकता है। 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था साल 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर, 2040 तक 19 और 2047 तक 35 ट्रिलियन डॉलर रहने का अनुमान है।

कोई भी विजन बिना मिशन के नहीं प्राप्त किया जा सकता। भारत को 35 ट्रिलियन डॉलर कि विकसित अर्थव्यवस्था के विजन प्राप्ति का लक्ष्य मोदी मिशन ऑफ डेवलप्ड इंडिया से संभव होगा। किसी भी देश को वस्तु और सेवाओं को बेंचने के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। बाजार से ही मांग होती है जिसकी पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। भारत दुनिया के लिए आज सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। हर देश भारत को दुनिया के सबसे बड़े बाजार के रूप में देख रहा है।

देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा ताकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति देश खुद कर सके। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम देश को आर्थिक गति देने में ईंधन का काम कर रहे हैं। भारत युवाओं का देश है। देश की 67 प्रतिशत से अधिक आबादी युवा है। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जो वर्तमान में 56 प्रतिशत है उसे आने वाले 10 सालों में 70 प्रतिशत तक ले जाने की आवश्यकता है। मैन्युफैक्चरिंग, छोटे उद्योगों और सर्विस सेक्टर में व्यापक रोजगार के अवसर सृजित करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। आने वाले कई दशकों तक भारत दुनिया का शीर्ष ग्लोबल वर्कफोर्स कंट्रीब्यूटर बना रहेगा।

भारत को विकसित देश बनाने के लिए व्यापक ढांचागत एवं नीतिगत सुधार करने होंगे। कैपेक्स एक्सपेंडिचर पिछले 10 सालों में 6 गुना बढ़ाया गया है जिसे 2030 तक 15 लाख करोड़ रुपए करने की आवश्यकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, एमएसएमई जिनकी संख्या 6.3 करोड़ और पूंजीगत व्यय पर विशेष ध्यान देना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रक्षा और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में स्वदेशी उत्पादन बढ़ाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। नागरिकों और कंपनियों पर पड़ने वाले टैक्स भार को और कम करना चाहिए। टैक्स स्लैब तीन से अधिक नहीं होने चाहिए।

मेक इन इंडिया पर मेक फॉर वर्ल्ड के सफल क्रियान्वयन से भारत का निर्यात कई गुना बढ़ सकता है। हमारा कुल निर्यात 825 बिलियन डॉलर है जो जल्द 1 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। 2047 तक देश का निर्यात 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। अव्यवहारिक एवं अनावश्यक नियम कानूनों से निजात पाने की आवश्यकता है जिससे कारोबारी सुगमता बढ़ेगी और अनुपालन लागत कम होगी। भारत को आने वाले विदेशी निवेश पर भी इसका व्यापक सकारात्मक असर पड़ेगा। पिछले 10 वर्ष में एफडीआई इनफ्लो 668 बिलियन डॉलर रहा है।

डिजिटल क्रांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंटरनेट यूजर्स की संख्या है। 2010 में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या मात्र 8% था जिसका 2025 तक 55 प्रतिशत तक पहुंचना काबिले तारिफ है। डिजिटलाइजेशन के लिए 6.92 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर देश में बिछाया गया है। आज देश में 94 करोड़ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर हैं। दुनिया का 49 प्रतिशत डिजिटल ट्रांजेक्शन अकेले भारत में होता है। 2024 में 172 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन होना भारत के लिए गर्व की बात है। डिजिटल क्रांति के बाद अब डिजिटल क्रांति-2 की जरूरत है। 2030 तक इंटरनेट पेनिट्रेशन को 70 प्रतिशत तक ले जाने की आवश्यकता है।

टूरिज्म का भारत के जीडीपी में 5 प्रतिशत का योगदान है और टूरिज्म सेक्टर से 7.6 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का अहम योगदान है। भारत में टूरिज्म उद्योग की अनंत संभावनाएं हैं। कल्चरल टूरिज्म, रिलिजियस टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, हेरीटेज टूरिज्म इत्यादि को बढ़ावा दिया जा सकता है। भारत के हिस्सेदारी वैश्विक टूरिज्म में 1.8 प्रतिशत है जिसे 2040 तक 10 प्रतिशत तक लाने की दिशा में प्रयास होने चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पर्यटन उद्योग से जोड़ा जाना चाहिए। विलेज टूरिज्म को प्रमोट करने से देश को फायदा होगा।

उच्च शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव हुए हैं। आज देश में 70,683 उच्च शिक्षा संस्थान, 1,334 विश्वविद्यालय, 51,959 कॉलेज, 23 आईआईटी और एम्स, 2,045 मेडिकल कॉलेज हैं। शिक्षा और कौशल विकास पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत व्यापक बदलाव अभी तक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक जमीनी स्तर पर परिलक्षित नहीं हो रहे हैं। शिक्षा को भारतीय ज्ञान, भारतीय भाषा, रोजगार, इंटर्नशिप, कौशल विकास, उद्यमिता और अनुसंधान से सीधा जोड़ना होगा।

राज्यों की अर्थव्यवस्था देश के अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ी है। राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। 2047 तक देश की अर्थव्यवस्था को 35 ट्रिलियन डॉलर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था का कम से कम 5 ट्रिलियन डॉलर होना नितांत आवश्यक है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग में अधिक निवेश की आवश्यकता है। अगले पांच वर्षों में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में रिसर्च और निवेश बढ़ाने से कच्चे तेल के आयात के लिए विदेशों पर देश की निर्भरता कम होगी। आज के दौर में वैश्विक अनिश्चितता और जियो-पोलिटिकल टेंशन से नहीं बचा जा सकता है। दुनिया के ताकतवर देशों और ट्रेडिंग ब्लॉक्स से आर्थिक और सामरिक साझेदारी के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते लगातार करते रहने होंगे।

जिस गति से देश का आर्थिक विकास हो रहा है वह दुनिया में सर्वाधिक है। जरूरत विकास गति को और तेज करने की है। आने वाले 20 वर्षों में यदि हम आर्थिक विकास दर 8-11 प्रतिशत रखने में कामयाब रहते हैं तो निश्चित तौर पर आजादी की 100 वीं वर्षगांठ 2047 तक देश 35 ट्रिलियन डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था होगा।

सच्चे रूपांतरण का आतंरिक संकल्प

> **यह समझना महत्वपूर्ण है कि आत्म-परिवर्तन के मार्ग पर, श्रद्धांजलि और प्रशंसा पाने, प्रसिद्धि और गौरव प्राप्त करने के प्रलोभन अविश्वसनीय रूप से मजबूत होंगे।**

ब्रह्मकुमार निकुंज
(लेखक, आध्यात्मिक उपदेशक हैं)

जहां चाह है, वहां राह है एक जानी-पहचानी कहावत है, और जबकि इसका सामान्य अर्थ व्यापक रूप से समझा जाता है, बहुत से लोग आत्म-परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में इसकी गहन उपयोगिता को नहीं समझते हैं। किसी व्यक्ति का आंतरिक परिवर्तन आंतरिक रूप से उसकी इच्छाशक्ति की ताकत और उसकी आत्मा की दृढ़ता से जुड़ा हुआ है।

यदि कोई व्यक्ति, एक मजबूत और अडिग इच्छाशक्ति के साथ, नकारात्मक विचारों को दूर रखने या किसी विशिष्ट बुरे व्यवहारिक प्रतिक्रिया में लिप्त होने का फैसला करता है, तो आंतरिक परिवर्तन में आंशिक या पूर्ण सफलता प्राप्त की जा सकती है; अन्यथा, व्यक्ति बार-बार लड़खड़ाता है, जल्दी या बाद में हतोत्साहित हो जाता है, और बदलाव का प्रयास छोड़ देता है।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि आत्म-परिवर्तन के मार्ग पर, श्रद्धांजलि और प्रशंसा पाने, प्रसिद्धि और गौरव प्राप्त करने के प्रलोभन अविश्वसनीय रूप से मजबूत होंगे। लिंग आकर्षण व्यक्ति के दिमाग पर एक शक्तिशाली खिंचाव डालेंगे, और गुस्से को शांत करने के लिए स्थितियाँ बहुत उत्तेजक या बहुत अधिक होंगी। माया के इन सूक्ष्म तरीकों से व्यक्ति ठगा हुआ महसूस कर सकता है।

इसलिए, दृढ़ रहना आवश्यक है और इन तूफानों का चट्टान की तरह सामना करते हुए खुद से कहना चाहिए: यह मेरी ईमानदारी और सम्मान का सवाल है। मैंने खुद से वादा किया है कि मैं अब अपनी इस नकारात्मक आदत या उस व्यक्तित्व विशेषता का कठपुतली या गुलाम नहीं बनूंगा। क्या मैं अपना वादा तोड़ने जा रहा हूं? क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने वचनों पर कायम नहीं रहता या जिसके वादे का कोई मूल्य नहीं है? क्या यह ईश्वर द्वारा मुझ

पर रखे गए भरोसे का उल्लंघन नहीं होगा, या ईश्वर से किया गया मेरा वादा नहीं होगा कि मैं इस घृणित कार्य में शामिल हो जाऊं जिसे मैंने त्यागने की कसम खाई थी? क्या किसी भी आत्म-सम्मान वाले व्यक्ति को अपना वादा तोड़ना और वह करना शोभा देता है जिसे उसने आध्यात्मिक रूप से घृणित और नैतिक रूप से बुरा माना है? आत्म-परिवर्तन के मार्ग पर इस तरह की आत्म-चर्चा बहुत सहायक होती है। यह देखा गया है कि मनुष्य के आध्यात्मिक विनाश की एक कमजोरी यह है कि वह कुछ निर्णयों को लागू करने में देरी करता है, भले ही वे स्वेच्छा से लिए गए हों और उसके स्थायी लाभ के लिए हों।

ऐसा विशेष रूप से तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने किसी भी नकारात्मक गुण को प्रकट होने से रोकने के लिए अपने शुरुआती कदमों में विफल हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप, असफल होने की स्थिति में, वह निराश महसूस करता है और अपना आत्मविश्वास खो देता है, यह सोचकर कि उसके सारे प्रयास धुएं में समा जाएंगे। अपनी इच्छाशक्ति खो देने के बाद, वह प्रयास छोड़ देता है और खुद से कहता है- मैं इसे हमेशा के लिए नहीं छोड़ रहा हूं। मैं इस बुराई के खिलाफ़ लड़ना शुरू करूंगा जो मेरे अंदर समा गई है, लेकिन शायद, अभी समय नहीं आया है। मैं इसे किसी और शुभ और यादगार दिन पर शुरू करूंगा।

और जब वह दिन आखिरकार आता है, तो वह सोचता है कि इस दिन के लिए, वह नए सिरे से शुरुआत करेगा। लेकिन फिर से एक गड़बड़ है। इसलिए, वह खुद से कहता है। मुझे इसे अगले महीने की पहली तारीख से शुरू करना चाहिए। उस दिन वह फिर से शुरू करता है। लेकिन, जिसने यह निश्चय नहीं किया है कि वह अब सभी बाधाओं के बावजूद इसे जारी रखेगा, वह बार-बार अपनी हार स्वीकार करेगा और अपना हौसला खोकर या तो हमेशा के लिए प्रयास छोड़ देगा या फिर किसी और शुभ दिन तक इसे टाल देगा! ऐसे लोगों को बार-बार असफल होने की आदत हो जाती है और इस प्रक्रिया में वे कमजोर हो जाते हैं।

इसलिए, आइए हम एक दृढ़ प्रतिज्ञान करें और अपने आप से कहें: भले ही आसमान गिर जाए, मैं अब नहीं गिरने वाला। मेरी प्रतिज्ञा इस्पात से भी कठोर है। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं डगमगाने वाला नहीं हूं और अब महानता से महानतम ऊंचाइयों की ओर बढ़ूंगा! जब व्यक्ति दृढ़ निश्चयी और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ आत्म-परिवर्तन के लिए काम करते हैं, तभी समाज में बदलाव आता है। आत्म-परिवर्तन की इस व्यक्तिगत जिम्मेदारी को साझा करने के अलावा, विश्व-परिवर्तन का कोई अन्य ज्ञात तरीका नहीं है।

प्रत्येक व्यक्ति के दिल और दिमाग से शुरू होने वाला यह लहरदार प्रभाव धीरे-धीरे परिवारों, समुदायों और अंततः राष्ट्रों को बदलने के लिए फैलता है। आत्म-जागरूक, नैतिक रूप से आधारित व्यक्तियों से बना समाज स्वाभाविक रूप से शांति, न्याय और सतत प्रगति को बढ़ावा देता है। व्यक्तिगत इच्छाओं की इस सामूहिक जागृति में ही एक बेहतर दुनिया का सच्चा वादा निहित है, जो सार्वभौमिक कल्याण और सद्भाव के लिए एक वास्तविक मार्ग प्रदान करता है। इस प्रकार, आत्म-परिवर्तन की यात्रा एक समृद्ध, दयालु वैश्विक सभ्यता का आधार बन जाती है।

आप की बात

मोदी-कार्नी वार्ता

भारत के अधिकांश देशों के साथ मित्रवत संबध है। वर्तमान भारत मोदी की आत्मनिर्भरता व आत्मसम्मान के रास्ते पर चलने वाला देश है। जी-7 शिखर सम्मेलन में मोदी-कार्नी वार्ता भारत और कनाडा के बीच संबंधो को स्थिरता देने और बेहतर बनाने के लिए रचनात्मक कदम उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी निज्जर की हत्या को लेकर दोनों देशों के बीच संबंध बहुत निचले स्तर पर पहुंच गए थे। मोदी-कार्नी वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने लोकतान्त्रिक मूल्यों, क़ानून व शासन के प्रति सम्मान तथा संप्रभुता अखंडता के सिद्धांतों को बनाये रखने की प्रतिबद्धता के आधार पर द्विपक्षीय संबंधो का महत्व बताया है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच सफल वार्ता से भारत-कनाडा संबंधों में मौजूदा खटास दूर होकर उनमें बेहतरी का रास्ता खुला है। उल्लेखनीय है कि कनाडा की जनता ने भारत-विरोधी व खालिस्तानी अलगाववादी तत्वों का हालिया चुनाव में बिल्कुल सफाया कर दिया है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने इस जनादेश को अच्छी तरह समझा है। द्विपक्षीय संबंधों में बेहतरी में अनिवासी भारतीयों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है जिन्होंने कनाडा में सम्माननीय स्थान प्राप्त किया है।

- योगेश जोशी, बड़वाह

सस्ती राजनीति

देश की सुरक्षा और सैन्य कार्रवाई जैसे सामरिक महत्व के मुद्दों पर सस्ती राजनीति किया जाना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि राष्ट्रीय एकता को भी नुकसान पहुंचाता है। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा में पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य जवाबी कार्रवाई पर चर्चा के दौरान यह प्रवृत्ति फिर से देखने को मिली। सेना की बहादुरी की प्रशंसा तो की गई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जैसे अहम सैन्य अभियान का उल्लेख तक नहीं किया गया। यह सेना के योगदान के साथ अन्याय तथा राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों को राजनीतिक चश्मे से देखने की प्रवृत्ति उजागर करता है। 1971 के युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विजय का खुलकर चुनावी लाभ उठाया था। आज भी विपक्ष, खासकर कांग्रेस किसी न किसी बहाने राष्ट्रीय उपलब्धियों को कमतर आंकने की कोशिश करती है। परंतु सोशल मीडिया के युग में जनता अब जागरूक हो चुकी है और अक्सर ऐसे बयान खुद जनता के बीच में ही आलोचना का शिकार बनते हैं। विपक्ष शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार का अंधविरोध राष्ट्रीय ढांचे को कमजोर करने का कार्य भी करता है। इससे पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश को फायदा उठाने का हौसला मिलता है।

- सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

ईरानी शासकों का घमंड

पाकिस्तान को अपनी न्यूक्लीयर शक्ति का तो ईरान को उससे भी ज्यादा गुमान हो रहा है। पाक को भारत ने समझाया कि अपने आतंकियों और उनके आकाओं पर कंट्रोल करे पर वह नहीं माना और बारम्बार समझाने पर भी घिनौनी हरकतें कर बैठा। आखिर उसका जवाब ऑप्रेशन सिन्दूर के जरिये पाक को देते ही वह युद्धविराम के लिए गिड़गिड़ाने लगा और सिंधु जल संधि रद्द करने से पानी मांगने लगा। ईरान को भी 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद घमंड हो गया हैऔर उसने हूती, हमास, हिजबुल्ला तथा सीरिया में अपनी मुहरा असद सरकार के माध्यम से इस्राइल के अस्तित्व को खतरे में डालने का प्रयास किया। असद सरकार का तो सफाया हो ही गया, अब इस्राइल ने हूती, हमास और हिजबुल्ला को भी बहुत कमजोर कर दिया है। इसके बावजूद ईरान अपना नाभिकीय शक्ति बनने का सपना और इस्राइल को दुनिया के मानचित्र से समाप्त करने का घमंड छोड़ने को तैयार नहीं है। विडंबना है कि ईरानी जनता व खासकर ईरान की महिलाओं और लड़कियों को कट्टरपंथी इस्लामवादी तानाशाहों के हाथों अपनी स्वतंत्रता गंवानी पड़ी है। लगता है कि ईरान में शासकों का घमंड टूटने तथा महिलाओं की आजादी का समय आने वाला है।

शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

सराहनीय निर्णय

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण-एनएचएआई द्वारा एक वर्ष या 200 यात्राओं के लिए केवल 3 हजार रुपये का भुगतान लेने का निर्णय निजी वाहन चालकों के लिये निश्चित ही यह एक सुखद समाचार है। जहाँ घर से निकलते और कुछ दूर चलते ही टोल टैक्स का मीटर घूमने लगता था वहीं प्रतिमाह यह खर्च मात्र 250 रुपये होगा। अभी किसी भी यात्रा पर निकलने से पहले जनता को अपना फास्टैग रिचार्ज करना पड़ता है, परंतु नई नीति के लागू होने से इस झंझट से मुक्ति मिलेगी, यात्रा सुगम होगी और अन्य समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा । हालांकि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी अपने कार्य और निर्णयों से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं पर इस बार वाकई अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सुखद निर्णय लिया गया है। नितिन गडकरी ने भविष्य में टोल टैक्स शून्य होने की भी कल्पना की है और शायद उनका यह निर्णय उसी दिशा में एक कदम है। देखना होगा कि एनएचएआई इससे आय में होने वाली कमी कैसे पूरी करता है और राजमार्गों का निर्माण और तेज होता है। यह निर्णय मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धि है।

- मनोज पुरुषार्थी, मेरठ

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से **responsemail.hindipioneer@gmail.com** पर भी भेज सकते हैं।

हिन्दुस्तान
1936

कनाडा को एहसास

भारत-कनाडा संबंधों में सुधार के संकेत स्वागतयोग्य हैं। दोनों देशों के बीच तल्खी अब घटने लगी है और इसी कड़ी में कनाडा की शीर्ष खुफिया एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार कर लिया है कि कनाडा की धरती से खालिस्तानी चरमपंथी सक्रिय हैं। कनाडा की यह स्वीकारोक्ति महत्वपूर्ण है। यह कनाडा का करीब पचास साल पुराना स्याह पहलू है कि वहां भारत विरोधी चरमपंथियों का एक छोटा समूह लगातार सक्रिय रहा है। कभी कनाडा की सरकार इस सच को मानती है, तो कभी आंखें मूंद लेती है। उसकी पिछली सरकार ने इस सच को नजरअंदाज किया, इसीलिए दोनों देशों के संबंधों में खटास घुल गई थी। अब कनाडा यह मान रहा है कि चरमपंथियों का एक छोटा समूह कनाडा की धरती का इस्तेमाल हिंसक कृत्यों को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। यह समूह कनाडा में चरमपंथ का वित्त-पोषण करके और अपनी साजिशों के जरिये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। इतना ही नहीं, कनाडा की खुफिया एजेंसी ने यह भी माना है कि यह समूह मुख्य रूप से भारत को निशाना बनाता है।

गौर कीजिए, कनाडा से निकली यह बात हवा-हवाई नहीं है। कनाडा की सुरक्षा खुफिया सेवा (सीएसआईएस) ने अपनी संसद को सौंपी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में यह माना है। यह स्वीकारोक्ति भी विचारणीय है कि इस तरह की गतिविधियां राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसक उग्रवाद के अंतर्गत आती हैं। निस्संदेह, हम यह साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि कनाडा में चरमपंथी खुद को राजनीतिक रूप से मजबूत करने में जुटे हैं, ताकि अलगाववाद की उनकी दलील को मुख्यधारा में जगह मिले। अगर कनाडा की खुफिया एजेंसी इस बात को समझ रही है, तो यह वास्तव में भारत के लिए सकारात्मक है। विगत कम से कम एक वर्ष से जिस तरह की दुश्मनी ये चरमपंथी संगठन निभा रहे हैं, उससे खुद कनाडा की छवि को नुकसान पहुंचा है। चरमपंथियों की राजनीति या साजिश कनाडा को हर तरह से नुकसान पहुंचा रही है। दोनों देश एक-दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोनों के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और दोनों के आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं। सामाजिक रूप से भी कनाडा हमारे अनुकूल है। वहां 18 लाख से ज्यादा लोग भारतीय मूल के हैं और उन्हें वहां मिल-जुलकर भारतीय विविधता का आदर्श पेश करना चाहिए। कनाडा में रहते हुए मजहब की बुनियाद पर सामुदायिक विभाजन पैदा करना निंदनीय है। चंद ऐसे सिख हैं, जो गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्हें सुधारना चाहिए। कनाडा की खुफिया एजेंसी के खुलासे से इन मुट्ठी भर अलगाववादियों को माकूल जवाब मिला है और उनके सुधर जाने में ही सबकी भलाई है।

कनाडा की खुफिया एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में यह मान लिया है कि उसके यहां मौजूद एक अलगाववादी चरमपंथी समूह मुख्य रूप से भारत को निशाना बनाता है।

वैसे, कनाडा सरकार को भी अपनी नीतियों या राजनीति में सुधार करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के सत्ता में आने के बाद हालात बदले हैं। कनाडा ज्यादा व्यावहारिक हुआ है। उम्मीद करनी चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह से भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ा था, उसे सुधारने की दिशा में कार्नी अपने कदम बढ़ा चुके हैं। बेशक, भारत के साथ रहने में कनाडा को ज्यादा फायदा है। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र कनाडा पढ़ने जाते हैं, पर कनाडा के रूखे व्यवहार की वजह से मुंह फेरने लगे हैं। एक साल पहले वहां 44 हजार से ज्यादा भारतीय छात्र गए थे और आज संख्या 30 हजार के आस-पास ठहर गई है। समग्रता में संदेश स्पष्ट है, कनाडा सरकार को सच्चाई के अनुरूप उदारता का परिचय देना चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 20 जून, 1950

रुई की मूल्य-वृद्धि

पिछले सप्ताह बंबई में कपड़ा सलाहकार बोर्ड की बैठक हुई थी और उसमें उद्योग और रसद मंत्री श्री हरेकृष्ण महताब ने भी भाग लिया था। बोर्ड ने सरकार से सिफारिश की थी कि रुई के मौजूदा अधिकतम मूल्यों में 150 रु. की वृद्धि कर दी जाये। सरकार ने बोर्ड की सिफारिश को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है और अपने इस निर्णय की घोषणा भी बड़ी फुर्ती के साथ कर दी है। अगर सरकार समस्त प्रस्तुत प्रश्नों पर अपने फैसले इतनी ही फुर्ती के साथ कर दिया करे, तो बहुत कुछ लाभ हो सकता है। रुई का मौजूदा अधिकतम मूल्य प्रति खंडी (एक खंडी 784 पौंड की होती है) 620 रु. था। अब वह 770 हो जायेगा। इस मूल्य-वृद्धि का देश के आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह विचारणीय है। सरकार ने रुई के जो भाव नियंत्रण कर रखे थे, उस पर मिलों को रुई मिल नहीं रही थी और उन्हें अधिक मूल्य देकर अपनी आवश्यकता की रुई खरीदनी पड़ती थी। सरकार ने रुई के अधिकतम मूल्य में वृद्धि करके अस्वाभाविक स्थिति का अंत कर दिया है और वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है।

देश का कपड़ा उद्योग एक प्रमुख उद्योग है। वह केवल देश की कपड़े की आंतरिक अवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करता, बल्कि विदेशों को कपड़े का निर्यात करता है और विदेशी विनिमय अर्जित करने में सहायक होता है। कपड़े की मिलें अपना उत्पादन तभी बराबर जारी रख सकती हैं, जब उनको रुई जरूरत के मुताबिक मिलती रहें। कपड़ा मिलों को पिछले कुछ अर्से में यह शिकायत पैदा हो गई थी कि उन्हें रुई आवश्यक मात्रा में नहीं मिलती। रुई के अभाव में कई मिलों ने काम के घंटे घटा दिये थे और कुछ ने तो कुछ समय के लिए काम बिल्कुल ही बंद कर दिया था।

रुई का उत्पादन फिलहाल देश में आवश्यकता से कम ही हो रहा है। देश को प्रतिवर्ष 40 लाख गांठ ईस्ट इंडियन रुई की आवश्यकता है, किन्तु देश में उत्पादन 28 लाख गांठ से अधिक नहीं होता। जो कमी रह जाती है, उसकी पूर्ति विदेशों से रुई मंगाकर करनी होती है। पाकिस्तान से रुई मिल सकती थी, किन्तु भारत और पाकिस्तान के रुपयों के मूल्य के संबंध में झगड़ा उठ खड़ा होने से यह सूत्र प्रायः बेकार हो गया है।

मन से मानिए महिलाओं को बराबर

माजा दारूवाला | मुख्य संपादक, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

वैश्विक लैंगिक विषमता रिपोर्ट में भारत को 148 देशों की सूची में 131वें स्थान पर रखा गया है। हमें तरक्की करनी है, तो महिलाओं को बराबरी के स्तर पर लाना ही होगा।

अपने देश में एक सच्चाई को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह सच्चाई हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक विषमता रिपोर्ट के आंकड़ों से निकलकर सामने आई है। इस रिपोर्ट में भारत को 148 देशों की सूची में 131वें स्थान पर रखा गया है। लैंगिक समानता के लिहाज से यह ब्रिक्स देशों और दक्षिण एशिया के अपने ज्यादातर पड़ोसियों से भी पीछे है।

यह पिछड़ापन इसलिए नहीं है कि भारत में लैंगिक बराबरी के खिलाफ काम हो रहा है, बल्कि इसलिए है कि अन्य देशों में इस विषमता की खाई को तेजी से पाटा जा रहा है। साफ है, भारत को अगर तरक्की करनी है, तो महिलाओं को बराबरी के स्तर पर लाना जरूरी होगा। इस मामले में अच्छी और बुरी, दोनों तरह की खबरें हैं। अच्छी खबर यह है कि शिक्षा और सियासत के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है। 97 प्रतिशत पढ़ी-लिखी महिलाएं पुरुषों से बराबरी की ओर बढ़ रही हैं। भारत में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण की रफ्तार चीन से अधिक और ब्राजील के बेहद करीब है। यह तरक्की शायद पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के कारण हुई है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी 45 प्रतिशत तक है। हालांकि, देश की संसद में अब तक के इतिहास में सर्वाधिक 14 प्रतिशत महिलाएं ही पहुंच पाई हैं।

महिलाओं की कमजोर आर्थिक भागीदारी के कारण भारत दुनिया के पांच निचले देशों में है। भारी बेरोजगारी के माहौल में पुरुषों के हाथ ही ज्यादा नौकरियां आती हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, महिला श्रम की भागीदारी दर में पिछले दशक में ऐतिहासिक गिरावट आई है और सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी में स्त्रियों का योगदान 20 प्रतिशत से भी कम रह गया है। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले एक-तिहाई से भी कम कमाती हैं और निर्णय लेने में उनकी भूमिका बहुत कम है।

यह केवल लैंगिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह आर्थिक महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट का आकलन है कि यदि भारत में लैंगिक समानता होती, तो 2025 के अंत तक इसके जीडीपी में 770 अरब डॉलर का इजाफा हो सकता था। लेकिन मौजूदा दर से वहां तक पहुंचने में 135 साल लग सकते हैं। इस असलियत को देखते हुए हमारे नीति-नियंताओं को महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में तत्काल बदलाव करने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को बार-बार कहा है कि महिलाओं को नेतृत्वकारी भूमिका में लाने पर ही प्रगति संभव है।

आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने वाली नीतियों व कार्यक्रमों का सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों में अधिकतम किया जाना चाहिए। इसमें हर किसी की भूमिका है, लेकिन इस बदलाव को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की है। हाल में भारतीय प्रशासनिक सेवा में 41 प्रतिशत महिलाएं चयनित हुई हैं और भारतीय विदेश सेवा में 38 प्रतिशत। ये आंकड़े बेहद उत्साहजनक हैं। हालांकि, इन दोनों सेवाओं में अभी कितनी महिलाएं कार्यरत हैं, यह आंकड़ा अस्पष्ट है। सशस्त्र बलों में महिलाएं तीन प्रतिशत से भी कम हैं और सभी पुलिस बलों को मिला दें, तब भी उनकी भागीदारी महज 12 प्रतिशत तक पहुंचती है। यहां तक कि जिन शीर्ष संस्थाओं पर लैंगिक बराबरी सुनिश्चित करने का दारोमदार है, वे स्वयं इस मामले में बहुत पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2021 में 33 न्यायाधीशों में एक समय चार महिलाएं थीं, जो सर्वोच्च न्यायपालिका के इतिहास में सर्वाधिक संख्या है। अभी वहां मात्र एक महिला न्यायाधीश हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूरे इतिहास में कभी भी एक से अधिक महिला सदस्य नहीं रही। वह भी शायद इसलिए कि इसके कानून में 'कम से कम एक महिला सदस्य' के होने की बाध्यता है।

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के कई काम चल रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में उनके नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों, लक्षित बचत योजनाओं में उनकी बढ़ी भागीदारी और कम ब्याज वाले ऋण के आवंटन ने आर्थिक आधार को बदलना शुरू कर दिया है। केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक सरकार समर्थित कार्यक्रमों ने लाखों ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनने में मदद की है। जनगणना, परिसीमन के बाद संसद व विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होने से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में भी उछाल आने वाला है। लाखों महिलाएं पहले से पंचायती राज संस्थाओं में हैं, यानी राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित स्त्रियों की कमी नहीं है।

ब्रिटेन में लेबर पार्टी द्वारा महिलाओं को शॉर्टलिस्ट करने पर जोर देने से दो दशकों में महिला प्रतिनिधित्व 10 से बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया है। व्यवस्था समाज को आकार देती है और इसके मूल्यों व पूर्वाग्रहों को अगली पीढ़ियों तक ले जाती है। पितृ-सत्तात्मक समाज और परंपराओं के कारण महिलाओं की भागीदारी बाधित होती है। संस्थाएं यह मानकर चलती हैं कि पुरुष-प्रधान समाज तटस्थ, निष्पक्ष व योग्यता पर आधारित है। मगर जब महिलाएं अपने सामाजिक व जैविक सच पर गौर करने की मांग करती हैं, तो उनको भोग-विलास संबंधी मांग के रूप में देखा जाता है।

लैंगिक गैर-बराबरी की वास्तविकता से मुंह मोड़ने के कारण बहुत कम महिलाएं शीर्ष तक पहुंच पाती हैं। जिला अदालतों में 38 प्रतिशत महिला न्यायाधीश हैं, जबकि उच्च न्यायालयों में केवल 14 प्रतिशत। पुलिस विभाग में अधिकारी स्तर पर केवल आठ प्रतिशत महिलाएं हैं। हालांकि, निजी क्षेत्र में मध्यम क्रम के प्रबंधन स्तर पर उनकी संख्या ठीक-ठाक है। फिर भी, देश की फॉर्च्युन-500 कंपनियों में से केवल दो प्रतिशत ही महिलाएं चला रही हैं।

समानता का मतलब है समता और संतुलन। इसके लिए किसी भी लैंगिक समुदाय की कहीं पर भी 50-60 प्रतिशत से अधिक भागीदारी नहीं होनी चाहिए। यहां तो 33 प्रतिशत आरक्षण देने में ही हीला-हवाली है, मानो समान भागीदारी की मांग करना हिमाकत हो। उनकी धीमी वृद्धि को अक्सर प्रगति कहा जाता है, असल में यह महिलाओं को उनकी जगह देने की अनिच्छा ही दर्शाती है। बदलाव की जिम्मेदारी संस्थानों पर है और भागीदारी बढ़ाने का मतलब है कि सभी संस्थानों में यह तत्काल और सायास बढ़े, ताकि मौजूदा कमियां दूर की जा सकें। यह काम किसी अनुकंपा और अनुग्रह की मानसिकता से नहीं, लंबे समय से वंचित रखे गए अधिकारों की क्षतिपूर्ति के रूप में होना चाहिए।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

पहाड़ों पर एक से ज्यादा पैदल मार्ग तैयार रखना चाहिए

वीरेंद्र कुमार पैन्यूली | सामाजिक कार्यकर्ता

खराब मौसम, भूस्खलन और दुर्घटनाओं की वजह से केदारनाथ पैदल मार्ग को बार-बार रोकना पड़ रहा है। अभी 15 जून को ही जंगलचट्टी के पास मार्ग पर भारी पत्थर गिरने से पैदल यात्रा रोक दी गई। इस बार 2 मई को यात्रा के पहले ही दिन हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। बार-बार यह जरूरत महसूस हो रही है कि भीड़भाड़ व दुर्घटनाओं से बचने के लिए केदारनाथ पुरी को वैकल्पिक मार्गों से जोड़ने की जरूरत है।

लोग अभी भूले नहीं हैं। 31 जुलाई 2024 की रात केदारनाथ पैदल मार्ग में बादल फटने से जंगलचट्टी, भीमबली, लिंचोली तथा रामबाड़ा के क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ था। भीमबली पुलिस चौकी के पास इसका लगभग 30 मीटर हिस्सा ढह गया था। दो पुल भी बह गए थे। जंगलचट्टी में 60 मीटर व गौरीकुंड में घोड़ा पड़ाव के पास 15 मीटर सड़क बिल्कुल खत्म हो गई थी। लगभग 15,000 यात्री जहां-तहां फंस गए थे। उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में पूरे पंद्रह दिन लग गए थे। पैदल मार्ग लगभग 29 जगह क्षतिग्रस्त हुआ था। इसके बाद तो पूरे यात्राकाल में पैदल मार्ग खुलता और बंद होता रहा। इस साल जून में ही मार्ग पर भारी पत्थर गिरने से पैदल यात्रा रोकनी पड़ी। मानसून से पहले भी पूरे देश में तेज बरसात होने लगी है। उत्तराखंड भी इसका अपवाद नहीं है। पूरी आशंका है कि भूस्खलन व मार्ग पर मलबा गिरना जारी रहेगा। इसलिए वैकल्पिक पैदल मार्गों की रणनीति अपनाने का समय आ गया है।

बार-बार यह जरूरत महसूस हो रही है कि भीड़भाड़ व दुर्घटनाओं से बचने के लिए केदारनाथ पुरी को वैकल्पिक मार्गों से जोड़ने की जरूरत है।

इस बार हेलीकॉप्टर दुर्घटना भी 15 जून को हुई है, जिसमें कुल सात लोगों ने जान गंवाई है। वैसे भी बरसात में हेलीकॉप्टर सेवा बाधित होती है। ऐसे में, वैकल्पिक पैदल मार्गों को चुस्त-दुरुस्त रखना आवश्यक हो गया है। बीते वर्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मार्ग की क्षतियों के आकलन व उस पर रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के पूर्व प्रधानाचार्य (सेवा निवृत्त) कर्नल अजय कोठियाल को दी थी। आकलन में यह भी पता चला है कि गिरते झरनों से होने वाले कटाव से भी पैदल मार्ग की चौड़ाई जगह-जगह कम हुई है। अब साल 2013 में ध्वस्त हुए व बंद किए गए पैदल मार्ग को चालू कर वहां से भी यात्रा चलाई जाएगी। वर्तमान पैदल मार्ग को भी पूरी तरह से ठीक किया जाएगा। 16-17 जून 2013 की आपदा में पारंपरिक 14 किलोमीटर का गौरीकुंड- केदारनाथ पैदल मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। रामबाड़ा का तो नामो-निशान ही नहीं बचा। वन विभाग से मिली भूमि उपयोग की अनुमति के बाद 2013 में क्षतिग्रस्त हुए मार्ग को ठीक करने की राह खुली।

कर्नल कोठियाल के ही नेतृत्व में उनके 12 सदस्यीय दल ने जून 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद मंदाकिनी घाटी में ट्रैकिंग कर तीन वैकल्पिक मार्ग बताए थे। एक माह के भीतर ही उत्तराखंड सरकार को चौमासी-खाम-रेका केदारनाथ मार्ग सुझाया था। इसमें दूरी 34 किलोमीटर है और चलने में तीन दिन लगते हैं। वैकल्पिक मार्गों को अगर दुरुस्त कर दिया जाए, तब मंदाकिनी के दोनों छोरों से चलने पर केदारपुरी पहुंचने के लिए दो वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो जाएंगे। जुलाई 2024 की आपदा के बाद केवल एक ही खुलते और बंद होते मार्ग की वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित रखना मुश्किल हो जा रहा है। पहाड़ों में अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अधिक मार्ग तो होने ही चाहिए, क्योंकि समय के साथ श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती ही जाएगी।

बीते सीजन में लगभग 16 लाख लोग पैदल मार्ग से केदारनाथ पहुंचे थे। इस संख्या में अगर स्थानीय लोगों, घोड़े-खच्चर, पालकी लाने-ले जाने वालों की संख्या के साथ पूरे मार्ग पर आने-जाने वाले लोगों को जोड़ लें, तो सोचकर ही मुश्किल का एहसास होता है। इतनी भारी संख्या में लोग एक ही पैदल मार्ग से यात्रा करेंगे, तो हादसों की आशंका रहेगी। पहाड़ों को बेतहाशा भीड़ के लिए तैयार रहना होगा, इसके लिए दो से ज्यादा पैदल मार्गों को दुरुस्त रखना होगा। वैकल्पिक मार्गों पर संचार सुविधा भी पुख्ता रखने की जरूरत है। पहाड़ों में मोबाइल फोन संपर्क टूटने पर परिजन बहुत चिंतित हो जाते हैं और राहत कार्यों में भी खूब परेशानी आती है। अफवाहों को भी बल मिलता है। मतलब, पहाड़ों में पैदल यात्रा और संचार का क्रम सुनिश्चित रहना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

दया कमजोरी नहीं

हमारी प्रगति के ऐतिहासिक चक्र के दौरान सार्वभौम शांति और सद्भाव का धार्मिक सिद्धांत आत्मसात करने में मानव जीवन एक क्षण के लिए भी कभी सफल नहीं रहा, जबकि बिना सार्वभौम और संपूर्ण पारस्परिक सद्भाव के वास्तविक शांति हो नहीं सकती। अभी भी संघर्षशील हितों के बीच निबाह लेने की एक व्यवस्था की संभावना के आगे हमने कोई वास्तविक प्रगति नहीं की है, जिससे संघर्ष के निकृष्टतम स्वरूप की पुनरावृत्ति को कम किया जा सके।

इस सिद्धि के लिए जो प्रणाली, जो रास्ता मानवता को स्वयं अपने स्वभाव से बाध्य होकर अपनाना पड़ा है, वह है भयानक परस्पर कत्लेआम, जो इतिहास में बेमिसाल है; सार्वभौम शांति को स्थापित करने के लिए आधुनिक मानव ने जो रास्ता और विजयी साधन खोज निकाला है, वह है कड़वाहट और घृणा से भरा सार्वभौम युद्ध !... ऐसा दिन आएगा और निश्चित रूप से आना चाहिए, जब मानवता सार्वभौम शांति के आधिपत्य के लिए आध्यात्मिक, नैतिक व सामाजिक रूप से तैयार होगी; तब तक एक लड़ाकू के रूप में मनुष्य के स्वभाव और कर्म को किसी भी व्यावहारिक दर्शन और धर्म को स्वीकार व समायोजित करना होगा।

गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि शत्रु से लड़ने की अपनी अनिच्छा द्वारा अर्जुन कायरतापूर्ण कमजोरी में च्युत हो गया, क्योंकि वह दया से आक्रांत हो गया था- *कृपयाविष्टम्।* क्या तब यह दैवी कमजोरी नहीं है ? क्या दया दैवी भावना नहीं है, जिसे कृष्ण की कड़ी भर्त्सना के साथ इस प्रकार हतोत्साहित नहीं करना चाहिए था ? या क्या हम युद्ध और वीरत्वपूर्ण कर्म के धार्मिक सिद्धांत के सम्मुख हैं ? नीत्से का सिद्धांत, यहूदियों का सिद्धांत दया को एक कमजोरी मानता है और नॉर्दे के नायक जैसा सोचता है, जिसने ईश्वर को इसलिए धन्यवाद दिया कि उसने उसे एक कठोर हृदय दिया ? किंतु *गीता* की शिक्षा एक भारतीय धार्मिक सिद्धांत से निकली है और भारतीय मस्तिष्क के लिए दया सदैव ही दैवी प्रकृति के महत्तम तत्वों में से एक रही है।...

आर्य योद्धा में वही दया भाव है, जो उसके शौर्य की आत्मा है। वह चोट खाए हुए सरकंडे को तोड़ेगा नहीं, बल्कि कमजोर, पीड़ित और गिरे हुए की रक्षा करेगा। पर यह भी दैवी दया ही है, जो बलवान अत्याचारी और आश्वस्त उत्पीड़क को मार गिराती है, क्रोध और घृणा से नहीं, बल्कि जैसा प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता ने स्पष्ट रूप से देखा है वैसे। अपनी शक्ति द्वारा गलती करने वाले और अपने पापों के लिए वध किए जाने वाले बलवान दैत्य के लिए भी उतनी ही दया और प्रेम के साथ, जितनी कष्ट उठाने वालों और पीड़ितों के लिए, जिन्हें उसकी हिंसा और अन्याय से बचाना है।

सार्वभौम शांति को स्थापित करने के लिए आधुनिक मानव ने जो रास्ता और विजयी साधन खोज निकाला है, वह है कड़वाहट और घृणा से भरा सार्वभौम युद्ध !

श्री अरविंद

जगदीप धनखड़ | उप-राष्ट्रपति, भारत

एक समय था, जब शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा समाज को कुछ देने के साधन थे। इन्हें कभी मुनाफा कमाने वाला कार्य नहीं माना जाता था।... हमें शिक्षा के व्यवसायीकरण से प्रेरित नहीं होना चाहिए !

अनुलोम-विलोम
भारत-कनाडा संबंध

प्रधानमंत्री की कनाडा यात्रा सार्थक रही

भारत और कनाडा के रिश्तों में बीते कुछ वर्षों में जो कड़वाहट आई थी, उसका मुख्य कारण खालिस्तानी अलगाववादियों को लेकर कनाडा की उदासीनता रही। पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में वहां खालिस्तानी गतिविधियों को नजरअंदाज किया गया, जिससे भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। इसी कारण दोनों देशों के संबंधों में दरार आ गई और राजनयिक स्तर पर संवाद सीमित होता गया।

हालांकि, अब कनाडा में नई सरकार और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के सत्ता में आने के बाद रिश्तों में नया मोड़ आया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कार्नी की मुलाकात ने इस दिशा में सकारात्मक संकेत दिए हैं। दोनों देश एक बार फिर राजनयिक रिश्तों को पूरी तरह बहाल करने पर सहमत हुए हैं, जो एक स्वागत के योग्य कदम है। भारत को जो सबसे ठोस लाभ मिले, उसमें निज्जर के मुद्दे पर संवाद की पुनः शुरुआत एक सकारात्मक और सार्थक बात रही।

मगर इस नई शुरुआत का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब कनाडा सरकार भारत की उन सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लेगी, जो खालिस्तानी तत्वों से जुड़ी हैं। लोकतांत्रिक अधिकार की आड़ में हिंसा और अलगाव की मानसिकता को बढ़ावा देना न सिर्फ भारत के लिए खतरा है, बल्कि कनाडा की सामाजिक एकता और अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। अब कनाडा अपनी नीतियों में संतुलन बनाए और यह सुनिश्चित करे कि उसकी भूमि का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए न हो। अगर दोनों देश आपसी विश्वास और सम्मान के आधार पर आगे बढ़ते हैं, तो द्विपक्षीय सहयोग के नए अवसर खुलेंगे।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

जी-7 शिखर सम्मेलन में भारत और कनाडा के प्रधानमंत्रियों की वार्ता काफी सकारात्मक संदेश देती नजर आ रही है। मोदी-कार्नी वार्ता संबंधों को बहाल करने और स्थिरता देने के लिए रचनात्मक कदम उठाने की सहमति है। यहां मोदी ने संबंधों को फिर से बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ भी हो अगर संबंधों में सुधार के संकेत हैं, तो दोनों देशों में हर स्तर पर प्रगति के द्वार खुलेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों, संप्रभुता व अखंडता के सिद्धांतों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता के आधार पर संबंधों के महत्व की पुष्टि की है। इसमें कोई दो मत नहीं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की वार्ता कनाडा के साथ सफलता से परिपूर्ण होकर दोनों देशों की औद्योगिक, आर्थिक और राजनयिक नीतियों को मजबूत करेगी।

योगेश जोशी, टिप्पणीकार

भारत को अभी करना होगा आत्ममंथन

अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक मंच पर जब विश्व की सबसे सशक्त आर्थिक शक्तियां एकत्र होती हैं, तो यह अपेक्षित होता है कि ये वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक बुद्धिमत्ता, नीतिगत एकता और कूटनीतिक दृढ़ता प्रदर्शित करें। किंतु कनाडा के कानानास्किस में हाल ही में संपन्न हुआ जी-7 शिखर सम्मेलन इन अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा नहीं उतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मेलन में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, किंतु भारत को जिन अपेक्षाओं के साथ यह यात्रा करनी पड़ी थी, वे अधूरी ही रह गईं। सम्मेलन में न तो आतंकवाद विरोधी रणनीति पर कोई ठोस चर्चा हुई, न ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर कोई साझा दृष्टिकोण सामने आया। भारत को जो सबसे ठोस लाभ मिला, वह केवल कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से हुई द्विपक्षीय भेंट थी। परंतु इसमें भी कनाडा की नीति में कोई बुनियादी बदलाव नहीं हुआ। खालिस्तानी उग्रवाद पर कनाडा की चुप्पी अभी भी भारत के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। जी-7 का साझा वक्तव्य टीएनआर पर केंद्रित रहा, जिसमें भारत के साथ-साथ चीन, रूस और ईरान को परोक्ष रूप से निशाना बनाया गया।

कनाडा द्वारा भारत पर 'विदेशों में कार्रवाई' के आरोप इस दस्तावेज के माध्यम से दोहराए गए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत की सहभागिता का उद्देश्य ही संदिग्ध बना दिया गया। भारत यदि इस मंच पर अपनी बात मजबूती से नहीं रख सकता है और यदि उसकी चिंताओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, तो फिर ऐसे मंचों पर बार-बार हमारी उपस्थिति कितनी सार्थक है, यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है।

यह भी विचारणीय है कि जब प्रधानमंत्री को 11,000 किलोमीटर की यात्रा कर एक ऐसे सम्मेलन में भाग लेने जाना पड़े, जहां न तो ठोस संवाद हो, न भारत के मुद्दों को गंभीरता से लिया जाए और जहां अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश केवल अपने भू-राजनीतिक हितों की पूर्ति में लगे हों, तो उस मंच की उपयोगिता पर पुनर्विचार आवश्यक हो जाता है। आज भारत विश्वगुरु बनने की आकांक्षा रखता है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और अनेक वैश्विक मंचों पर अपनी सशक्त भूमिका निभा रहा है। ऐसे में, उसे केवल दिखावे की कूटनीति में उलझने के बजाय सार्थक सहभागिता की ओर ध्यान देना चाहिए। भारत को यह स्पष्ट करना होगा कि वह मात्र 'विशेष अतिथि' बनकर नहीं, बल्कि एक 'समान हैसियत' वाले सहभागी के रूप में ही किसी वैश्विक मंच का हिस्सा बनना चाहता है, अन्यथा यह केवल 'उपस्थिति' बनकर रह जाएगी।

नृपेंद्र अभिषेक नृप, टिप्पणीकार